विशेषांक

आत्मनिर्भर भारत की ओर...

कमल संदेश

मोदी सरकार 2.0 का एक वर्ष

जन-जन को यह पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश आज एकजुट उठ खड़ा हुआ है और अब एक गौरवशाली भविष्य भारत की बाट जोह रहा है।

– श्री जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

आत्मनिर्भर भारत की ओर...

मोदी सरकार 2.0 का एक वर्ष

प्रस्तावना

श्री जगत प्रकाश नड्डा

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

30 मई, 2020

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003

प्रकाशकीय

देश की अनेक चिरलंबित समस्याओं का अत्यधिक कुशलता से समाधान करने के लिए मोदी सरकार को आने वाले समय में जाना जाएगा। ये इस प्रकार की समस्यायें थीं जिनका समाधान असंभव माना जाता था तथा राष्ट्र की प्रगति में बाधा बने हुए थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति, अटूट प्रतिबद्धता, पूर्ण समर्पण, दूरदर्शिता तथा हृदय में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की आवश्यकता थी।

अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याणार्थ मोदी सरकार ने अनेक अभिनव कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ ही अनेक ऐसे राजनैतिक निर्णय लिये जिससे संपूर्ण देश में आशा एवं विश्वास के वातावरण का निर्माण हुआ है। राजनैतिक प्रतिबद्धता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का एक अद्भुत उदाहरण, जिस प्रकार धारा 370 का संशोधन कर क्रियान्वित किया, उसमें देखा जा सकता है। यह माना जाता था कि कश्मीर समस्या का समाधान असंभव है तथा कश्मीर की जनता को शेष भारत की मुख्यधारा में लाना दुष्कर है। परंतु इस निर्णय से यह प्रमाणित हो गया कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसी प्रकार से 'तीन तलाक' के विषय पर तुष्टिकरण की राजनीति के अनैतिक दबाव से कांग्रेस की सरकारें निर्णय को टालती रहीं, परंतु मोदी सरकार के द्वारा न्यायालय में सुविचारित एवं स्पष्ट मत रखने के बाद मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला एवं करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस अमानवीय कुप्रथा से आजाद हो गईं। यहां तक कि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे न्यायिक प्रक्रिया पर भी निरंतर अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास हुए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्पष्ट एवं सर्वसम्मत निर्णय देकर समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण निर्माण किया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से इस विधेयक का विरोध करने का प्रयास किया है, उससे इन दलों की 'वोट बैंक' एवं तुष्टीकरण की राजनीति पुनः बेनकाब हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इस दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के लिए सारा देश अभिनंदन कर रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश बड़ी मजबूती के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है जिसके लिए पूरे विश्व में अनेक अन्तरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत की प्रशंसा की जा रही है। 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए देश का आह्वान किया है। आज जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के पूर्व और पश्चात् की दुनिया की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, व्यवस्था, जनसंख्या और मांग पर जोर देकर भविष्य की दिशा दिखाई है। अर्थव्यवस्था में एक लंबी छलांग, भारत की पहचान बनाने वाली आधारभूत संरचना, 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा के रूप में जनसंख्या तथा मांग एवं आपूर्ति की क्षमता के उपयोग से भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की जीडीपी की 10% आर्थिक पैकेज के साथ सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। 'लोकल' उत्पादों के लिए 'वोकल' होने का मंत्र निश्चित ही भारतीय उत्पादों को 'ग्लोबल' स्तर पर ले जाएगा।

मोदी सरकार-2.0 के प्रथम वर्ष का कार्यकाल अद्भुत उपलब्धियों से भरा हुआ है। हर दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसका देश पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 'कमल संदेश विशेषांक-आत्मनिर्भर भारत की ओर' इन्हीं सब उपलब्धियों को अपने सुधी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास है। आशा है हमारे पाठक इसका लाभ अवश्य उठायेंगे।

— डॉ. शिव शक्ति बक्सी

कमल संदेश

संपादकः प्रभात झा, **कार्यकारी संपादकः** डॉ. शिव शक्ति बक्सी
सह संपादकः संजीव कुमार सिन्हा, राम नयन सिंह
कला संपादकः विकास सैनी, भोला राय
डिजीटल मीडियाः राजीव कुमार, विपुल शर्मा
सदस्यता एवं वितरणः सतीश कुमार

दूरभाष : 011-23381428 **ई-मेल :** mail.kamalsandesh@gmail.com

https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ @kamalsandeshbjp www.kamalsandesh.org

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना - श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष 06
2. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पत्र 08
3. एक ही लक्ष्य 'जनसेवा' 13
4. मोदी सरकार - 2.0 के प्रथम वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां 15
5. अनेक फैसले - अनेक बदलाव 16
6. कोविड-19 संकट और प्रबंधन 22
7. आत्मनिर्भर भारत अभियान 26
8. मोदी सरकारः 2014 - 2019 28
9. विश्व भर में हो रही भारत की प्रशंसा 36
10. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा 40
11. ढांचागत परिवर्तन के नवयुग की शुरुआत / नितिन गडकरी 42
12. सामाजिक न्याय और मोदी सरकार 2.0 / डॉ. थावरचंद गहलोत 43
13. जनजातीय कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार / अर्जुन मुंडा 45
14. भारत के भविष्य की आधारशिला / प्रकाश जावडेकर 46
15. साहसिक नेतृत्व का 'ऊर्जावान' कार्यकाल / धर्मेन्द्र प्रधान 48
16. समावेशी विकास–सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण मोदी सरकार की नीति / मुख्तार अब्बास नकवी 50
17. वैचारिक उत्कर्ष का वर्ष / प्रभात झा 53
18. अहम है भारतीयों का जीवन और सुधार.../ विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे 55
19. मोदी सरकार की दमदार पहल / श्याम जाजू 56
20. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं / दुष्यन्त कुमार गौतम 57
21. अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प / बैजयंत 'जय' पंडा 58
22. आत्मनिर्भरता : 21वीं सदी के भारत की राह / मुरलीधर राव 60
23. मोदी सरकार की नीतियों में गरीब कल्याण पर जोर / भूपेंद्र यादव 62
24. मोदी सरकार के पैकेज का गणित और प्रभाव / स्वामिनाथन गुरुमूर्ति 64
25. 'लोकल के लिए वोकल' का संकल्प / अनुराग ठाकुर 66
26. एमएसएमईः भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन / प्रताप चन्द्र षडंगी 68
27. नारीशक्ति के दम पर बढ़ता नया भारत / विजया रहाटकर 70
28. आत्मनिर्भर भारत : चुनौतियां एवं अवसर / गोपाल कृष्ण अग्रवाल 72
29. मोदी 2.0- विदेश नीति की पहल / डॉ. विजय चौथाईवाले 74
30. युवा हो रहे सशक्त / संजीव कुमार सिन्हा 76
31. स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम../ राम प्रसाद त्रिपाठी 77
32. मोदी सरकार ग्राम स्वराज की ओर / विकास आनंद 78

प्रस्तावना

केन्द्र की मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो चुका है। इस एक वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। अब तक जिन समस्याओं से पूरे देश का मन-मस्तिष्क आहत रहता था, जिन समस्याओं का समाधान संभव प्रतीत नहीं होता था, उन समस्याओं को इस तरह से हल कर दिया गया जैसे वे कभी कोई 'समस्या' थीं ही नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि धारा 370 हो या नागरिकता संशोधन अधिनियम, तीन-तलाक पर कानून हो या फिर प्रभु श्रीराम के मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करना हो, ब्रू-रियांग समझौता हो या बोडो समझौता; इन सभी विषयों पर राष्ट्र ने विजय प्राप्त की है।

भाजपानीत राजग को लोकसभा चुनाव 2019 में मिला जबरदस्त जनादेश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं अथक परिश्रम का परिणाम है। इसी कठिन परिश्रम एवं तप के बल पर कांग्रेसनीत यूपीए के शासनकाल के भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, कुशासन, आर्थिक गिरावट, कमरतोड़ महंगाई एवं निरंतर बढ़ते बजट घाटे से देश को पिछले पांच वर्षों में उबारने में श्री नरेन्द्र मोदी सफल हुए हैं। कांग्रेसनीत यूपीए के कुशासन के बीच देश को श्री नरेन्द्र मोदी के रूप में एक आशा की किरण दिखाई दी थी, जिसके परिणामस्वरूप कई दशकों के बाद जनता ने भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया था। इस जनादेश के पीछे पूरे देश की आशाएं, अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं जुड़ी हुई थीं। पांच वर्षों के सकारात्मक कार्य, निरंतरता एवं परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ-साथ अभिनव योजनाएं एवं परिणामकारक नीतियों, शासन में नई कार्य-संस्कृति, संस्थाओं को पुनर्जीवित करने वाले कार्य, समयानुकूल निर्णय एवं कभी-कभी कठोर निर्णय लेने की क्षमता के फलस्वरूप आज एक ऐसी सरकार केन्द्र में है जिसकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता एवं कार्यक्षमता से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि आज देश एक भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देख रहा है, जो देश के दूर-दराज इलाकों में भी गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा-सीधा पहुंचाने में सक्षम है। यह पहली बार हुआ है कि समाज की कतार के अंत में खड़ा व्यक्ति सरकारी योजनाओं का सीधा लाभार्थी बना है और पक्का आवास, बिजली कनेक्शन, गैस सिलिंडर, शौचालय, बैंक खाता और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ अपने परिवार को सामाजिक सुरक्षा एवं दस करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हो पाया है।

एक ओर जब देश की विकास यात्रा अपनी तेज गति से पूरे विश्व को चमत्कृत कर रही है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ा है और अनेक अभिनव योजनाओं से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, एक चुनौती के रूप में कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित कर दिया है। आज जबकि अनेक देशों में 'लॉकडाउन' हुआ

है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के विवरण सामने आने से देश में सुरक्षित भविष्य के प्रति आशा और विश्वास का एक वातावरण बना है। यह पैकेज स्वयं में इतना विस्तृत एवं सर्वसमावेशी है कि हर वर्ग की आवश्यकताओं का इसमें ध्यान रखा गया है और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की योजना इसमें समाहित है।

किसान, मजदूर, महिला जन-धन खाताधारक, वरिष्ठ नागरिकों आदि को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से नकद रुपया देकर समाज के इन कमजोर वर्गों की तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास हुआ है, जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। दाल, चना सहित निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति कर इस बंदी के दौर में गरीब से गरीब व्यक्ति की भोजन की समस्या हल की गयी है। अपने गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखते हुए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है जिससे उन्हें अपने स्थान पर ही रोजगार मिलने में सहायता होगी। ग्रामीण भारत पर केंद्रित कृषि एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाओं, कृषि ऋण की उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार एवं अन्य कदमों से आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेगी। प्रवासी श्रमिकों को 'श्रमिक स्पेशल ट्रेनों' से भारी राहत मिली है। विदेशों में भी फंसे भारतीयों को वापस लाया गया है। 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए उनके आह्वान का पूरे देश में व्यापक समर्थन मिला है।

अब तक भारत ने कोविड-19 महामारी से बहुत ही धैर्य एवं दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं मजबूत नेतृत्व में किए गए प्रयासों को विश्व में पूरी तरह से सराहा गया है। अब तक यह स्पष्ट है कि इस महामारी के विरुद्ध पूरे विश्व को एक लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए अब भारत पूरी तरह से तैयार है। देश ने 'लॉकडाउन' के समय का पर्याप्त उपयोग करते हुए अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में कई ढांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है और भविष्य में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों, गांव, शहर एवं नगर के स्थानीय निकायों के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन एवं व्यक्तिगत स्तर पर अनगिनत लोग बड़े स्तर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए भाजपा कार्यकर्ता देश के कोने-कोने में राहत कार्य चला रहे हैं। 907 संगठनात्मक जिलों के 13,796 मंडलों में 8.25 लाख भाजपा कार्यकर्ता निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। अब तक 4.90 करोड़ से अधिक राशन किट, 19.28 करोड़ फूड पैकेट तथा 5.05 करोड फेस मास्क लोगों के बीच बांटा जा चुका है। साथ ही 8.30 लाख कार्यकर्ता वरिष्ठ/बीमार व्यक्तियों की देख-रेख करने को नियुक्त हुए हैं। कार्यकर्ताओं के प्रयासों से 53.90 लाख से अधिक लोगों ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया है। 12.87 लाख बूथों में (#Thank you corona warrior) हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है।

2019 के जबरदस्त जनादेश न केवल मोदी सरकार पर जन-जन के भारी विश्वास का परिणाम है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की बढ़ती जनाकांक्षाओं के दायित्वों को निर्वहन करने का भी संदेश है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो प्राचीनकाल से ही भिन्न-भिन्न परंपराओं, मान्यताओं एवं आस्थाओं के बीच विविधतापूर्ण संस्कृति के लिये पूरे विश्व में विख्यात है। जन-जन को यह पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश आज एकजुट उठ खड़ा हुआ है और अब एक गौरवशाली भविष्य भारत की बाट जोह रहा है। देश कोविड-19 महामारी की चुनौतियों को एक अवसर में बदल रहा है। पूरा राष्ट्र अब 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में जुट गया है।

(जगत प्रकाश नड्डा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र

मेरे प्रिय स्नेहीजन,

आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए, अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतन्त्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का।

यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में, मैं इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ।

बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है।

वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने, देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन पाँच वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन पाँच वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है।

उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन-बान-शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर, गरीब की गरिमा भी बढ़ाई।

उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स-GST, किसानों की MSP की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया।

वह कार्यकाल देश की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा।

वर्ष 2019 में आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस एक साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है।

आज जन-जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति, राष्ट्रशक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत एक वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए, और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए।

भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है।

प्रिय स्नेहीजन,

बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है।

राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम - राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण हैं।

एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं-युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है।

अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 72 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है।

देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है।

हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है।

देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब, किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों, सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हज़ार रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है।

मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकॉनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल में ही स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर दोगुना यानि 20 लाख कर दिया गया है।

आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान भी शुरू किया गया है।

सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बनें, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिटफंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हों, ये सब तेज़ी से बन पाए हैं।

सरकार की नीतियों और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच की खाई कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या, शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10 प्रतिशत

ज्यादा हो गई है।

देशहित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि एक साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन चौबीसों घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं।

प्रिय स्नेहीजन,

देशवासियों की आशाओं-आकाँक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे, कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया।

एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है।

कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा, तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा।

लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है।

ताली-थाली बजाने और दीया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है।

निश्चित तौर पर, इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई-बहन, छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी-ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई-बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा, जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। यह एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है।

अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने स्थितियों का मुकाबला किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वह भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

प्रिय स्नेहीजन,

इन परिस्थितियों में, आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उबरेंगी? लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय, अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं।

आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है - आत्मनिर्भर भारत।

अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।

यह अभियान, हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्ट अप्स से जुड़े नौजवान, सभी के लिए, नए अवसरों का दौर लेकर आएगा।

भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा।

प्रिय स्नेहीजन,

बीते छह वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही, देश पिछले एक साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन-रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। और इसलिए, मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है।

मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है।

वैश्विक महामारी के कारण, यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है।

हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती।

हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी।

हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे।

हमारे यहां कहा गया है- 'कृतम् मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहितः'॥

यानि, हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है।

देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं।

आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए !!!

जागृत रहिए, जागरूक रखिए !!!

आपका प्रधानसेवक

नरेंद्र मोदी

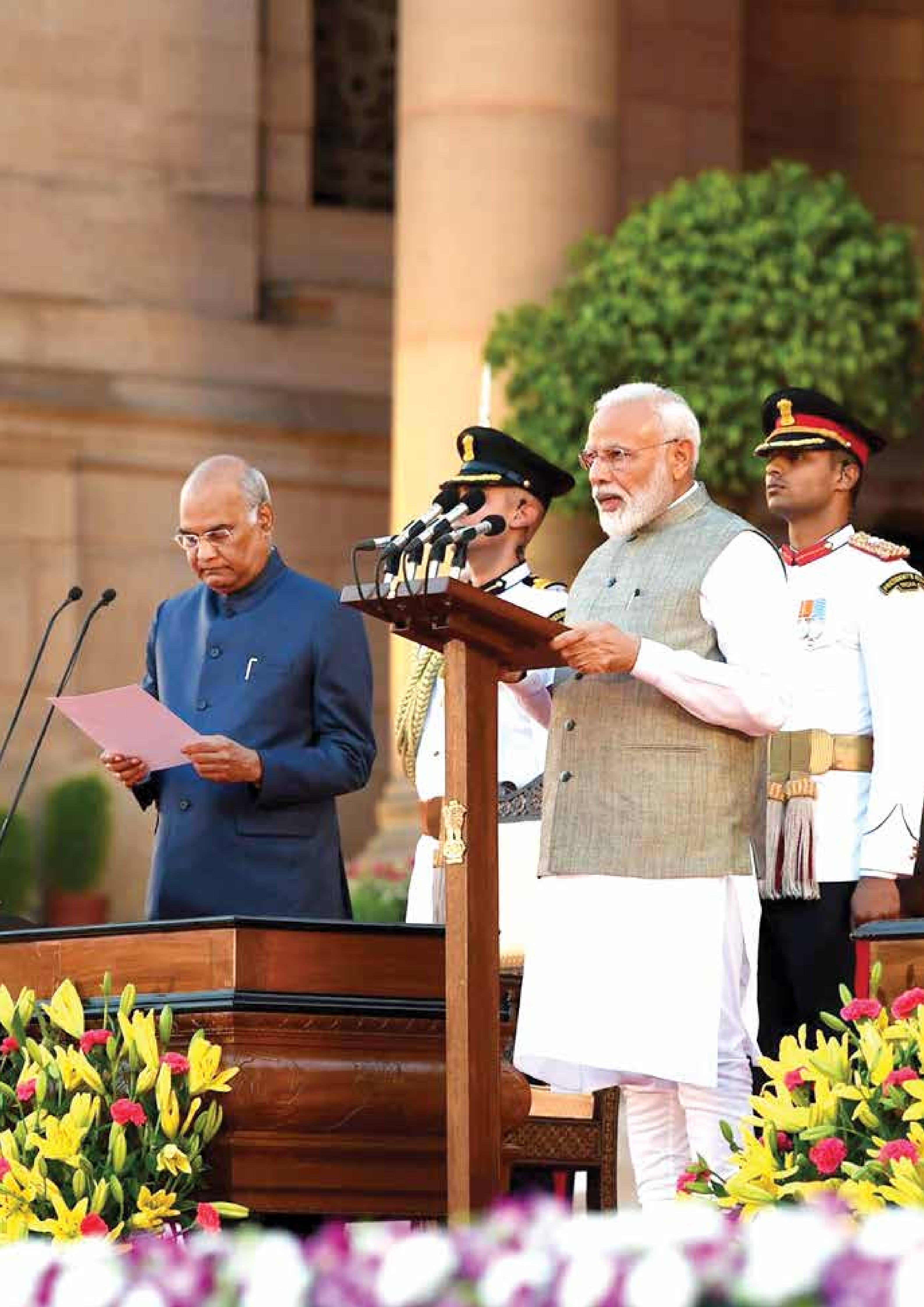

एक ही लक्ष्य 'जनसेवा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं 57 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जनादेश प्राप्त करते हुए केंद्र में सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने 'सबका साथ—सबका विकास' के मंत्र को चरितार्थ करते हुए हर नागरिक के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए। चाहे गरीब कल्याण का मुद्दा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या फिर विदेशों में भारत की साख का मामला; मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने फिर से भाजपा को स्थायी और मजबूत सरकार बनाने का जनादेश दिया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने बहुमत प्राप्त करते हुए जहां 282 सीटें प्राप्त की थी, वहीं सतरहवीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई और भाजपा ने अपने दम पर 303 सीटें जीती। राजग को 353 सीटें मिलीं। श्री नरेन्द्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 25 केन्द्रीय मंत्री, नौ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 24 ने राज्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

मजबूत नेतृत्व

ऐतिहासिक निर्णय
मोदी सरकार 2.0 के प्रथम वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

अनुच्छेद 370 हटाः दो नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने : जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का कलंक हटा और राज्य में तीव्र विकास के रास्ते खुले। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को मंजूरी दी। दो नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएं। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण से जनता के लिए अनगिनत सम्भावनाओं के द्वार खुल गए हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान है। यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा।

तीन तलाक : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता ही है कि मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त हो खुली हवा में सांस ले रही हैं। इस संबंध में मोदी सरकार ने तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़े कानून 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019' बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया।

तीन तलाक विधेयक पारित

बोडो समझौता : ऐतिहासिक बोडो समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला रहा। इस समझौते के परिणामस्वरूप 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्यों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया। समझौते के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी।

ब्रू-रियांग समझौता : त्रिपुरा में ब्रू-रियांग समुदाय को बसाने पर ऐतिहासिक निर्णय में 16 जनवरी को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम सरकार और ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही इस बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान होगा तथा करीब 34 हजार व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा।

अनेक फैसले-अनेक बदलाव

कैबिनेट की प्रथम बैठक में लिए गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

- 31 मई 2019 को हुए कैबिनेट की बैठक में देश भर के छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना का ऐतिहासिक निर्णय
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 14.5 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित, संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने का निर्णय
- **नई पेंशन योजना से 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित :** इस योजना के तहत सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व-रोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है।

- **करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पित :** करतारपुर गलियारे की चैक पोस्ट के शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हुई। डेरा बाबा नानक के निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जीरो-प्वॉइंट पर करतारपुर साहेब गलियारा तैयार करने के लिए भारत ने 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौता किया था।
- **'आयुष्मान भारत' के तहत एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थी :** भारत ने 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर इस दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
- **अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे :** अटल पेंशन योजना ने 2.23 करोड़ लोगों का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी।
- **'ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट': 142वें पायदान से छलांग लगाकर 63वें पायदान पर :** भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार के निरंतर ठोस उपायों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर कर वर्ष 2014 के निचले 142वें पायदान से छलांग लगाकर वर्ष 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है।
- **'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' के विस्तार को स्वीकृति :**

राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त : उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और केन्द्र को निर्देश दिया कि नयी मस्जिद के निर्माण के लिये सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी।

- सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की, इससे 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख नियोक्ता लाभान्वित होंगे।
- **कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करे पाकिस्तान:** अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने 17 जुलाई को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक श्री कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए। यह भारत की बड़ी जीत है।
- **मंत्रिमंडल ने 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी :** 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक (एक वर्ष के लिए) 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना।
- **संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंजूरी :** संसद ने 25 जुलाई को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
- **सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल का सफल परीक्षण :** रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 4 अगस्त को चंदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से सीधा हवाई लक्ष्य के विरुद्ध अत्याधुनिक त्वरित प्रतिक्रिया सतह-से-वायु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी :** राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 10 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 किए जाने संबंधी एक विधेयक पर दस्तखत कर दिया।
- **वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर :** अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ायेगा। 'अपाचे एएच-64ई' दुनिया का सबसे उन्नत बहु-भूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
- **10 बैंकों के विलय से बने चार बड़े बैंक :** देश में विश्वस्तरीय बैंक बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुये सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की 30 अगस्त को घोषणा की गई। इस पहल से न केवल आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, बल्कि देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी।
- **गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा 6,286 करोड़ रुपये की सब्सिडी:** 28 अगस्त को गन्ना सीजन 2019-20 के दौरान चीनी मिलों के लिए 10,448 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्यात सब्सिडी प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
- **प्रधानमंत्री ने किया 'फिट इंडिया' मुहिम का शुभारंभ :** वीरता और फिटनेस को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को 'फिट इंडिया आंदोलन' का शुभारंभ किया।
- **घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर घटकर 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% हुआ, कर की प्रभावी दरें करीब 10 प्रतिशत नीचे :** आर्थिक वृद्धि तेज करने तथा निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये 20 सितंबर को कारपोरेट कर में भारी कटौती की घोषणा की गई। सरकार के इस ताजा प्रोत्साहन

से कारपोरेट कर की प्रभावी दरें करीब 10 प्रतिशत नीचे आ गयी हैं।

- **प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया भारत रत्न :** पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक श्री भूपेन हजारिका को 8 अगस्त को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया।
- **व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत :** यह पेंशन योजना उन व्यापारियों (दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों) के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का शुभारंभ :** पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की व्यय राशि 12652 करोड़ रुपये है। बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देशभर में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक करोड़ लाभार्थियों तक पहुंची:** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की अग्रणी योजना-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच गई है। योजना के अन्तर्गत कुल 4,000 करोड़ से अधिक राशि लाभार्थियों को वितरित की गई है।
- **खुले में शौच से मुक्त हुआ ग्रामीण भारत :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि केवल शौचालयों का निर्माण ही काफी नहीं है, बल्कि इनके इस्तेमाल को आदत का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के अभियान के चलते देश की उत्पादकता भी बढ़ी है।
- **साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना है।
- **अब शहीदों के परिजन को चार गुना आर्थिक मदद, 2 से 8 लाख रुपये हुई राशि :** युद्ध में जान गंवाने वालों के परिजन या दिव्यांग सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में चार गुना वृद्धि कर दी गई है। 5 अक्टूबर को मौजूदा 2 लाख रुपये की मदद राशि को बढ़ाकर 8 लाख करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह राशि सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (एबीसीडब्ल्यूएफ) के तहत दी जाएगी।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 90 लाख से अधिक :** 47वीं केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने 4,988 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भागीदार राज्यों के लिए 1.23 लाख मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत सरकार की ओर से 1,805 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।
- **दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ :** केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तीन अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

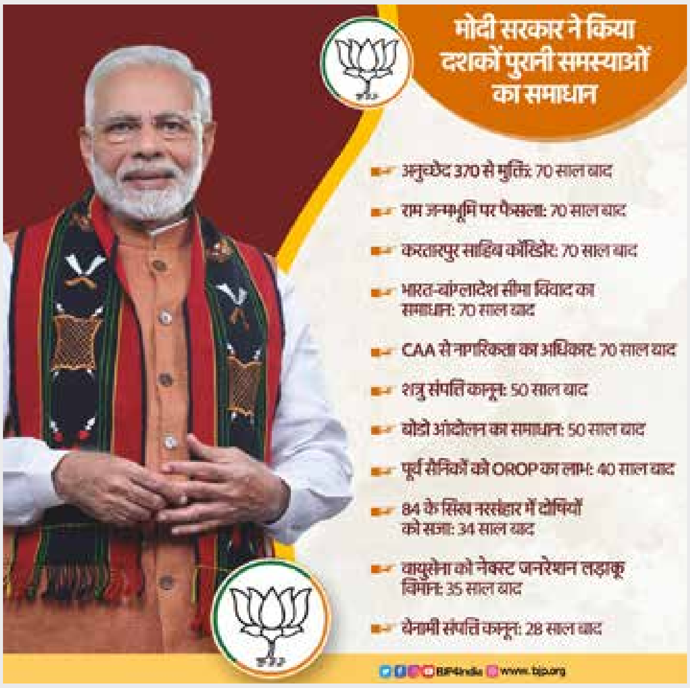

- **भारत ने फ्रांस से पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर को प्राप्त किया।** फ्रांस से खरीदे गये 36 राफेल लड़ाकू विमानों की शृंखला में प्रथम विमान सौंपे जाने के लिये आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को और मजबूती प्रदान करेगा। इस समारोह का आयोजन फ्रांस में राफेल विमान निर्माता दसाल्ट एविएशन के प्रतिष्ठान में किया गया।
- **रडार को मात देने वाला युद्धपोत 'आईएनएस नीलगिरि' का जलावतरण :** रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 28 सितंबर को रडार को मात देने वाला युद्धपोत 'आईएनएस नीलगिरि' का जलावतरण किया। श्री सिंह ने कहा कि सरकार भारत के समुद्री हितों के लिए किसी भी पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए नौसेना के आधुनिकीकरण और बेहतरीन प्लेटफार्मों, हथियारों और सेंसर से लैस करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
- **दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हक : 40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की 23 अक्टूबर को मंजूरी प्रदान करते हुये 1797 कालोनियों में रह रहे लाखों संपत्ति मालिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का रास्ता साफ कर दिया।
- **बीएसएनएल, एमटीएनएल का विलय : 68,751 करोड़ रुपये**

के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी। केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को 23 अक्टूबर को मंजूरी दी। इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल हैं।

- **पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से आए 5300 कश्मीरी परिवारों को मिले 5.5 लाख रुपये :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आ बसे 5300 परिवारों को दिवाली का तोहफा दिया।
- **4.58 लाख अधूरे फ्लैटों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मंजूरी, 1,600 रुकी परियोजनाओं को पूरा करने में मिलेगी मदद:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर को 4.58 लाख अधूरे फ्लैटों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी। 10 हजार करोड़ रुपए सरकार देगी और 15 हजार करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक एवं एलआईसी देंगे।
- **वित्तीय समावेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करने वाले शीर्ष देशों में भारत :** भारत वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष देशों में है। 31 अक्टूबर को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने गैर बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति दी है, अनुपातिक उपभोक्ता जांच पड़ताल और प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण का माहौल दिया है।
- **राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनारा:** भारत ने रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप को खारिज कर दिया। आज का भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करने वाला भारत है।
- **उड़ान/क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन :** गौरतलब है कि अब तक 'उड़ान' के तहत 230 मार्गों और 42 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है। उड़ान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 700 वायु मार्गों से जोड़ेगा, जो भारत के विमानन क्षेत्र में एक नए क्षेत्रीय संपर्क की नींव रखेंगे।

- **जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित, न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास:** इस विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का स्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर इसका संचालन करने वाले न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास किया गया।
- **युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास की सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने की मंजूरी :** युद्ध में घायल सैनिकों के लिए सरकारी आवास सुविधा को तीन माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया। सशस्त्र बलों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की थी।
- **भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने की मंजूरी देश में पहला कार्पोरेट बॉन्ड होगा भारत बॉन्ड ईटीएफ:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4 दिसंबर को भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बनाने और इसकी शुरुआत करने को मंजूरी दी।
- **संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव :** (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित। दिसंबर को दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित हो गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, प्रशासनिक व्यय कम करने, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के लिए यह विधेयक लाया गया।
- **साल्वो रूप में दो पिनाक मिसाइलों का सफल उड़ान परीक्षण :** पिनाक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की उड़ान परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा दो परीक्षण फायरिंग की गई। इस परीक्षण का मिशन उद्देश्य कम रेंज का परीक्षण करना, निकटता फ्यूज के साथ लाइव वॉरहेड कार्य प्रणाली का परीक्षण करना और साल्वो लॉन्च करना था।
- **प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति :** रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया गया। नवनियुक्त चीफ

ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत इसके प्रमुख बने। नए विभाग के पास तीनों सेनाओं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य होंगे।

- **'अटल भूजल योजना' की शुरुआत :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर को 'अटल भूजल योजना'(अटल जल) की शुरुआत की, जिससे सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा। उन्होंने इसके साथ ही लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण 'अटल टनल' करने की घोषणा की।
- **अब भारत के 125 करोड़ निवासियों के पास आधार :** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 27 दिसंबर को यह घोषणा की कि आधार परियोजना ने 125 करोड़ के अंक को पार करके नई उपलब्धि हासिल की है। इसका मतलब यह है कि भारत के 125 करोड़ से अधिक निवासियों के पास 12 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध है।
- **डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट :** प्रधानमंत्री ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की।
- **कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पेंशनधारकों का कल्याण:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन फंड की कमी को पूरा करने के लिए अंतिम किस्त के रूप में 501 करोड़ रुपये का चेक भी सौंपा।
- **'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के पांच वर्ष पूरे :** फरवरी 2020 को महत्वपूर्ण 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के पांच वर्ष पूरे हो गए। इस योजना के तहत वर्ष 2015-17 (चक्र-1) के दौरान 10.74 करोड़ और वर्ष 2017-19 (चक्र-2) के दौरान 11.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-दो को मंजूरी :** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी। इसमें खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा। 10,000 नए एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन हेतु 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन' को मंजूरी। 19 फरवरी को किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु 2019-2022 से 2023-24 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 नए एफपीओ के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। प्रत्येक एफपीओ के शुभारंभ वर्ष से पांच वर्षों तक के लिए सहायता जारी रखी जाएगी।
- **स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 81 प्रतिशत से अधिक महिलाएं खाताधारक :** वित्त मंत्रालय ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को बेहतर जीवन जीने और उद्यमी बनने के उनके सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।
- **ई-ग्राम स्वराज एप:** 'ई-ग्राम स्वराज' दरअसल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में मदद करता है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **स्वामित्व योजना:** 6 राज्यों में प्रायोगिक (पायलट) तौर पर शुरू की गई 'स्वामित्व योजना' ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गांवों में बसी हुई भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद करती है। यह योजना सुव्यवस्थित योजना बनाना एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता प्रदान करेगी। इससे संपत्ति (प्रॉपर्टी) के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। इस योजना के माध्यम से आवंटित मालिकाना प्रमाण पत्र (टाइटिल डीड) के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जाएगा।
- **स्टैंड-अप इंडिया योजना :** स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 17 फरवरी 2020 तक 81 प्रतिशत से अधिक खाताधारकों में से 73,155 खाते महिलाओं के लिए खोले गए। महिला खाताधारकों के लिए 16712.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। महिला खाताधारकों को 9106.13 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मृत्युदंड देने के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगेगी क्योंकि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):** इस योजना के शुरू होने बाद 31 जनवरी 2020 तक, 22.53 करोड़ से अधिक ऋणों की मंजूरी दे दी गई। इसमें से 15.75 करोड़ से अधिक ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, कुल ऋण उधारकर्ताओं में से 70% महिलाएं हैं।
- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) :** 19 फरवरी 2020 तक 38.33 करोड़ लाभार्थियों में से 20.33 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, जो 53% हैं।
- **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) :** यह योजना बैंक और डाकघरों के माध्यम से सदस्यता के लिए खुली है। 22 फरवरी 2020 तक, एपीवाई के अंतर्गत लगभग 2.15 करोड़ कुल ग्राहकों में से 93 लाख से अधिक ग्राहक (43%) महिलाएं हैं।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) :** पीएमजेजेबीवाई के तहत 40.70% नामांकन महिला सदस्यों के हैं और 58.21% लाभार्थी महिलाएं हैं। (31 फरवरी 2020 को) दर्ज किए गए कुल 4,71,71,568 नामों में से 1,91,96,805 महिलाओं ने नाम दर्ज कराए हैं। कुल 1,69,216 दावों में से महिला लाभार्थियों

के 95,508 दावों का भुगतान किया गया है। (31 जनवरी 2020 को)

- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) :** पीएमएसबीवाई के तहत 41.50% नामांकन महिला सदस्यों के हैं और 61.29% लाभार्थी महिलाएं हैं। (31 जनवरी 2020 को) कुल दर्ज किए गए 15,12,54,678 नामों में से 6,27,76,282 नाम महिलाओं ने दर्ज कराए। कुल 38,988 दावों में से महिला लाभार्थियों को 23,894 दावों का भुगतान किया गया है। ■

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधी को मृत्युदंड

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करनेवालों को मृत्युदंड देने के प्रावधान को मंजूरी दी। इससे बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगेगी क्योंकि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे। ■

दुष्कर्म और पॉस्को अधिनियम के मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन

12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म तथा महिलाओं के खिलाफ इसी तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों को निपटाने हेतु देश भर में 1023 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की योजना प्रारंभ। ■

भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आईएमएफ

श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब साल 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने देश का शासन संभाला था, तब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत 9वें स्थान पर था। अक्टूबर में आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत अब फ्रांस, ब्रिटेन से आगे निकल गया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देश की जीडीपी वृद्धि दर पिछले एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक रही है- जो नियमित रूप से 6-7% की वार्षिक दर से बढ़ी है। ■

अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक का विस्तार देना

आज भारत की अर्थव्यवस्था करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की है। गत बजट में जिन नए सुधारों की घोषणा की गई है, उससे अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होगी और अगले पांच साल में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में सहयोगी होगा। ■

भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर...

- **भारत ने किया 'चंद्र मिशन-2' का सफल प्रक्षेपण :** रूस, अमेरिका, चीन के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश भारत।

  भारत ने 'अनगिनत सपनों को चांद पर ले जाने' के उद्देश्य से अपने दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2' का 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

- **चंद्रयान-2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित :** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान-2 को चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।
- **कार्टोसैट-3 और 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण :** भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन ने अपनी 49वें उड़ान (पीएसएलवी-सी47) में कार्टोसेट-3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों का 27 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया।
- **पीएसएलवी की पचासवीं उड़ान :** आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपनी पचासवीं उड़ान (पीएसएलवी-सी48) में आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ वाणिज्यिक उपग्रहों का 11 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
- **भारत के नवीनतम संचार उपग्रह 'जीसैट-30' :** भारत के नवीनतम संचार उपग्रह 'जीसैट-30' का 17 जनवरी को फ्रेंच गुआना के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।

कोविड-19 संकट और प्रबंधन
चुनौतियों पर विजय-भारत अजेय

'जान है तो जहान है'

‘जनता कर्फ्यू’

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर पूरे देश ने 22 मार्च, 2020 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ‘जनता कर्फ्यू’ का पालन किया। उसी दिन शाम 5 बजे राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं सुरक्षाकर्मियों को पूरे देश ने घर से बाहर निकल कर ताली, थाली, शंख घंटी आदि बजाकर धन्यवाद किया।

‘जान है तो जहान है’

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 की आधी रात से शुरू होने वाला लॉकडाउन अगले 21 दिनों तक पूरे देश में लागू किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्र के साथ 5 अप्रैल को ‘दीप प्रज्ज्वलन’ कार्यक्रम में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 अप्रैल, 2020 को नई दिल्ली में अपने निवास पर सभी लाइटों को बंद करने के बाद दीप प्रज्ज्वलित करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले श्री मोदी ने अपने संबोधन में कोरोनो वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाने के लिए नागरिकों से 09 बजे 09 मिनट के लिए लाइट बंद करने की अपील की थी, जिसका पूरे देश में एकजुटता से पालन हुआ।

कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के 07 कदम

14 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सात चरणों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जिसमें बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने, सामाजिक दूरी की ‘लक्ष्मण रेखा’ का पूरी तरह से पालन, होममेड फेस-कवर और मास्क का इस्तेमाल, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन, ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने, गरीब परिवारों की देखभाल, किसी को आजीविका से वंचित न करने, देश के कोरोना वारियर्स को अत्यधिक सम्मान देने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘गमछा मास्क’ का उपयोग किया

राष्ट्रीय एकता का उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान मणिपुरी गमछे से बने फेस कवर इस्तेमाल किया। जिसमें उन्होंने 03 मई तक कोरोना वायरस लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि लेंग्यान गमछा एकता का प्रतीक है।

मोदी सरकार ने एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों के वेतन में 30% की कमी की और 2 वर्षों के लिए सांसद निधि पर रोक लगाई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के सभी सदस्यों के वेतन में 30% कटौती और सांसद निधि (MPLAD) योजना पर दो साल के लिए प्रतिबंध को मंजूरी दे दी ताकि बचाई गई राशि को कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकें।

- 19 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने के लिए संसद अधिनियम, 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सहित सभी सांसदों के वेतन में वित्त वर्ष 2020-2021 में कटौती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने 2020-2021 और 2021-2022 के लिए सांसद निधि को भी निलंबित करने का फैसला किया है। इन कटौतियों से सरकार को 7,900 करोड़ रूपये की बचत होगी।
- केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने यह बताया कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू समेत सभी राज्यपालों ने 30% वेतन कटौती का निर्णय अपनी इच्छा से लिया है।
- बचाई गई पूरी राशि भारत के समेकित कोष में जाएगी।

सरकार ने पीएम केयर फंड बनाया

भारत में कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर फंड) 28 मार्च 2020 को बनाया गया। इस कोष का उपयोग भविष्य में कोरोना वायरस प्रकोप और इसी तरह की महामारी के खिलाफ मुकाबले, रोकथाम और राहत प्रयासों के लिए किया जाएगा। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ट्रस्टियों में रक्षा, गृह और वित्त मंत्री शामिल हैं।

13 मई, 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने 3,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया। 3,100 करोड़ रुपये में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये की राशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए दी गई। 1,000 करोड़ रुपये का उपयोग प्रवासी की देखभाल के लिए किया जाएगा। मजदूरों टीका विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

स्विस आल्प्स भारतीय तिरंगा की रोशनी से रोशन हुआ

स्विट्जरलैंड ने 18 अप्रैल, 2020 को स्विस आल्प्स में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर से अधिक आकार के भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्ट करके कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री नरेंद्र मोदी ने एचसीक्यू टैबलेट्स की आपूर्ति के साथ कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व किया।

भारत ने लॉकडाउन से पहले 1444 देशी और विदेशी नागरिकों को बचाया

कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के साथ ही भारत सरकार ने वायरस की चपेट में आए विभिन्न देशों में फंसे अपने नागरिकों इसके अलावा मोदी सरकार ने मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका जैसे देशों के 48 नागरिकों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया।

भारत ने 30 देशों में फंसे 28,000 से अधिक नागरिकों को बचाया

भारत ने 'वंदे भारत' और 'समुद्र सेतु' मिशन पहले दो चरणों के दौरान बड़े पैमाने पर 30 से अधिक देशों में फंसे 28,500 से अधिक नागरिकों को वापस लाया है। 4921 छात्र, 3969 पेशेवर, 5936 श्रमिक, 3254 पर्यटक, 610 निर्वासित, 429 जिन्हें विभिन्न देशों में एमनेस्टी दी गई, 551 चालक दल के साथ-साथ 5222 विभिन्न श्रेणियों से, कुल मिलाकर 28,500 नागरिक 30 देशों से वापस आए। 'समुद्र सेतु' के तहत भारतीय नौसेना के पोत 1,488 भारतीयों को वापस लेकर आए।

'वंदे भारत मिशन' के तहत 50 गर्भवती महिलाओं का लाया गया

'वंदे भारत मिशन' के तहत नेशनल कैरियर एयर इंडिया ने 11 मई, 2020 को लंदन से हैदराबाद की एक उड़ान भरी, जिसमें 50 गर्भवती महिलाएं सवार थीं। लंदन में फैली महामारी की स्थिति के कारण स्त्रीरोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं कर रहे थे। यह कुछ ऐसा है जिसने उन्हें भारत लौटने के लिए मजबूर किया।

सरकार ने कोविड -19 के लिए सबसे बेहतर स्वास्थ्य ढांचा स्थापित किया

देश में कोविड-19 प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की गई है। आज सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 483 जिलों में 7740 सुविधा केंद्रों की पहचान की गई है, जिसमें राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अस्पतालों और केंद्र सरकार की सुविधाएं भी शामिल हैं। आइसोलेशन के लिए 6,56,769 बेड, पुष्टि मामलों के लिए 3,05,567 बेड, संदिग्ध मामलों के लिए 3,51,204 बेड, 99,492 ऑक्सीजन समर्थित बेड, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड्स के साथ 1,696 सुविधाएं और 34,076 आईसीयू बेड हैं।

जनवरी में 1 परीक्षण प्रयोगशाला से बढ़कर अब 610 हुई

25 मई तक भारत में 610 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें 432 सार्वजनिक और 178 निजी क्षेत्र की है। यह प्रयोगशालाएं वर्तमान में प्रतिदिन 1.1 लाख नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। जनवरी, 2020 में देश में केवल 01 परीक्षण प्रयोगशाला थी। परीक्षण क्षमता भी प्रति दिन 1.4 लाख नमूनों तक बढ़ा दी गई है।

भारत का कोविड-19 मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है

26 मई, 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 2.87 प्रतिशत है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। समय पर लॉकडाउन, जल्दी जांच और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का प्रबंधन कम मौत का मुख्य कारण है। अप्रैल में 3.38 फीसदी से घटकर अब मृत्यु दर 2.87 फीसदी पर आ गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 6.4 फीसदी है।

अन्य देशों जैसे फ्रांस में मृत्यु दर 19.9 प्रतिशत है, बेल्जियम में 16.3 प्रतिशत है, इटली में 14.3 प्रतिशत है, यूके में 14.2 प्रतिशत है, स्पेन में 12.2 प्रतिशत है, स्वीडन में 11.9 प्रतिशत है, कनाडा में 7.6 प्रतिशत है, ब्राजील में 6.3 प्रतिशत है, यूएस में 6.0 प्रतिशत है, चीन में 5.5 प्रतिशत और जर्मनी में 4.6 प्रतिशत है।

विश्व में 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख 0.3 मौतें

वैश्विक स्तर पर 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख जनसंख्या में 0.3 मौतें होती हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। यह लॉकडाउन, समय पर जांच और कोविड-19 मामलों के बेहतर प्रबंधन के कारण हुआ है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार बेल्जियम में प्रति लाख जनसंख्या में 81.2 मौतें होती हैं, जबकि स्पेन में प्रति जनसंख्या 61.5 मौतें और ब्रिटेन में प्रति लाख आबादी में 55.3 मौतें हुई हैं। इटली, फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और जर्मनी में यह दर क्रमशः 54.3, 42.3, 39.3, 29.3, 17.2, 10.5 और 10.0 लोगों की मृत्यु प्रति लाख है।

केंद्र सरकार ने 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉंच किया

एक प्रमुख निवारक उपाय के रूप में मोदी सरकार ने 'आरोग्य सेतु' नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह एक टोल-फ्री सेवा है जो लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को होने वाले जोखिम का आकलन करने में सक्षम बनाती है। भारत का 'आरोग्य सेतु' ऐप केवल 13 दिनों में दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है।

भारत ने 120 से अधिक देशों को दवाएं भेजीं

भारत, जिसे 'विश्व की फार्मेसी' माना जाता है, ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन दवाएं भेजी हैं।

6.39% कोविड-19 मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता, रिकवरी दर 42% हुई

भारत में 25 मई को कोरोना रिकवरी दर 42% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल कोविड रोगियों में से लगभग 42 प्रतिशत ठीक हो गए है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में केवल 6.9 प्रतिशत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक स्तर पर, प्रति 100,000 में 62 लोग संक्रमित हैं और भारत में यह आंकड़ा 7.9 पर है।

वायु सेना ने कोरोना योद्धाओं दी सलामी

भारतीय वायु सेना ने दिल्ली और एनसीआर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों एक फ्लाई पास्ट किया, जिसमें उन कोरोना योद्धाओं को सलामी दी गई, जो इस महामारी का सामना करने वालों की अग्रिम पंक्ति में शामिल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस फ्लाई पास्ट की तारीफ की।

'शून्य' से लेकर अब भारत प्रति दिन 3 लाख से अधिक पीपीई किट और एन95 मास्क का उत्पादन कर रहा है

भारत ने पीपीई और एन 95 मास्क की अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता में महज दो महीने के अंतराल में काफी वृद्धि की है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। फरवरी 2020 में शून्य उत्पादन से आज मई के मध्य तक प्रति दिन 3 लाख से अधिक पीपीई किट और इतनी ही संख्या में एन 95 मास्क का उत्पादन हो रहा है।

भारतीय नौसेना ने विशेष कपड़े से बने पीपीई किट का विकास किया

मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन में भारतीय नौसेना द्वारा कम लागत वाला पीपीई विकसित किया गया है। इसके तेज और बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक पेटेंट भी सफलतापूर्वक दायर किया है।

माइक्रोवेव स्टरलाइज़र 'अतुल्य' विकसित किया गया

डीआरडीओ द्वारा समर्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे ने एक माइक्रोवेव स्टेरिलिज़र विकसित किया है जिसे 'अतुल्य' नाम दिया गया है। 560 से 600 सेल्सियस तापमान पर यह वायरस को विघटित करने में कामयाब होता है।

29 दिनों में 3,736 'श्रमिक विशेष' ट्रेनों के माध्यम से 50 लाख से अधिक प्रवासियों को भेजा गया

29 मई, 2020 तक 3,736 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों में 50 लाख से अधिक फंसे हुए प्रवासी मजदूर को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। प्रवासियों को गृह राज्य तक पहुंचने के लिए राहत प्रदान करने के निरंतर प्रयास करते हुए रेल मंत्रालय ने जून के पहले सप्ताह तक 2600 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया है।

कोविड से मुकाबले के लिए मोबाइल स्प्रेयर विकसित किया गया

सीएसआईआर-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमईआरआई), दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने दो मोबाइल इनडोर कीटाणुशोधन स्प्रेइंग इकाइयां विकसित की हैं। इन स्प्रेयरों का उपयोग टेबल, डॉकानॉब्स, लाइट स्विच, काउंटरटॉप्स, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालय, नल, सिंक और कार्डबोर्ड जैसी सतहों को साफ और कीटाणुरहित करने के लिए किया जा सकता है।

कोविड -19 के परीक्षण के लिए 'कोविड कवच एलिसा'

पुणे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) -ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी तकनीक एलिसा परीक्षण को विकसित किया है। इससे कोरोनावायरस संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात पर निगरानी रखने में सहायता प्राप्त होगी। ■

लॉकडाउन ने कोविड-19 की रफ्तार को 60% तक कम किया

लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने में काफी हद तक सफल मिली है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन से पता चलता है कि लॉकडाउन 1.0 के अंत तक यानी 14 अप्रैल को यह 1.71 पर आ गया। 3 मई को, जब लॉकडाउन 2.0 समाप्त हुआ, तो यह घटकर 1.46 हो गया और 16 मई को यह और गिरकर 1.27 हो गया। इसका मतलब है कि लॉकडाउन वायरस के प्रसार को लगभग तीन गुना तक कम कर देता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान
20 लाख करोड़ रु. का व्यापक पैकेज

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज

- कोविड-19 से लड़ने वाले प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी।
- 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे।
- मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
- 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- सरकार वर्तमान ‘पीएम किसान योजना’ के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
- केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ‘भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष’ का उपयोग करने के आदेश दिए हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान : 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए स्पष्ट आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों यथा-अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी या शक्ति और मांग को भी रेखांकित किया।

एमएसएमई को भारी राहत

- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा।
- कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अप्रधान ऋण।
- ‘एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स’ के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी।
- एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
- जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई।
- ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा।
- एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना।
- एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण

गारंटी योजना 2.0।

- डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी।
- ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई।
- रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत, सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा।
- व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे।
- वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'स्रोत पर कर कटौती' और 'स्रोत पर संगृहीत कर' की दरों में 25% की कटौती।

प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी–पटरी वालों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा

- **प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त अनाज : एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।** प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिक मार्च 2021 तक देशभर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन (पीडीएस) प्राप्त कर सकें एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड।
- प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- 'शिशु मुद्रा' के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी – 1500 करोड़ रुपये की राहत।
- रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा।
- पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
- कैम्पा फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये।
- नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन।

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों की घोषणा

- किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष।
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाना - 15,000 करोड़ रुपये।
- कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय।
- किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन।
- किसानों को विपणन के विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार।

आठ सेक्टरों में ढांचागत सुधार :

- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, विविध अवसर, उदार व्यवस्था, खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और नीतिगत सुधार।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार।

रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि

- केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा।
- भारत को भावी महामारियों हेतु तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुधार।
- कंपनी अधिनियम से संबंधित डिफॉल्ट को अपराध की श्रेणी से हटाया गया।
- कंपनियों के लिए कारोबार करने में सुगमता। एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति। ■

मोदी सरकारः 2014 - 2019

मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां

गरीब हमारी पहली प्राथमिकता

- **34 करोड़ 43 लाख गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए** - देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुख्यधारा के अर्थतंत्र से जोड़ने के लिए जन-धन योजना के अंतर्गत यह खाते खोले गए। इन खातों में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा हुई है।
- **1 करोड़ 53 लाख से अधिक घरों का निर्माण हुआ** - प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में इन घरों का निर्माण हुआ है जिन्हें बेघर गरीबों के लिए स्वीकृत किया जा रहा है ।
- **जन औषधि केंद्र** - प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत देश में 5,000 से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं जिनके माध्यम से जन सामान्य को 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- **10 करोड़ परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा** - आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों का 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
- **14 करोड़ 64 लाख लोगों का दुर्घटना बीमा** - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष देकर इतने लोगों का बीमा करवाया गया।
- **5 करोड़ 67 लाख परिवारों का जीवन बीमा** - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये प्रति वर्ष देकर इतने लोगों का बीमा करवाया गया।
- **9 करोड़ 74 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण** - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसके कारण स्वच्छता के साथ-साथ गरीब महिलाओं को शर्मसार होने से मुक्ति मिली।
- **समूचे देश में अन्न सुरक्षा योजना का लाभ**- देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल दिया गया।
- **आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण** - एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए और दशकों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए संविधान में संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया।
- **सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में**- 437 योजनाओं के लाभान्वित लोगों को 6 लाख 6 हजार 473 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में भेजी गयी है।
- **देश के हर गांव में बिजली पहुंची** - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी गांवों में यह बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया गया।
- **2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंची** - गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए।

समृद्ध किसान - समृद्ध राष्ट्र

- **लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य**- पहली बार किसानों को उनकी रबी और खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का ड़ेढ़ गुना घोषित किया गया है, जिसके कारण उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत प्राप्त हो रही है।
- **प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को सम्मान** - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में पहली बार 5 एकड़ तक भूमि वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
- **ई-नैम प्लेटफार्म के माध्यम से फसलों की सीधी बिक्री**- किसान अपना माल जिस मंडी में सबसे ज्यादा भाव या दाम मिल रहा हो उसमें बेच सकें और सस्ते में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर न हों, इसलिए 585 मंडियों को ई-नैम के अंतर्गत जोड़ा गया है जिसके माध्यम से किसान सर्वाधिक मूल्य पर अपनी फसलें बेच रहे हैं।
- **नीम कोटेड यूरिया** – यूरिया की कालाबाजारी को रोकने और किसानों को यूरिया सहजता से उपलब्ध कराने के लिए 100% यूरिया की नीम कोटिंग करवाई गई है, इसके कारण किसान को समय पर और पर्याप्त मात्रा में बिना किसी परेशानी के यूरिया मिल पा रहा है।
- **कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन**- कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए और किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, फसल बर्बाद होने पर पर्याप्त मुआवजा मिले, इसलिए पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 2 लाख 11 हजार 694 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया, है जो अब तक का सबसे ज्यादा है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु बजटीय आवंटन में 16.21% की वृद्धि**- इस योजना के अंतर्गत 'पर ड्राप मोर क्रॉप (बूंद-बूंद से फले फसल)' के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 5 हजार 460 करोड़ रुपये की धनराशि का बजटीय आवंटन किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।
- **प्राकृतिक आपदा से अधिक सुरक्षा**- पहले किसानों को प्राकृतिक आपदा से 50 प्रतिशत फसल बर्बाद होने पर ही आर्थिक सहायता मिला करती थी किंतु अब 33 प्रतिशत का नुकसान होने पर ही यह सहायता दी जा रही है। इसके कारण किसानों को दी गई कुल राहत राशि में 6 गुना वृद्धि हुई है।
- **18 करोड़ 41 लाख मिट्टी जांच कार्ड (Soil Health Card) का वितरण**– किसानों की ज़मीन की मिट्टी की जांच के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना बनाई गई है। मिट्टी की इस जांच के कारण किसानों को ज्यादा फसल लेने के लिए सही सलाह मिल रही है।
- **वार्षिक दूध उत्पादन में 49% की वृद्धि**- डेयरी किसानों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर में पिछले पांच वर्षों में लगभग 49% की बढ़ोतरी हुई है।
- **दलहन-तिलहन की खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि**- भाजपा सरकार के

पांच वर्षों में 78 लाख 61 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की खरीद की गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा खरीदी है।

- **मछली उत्पादन में 42.22% वृद्धि-** पिछले वित्त वर्ष के दौरान मछली के उत्पादन में 42.22% वृद्धि दर्ज की गयी है। इस दिशा में भारत की निर्यात क्षमता में भी 180% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- **दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों तथा मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड-** पहले किसान क्रेडिट कार्ड केवल खेती करने वालों को ही दिया जाता था लेकिन अब दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों तथा मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है ।
- **बांस को काटने की अनुमति-** भारतीय वन अधिनियम, 2017 में संशोधन करके बांस को अब वृक्ष की श्रेणी से निकालकर घास की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब बांस को काटने एवं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसानों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण पूर्वोत्तर के किसानों की किस्मत ही बदल गई है और अन्य राज्यों के किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल गया है।

श्रमिकः श्रमेव जयते

- **असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मानधन-** असंगठित क्षेत्र के कामगार यानी स्वयं मेहनत मज़दूरी करके अपने परिवारों को पालने का काम कर रहे लोगों के लिए एक ऐतिहासिक 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से इन कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है, तो उसे मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- **न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि-** मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है।
- **श्रमिकों की बोनस सीमा में वृद्धि-** श्रमिकों को मिलने वाले वार्षिक बोनस को अब दोगुना करके 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सबसे ज्यादा है।
- **न्यूनतम पेंशन का निर्धारण-** पहले श्रमिकों को 50 या 100 रुपए भी पेंशन मिला करती थी। मोदी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को 1000 रुपए से कम पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी को कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित कर दी गई है।
- **मनरेगा के बजटीय आवंटन में वृद्धि-** वर्ष 2018-19 में मोदी सरकार ने मनरेगा की धनराशि को बढ़ाकर 55 हजार करोड़ रुपए कर दिया है तथा सरकार अब मजदूरी की राशि हर 15 दिन बाद मजदूरों के बैंक खाते में सीधे डालती है।
- **यूनिक प्रोविडेंट फंड खाते का आरंभ-** सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को प्रोविडेंट फंड का यूनिक खाता प्रदान किया गया है। अब फंड की बचत राशि नौकरी बदलने के बाद भी नए रोजगार के रूप में मिलेगी।
- **दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और विकास बोर्ड -** इस बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित व मनरेगा कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

- **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु बजटीय प्रावधान-** अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के कल्याण हेतु 95 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।
- **पंचतीर्थ योजना-** हमारे संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के प्रति अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी सरकार ने डॉ. अम्बेडकर से जुड़े पांच स्थानों को पंचतीर्थ मानकर नया निर्माण करवाया है।
- **स्टैंड अप योजना-** अनुसूचित जाति, जनजाति के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए स्टैंड अप योजना बनाई गई है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। देश के हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कम-से-कम एक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यह ऋण अनिवार्य रूप से दिया जाए।

- **छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि-** अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दिया गया है।
- **छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि-** पिछले 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 7 लाख एससी/एसटी छात्रों को 15,918 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का लाभ मिला है।
- **जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना-** भाजपा सरकार द्वारा जनजातियों की विरासतों को संरक्षित करने हेतु उनकी पारंपरिक संस्कृति, कलाओं और बोली-भाषाओं के प्रोत्साहन और संवर्द्धन संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
- **अंतर-जातीय विवाह के लिए सम्मान राशि-** अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करने पर ढाई लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत 71,387 वैवाहिक जोड़ों को 219 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।
- **सशक्त एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम-** अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को संविधान में संशोधन करके और अधिक सशक्त बनाया गया है।
- **विशेष अदालतों की स्थापना -** एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई।
- **अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि-** अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान करने के लिए वेंचर कैपिटल योजना (Venture Capital Scheme) शुरू की गई। इसमें ब्याज़ दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 322 करोड़ 8 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए।
- **एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना-** इस योजना के तहत 288 एकलव्य मॉडल विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं तथा पिछले पांच वर्षों में 2751 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए गए हैं।
- **कौशल विकास योजना-** इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 102 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। अब तक एक लाख 7 हज़ार 246 अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्तियों को इसका लाभ मिला।
- **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना-** इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चिन्हित 2,500 गांवों के विकास के लिए 530 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
- **विदेश अध्ययन हेतु नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना-** इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष चयनित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की गई है। इस सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति वर्ग के 484 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन हेतु नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 39 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।

अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्ज़ा -** अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए संविधान का संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह आयोग अब सलाहकार नहीं, बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा।
- **क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि-** पहले 6 लाख रूपए से अधिक आय वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग की सुविधाओं की पात्रता नहीं थी। अब 8 लाख रुपए तक की आय वाले लोग भी पिछड़ा वर्ग की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- **पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के लाभ-** विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ 64 लाख छात्रों को 3,797 करोड़ 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

सेना और पूर्व सैनिकों के प्रति समर्पित मोदी सरकार

- **कृतज्ञ राष्ट्र का शहीदों को नमन-** शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देश में 'राष्ट्रीय समर स्मारक' की स्थापना की गई है।
- **वन रैंक-वन पेंशन की मांग पूरी-** दशकों पुरानी वन रैंक – वन पेंशन की मांग को पूरा करके सैनिकों को सम्मान दिया गया है।
- **रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक-** वर्ष 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने पहली बार रक्षा क्षेत्र का बजट 3 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है।
- **बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग पूरी-** सेना द्वारा वर्ष 2009 में की गई बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग को पूरा कर दिया गया है। एक लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद को स्वीकृति दी गई।
- **अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को स्वीकृति-** सेना के लिए राफेल सहित अन्य अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई।
- **शस्त्र निर्माण में स्वदेशी क्षमता की वृद्धि –** अभी तक भारत विदेशों से आयातित शस्त्रों पर ही निर्भर था। अब हम स्वदेश में शस्त्र निर्माण की क्षमता की ओर तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण

- अजन्मी बेटी से लेकर महिला के बुढ़ापे तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके कल्याण की योजनाएं बनाई हैं। उनकी एक झलक यहां प्रस्तुत है :
- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान –** कन्या भ्रूण हत्या हमारे लिए एक अभिशाप है। गर्भ में बेटी का पता लगते ही गर्भपात करा देने से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' चलाया। यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक अभियान है। इसके परिणामस्वरूप 104 जिलों में लड़कियों की जन्मदर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा का उदाहरण तो बहुत सुखद है, जहां 1,000 लड़कों की तुलना में 883 लड़कियां पैदा होती थीं। अब यह संख्या बढ़कर 914 हो गई है।

- **सुकन्या समृद्धि योजना –** इस योजना में बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत एक करोड़ 30 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मुफ्त शिक्षा और छात्रावास-** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गरीब परिवार की बेटियों को कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- **गर्भवती महिलाओं का रक्षण-** प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत 13,161 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक करोड़ 70 लाख से अधिक प्रसवपूर्व चेक-अप के साथ ही 86 लाख 88 हजार गर्भवती महिलाओं का रक्षण किया गया है।
- **गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता -** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हर वर्ष 50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- **महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि-** महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह (6 महीने) कर दी गई है ताकि वे अपने नवजात शिशु की अच्छी तरह देखभाल कर सकें। 49 लाख 88 हजार महिलाओं को मातृत्व लाभ के लिए 01 लाख 678 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- **गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन -** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं की जिन्दगी आसान करने तथा धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए के 6 करोड़ 26 लाख महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन बांटे गए हैं।
- **स्वरोज़गार के लिए ऋण की सुविधा-** महिला कामगारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 16.5 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 72.25 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं।
- **राशन कार्ड महिला के नाम पर-** एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर यह तय किया गया है कि महिला को परिवार की मुखिया मानकर राशन कार्ड उसके नाम पर ही बनाया जाएगा।
- **स्टैंप ड्यूटी में राहत-** यदि जायदाद महिला के नाम पर होगी तो स्टैंप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- **स्टैण्ड-अप योजना-** इस योजना के

अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। देश के हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कम-से-कम एक महिला को यह ऋण अनिवार्य रूप से दिया जाए।

- **भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में अब महिलाएं भी-** इंडियन एयर फोर्स में पहली बार भारतीय महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट के रूप में शामिल किया गया है।
- **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि-** देश भर में 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की गई है।
- **12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा-** एक कानून बनाकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी की न्यूनतम सजा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।
- **ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण-** तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाने तथा मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को पुरुष अभिभावक के बिना हज पर जाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है।
- **पासपोर्ट नियमों में संशोधन द्वारा तलाकशुदा महिलाओं को राहत-** पासपोर्ट नियमों में संशोधन करके तलाकशुदा महिलाओं के अपने पूर्व पति का नाम न लिखने की छूट दे दी गई है जिसके कारण उन्हें मानसिक यातना से राहत मिली है।

युवा- हमारा भविष्य

- **स्वरोज़गार हेतु 16 करोड़ से अधिक ऋणों का वितरण-** स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत 16 करोड़ लोगों को 7 लाख 74 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया।
- **स्वरोज़गार के लिए स्टार्ट-अप-** स्वरोज़गार के लिए अब तक 15,649 स्टार्ट-अप्स को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
- **देशभर में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना-** 14 नए एम्स, 14 नए ट्रिपल आईटी, 7 नई आईआईटी, 7 नए आईआईएम, एक नई एनआईटी, 103 नए केंद्रीय विद्यालय तथा 62 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है, ताकि हमारे युवा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छे संस्थानों में रोज़गार प्राप्त कर सकें।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों (PMKVY) की स्थापना-** युवाओं को 375 ट्रेड्स में प्रशिक्षित करने हेतु देश के हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए। इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवक तथा युवतियां अपना रोज़गार प्रारंभ कर रहे हैं।
- **प्रतिभाशाली युवाओं को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप-** इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं को 5 वर्ष तक 70,000-80,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति और शोध के लिए 2 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान दिया गया।
- **खेलो इंडिया-** इसके अंतर्गत हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के खिलाड़ियों, को निर्बाध रूप से एक व्यापक और मज़बूत व्यवस्था प्रदान करके खेलकूद के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा।
- **अटल टिंकरिंग लैब्स को स्वीकति-** 60 लाख से अधिक छात्रों को अभिनव कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कूलों में 5,441 अटल टिकरिंग लैब्स को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता-** इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक 5 लाख रुपये वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

दिव्यांग-हमारे विशिष्ट नागरिक

शरीर के किसी एक अंग से बाधित व्यक्ति को दिव्यांग शब्द की संज्ञा देकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए उन्हें सम्मान दिया है :

- **दिव्यांगजन के कल्याण हेतु दिव्यांगताओं के प्रकार में वृद्धि-** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से पूर्व में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई।
- **दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण में वृद्धि-** दिव्यांगजनों के अधिकतम कल्याण हेतु दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को पूर्व में दिए जा रहे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया।
- **कॉलजों और व्यावसायिक संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण में वृद्धि-** दिव्यांगजन के लिए कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण में वृद्धि करते हुए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
- **एडिप-** इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 7,800 से अधिक शिविर आयोजित किए गए जिसमें 12 लाख 40 हजार दिव्यांगजन को 737 करोड़ 51 लाख रुपए का लाभ। इस दौरान 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए गए।
- **कॉक्लियर इंप्लांट ऑपरेशन-** इस योजना के अंतर्गत ऑपरेशन कराने हेतु प्रत्येक दिव्यांगजन को 6 लाख रुपए सहायता राशि का अनुदान दिया।
- **मैट्रिकपूर्व और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति-** इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 17 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि जारी की गई है जिससे 24,545 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति हेतु 60 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है जिससे 31,448 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए।

- **दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-** इसके अंतर्गत 266 संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से एक लाख 58 हजार 468 दिव्यांगजन के कौशल प्रशिक्षण के लिए 174 करोड़ 48 लाख रुपए का सहायता अनुदान जारी किया गया।
- **दिव्यांगता खेल केंद्र-** ग्वालियर में 170 करोड़ रुपए की लागत से एक दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किया गया।
- **भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान केंद्र की स्थापना-** मूक एवं बधिर दिव्यांगजन की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) की स्थापना की गई।
- **दिव्यांग छात्रों के लिए रैम्प व रेलिंग और विशेष शौचालयों का निर्माण-** देशभर में दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए 54,000 रैम्प व रेलिंग और 50,000 विशेष शौचालयों का निर्माण किया गया।
- **दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्के-** मोदी सरकार द्वारा दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला को जारी किया गया।
- **दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र जारी-** दिव्यांगजन का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया।

अल्पसंख्यक अब मुख्यधारा में

गरीबों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबों को भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाएं केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाई गई हैं :

- सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, गरीब नवाज कौशल विकास योजना जैसी रोज़गारपरक तथा कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से लगभग 7 लाख 50 हजार युवाओं को कौशल विकास तथा रोज़गार के अवसर मुहैया कराए गए। इनमें लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं।
- हुनर हाट के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 2 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों/शिल्पकारों को न केवल रोज़गार तथा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसर भी मुहैया कराए गए।
- **विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-** पिछले लगभग 4 वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज के गरीब व कमज़ोर लगभग 2 करोड़ 95 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं।
- **लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी-** मोदी सरकार के

प्रयासों का नतीजा है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की दर, जो पहले 70-72 प्रतिशत थी, वह अब घटकर लगभग 35 प्रतिशत रह गई है। हम इसे शून्य प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- नई रोशनी योजना के तहत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को विभिन्न तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके जरिए वे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं।
- **मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण-** वर्ष 2018 में मदरसा शिक्षकों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण-** मोदी सरकार के इस अभियान के तहत 90 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल-** सभी छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 'डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT)' के जरिए सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भेजी जा रही हैं।
- **ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण-** तीन तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।
- **मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जाने की अनुमति-** अब मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक को साथ लिए हज के लिए जा सकती हैं।
- **हज कोटे में वृद्धि-** वर्ष 2014 में हज कोटा एक लाख 36 हजार हाजियों के लिए था, जो हमारे कार्यकाल में बढ़ते-बढ़ते अब 2 लाख हाजियों के लिए हो गया है।
- **'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के द्वारा विकास योजनाओं का विस्तार-** पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 28 डिग्री कॉलेज, 2197 स्कूल भवन, 40201 अतिरिक्त क्लासरूम, 1213 हॉस्टल, 191 आईटीआई, 50 पॉलिटेक्निक, 39586 आंगनबाड़ी केंद्र, 348624 घर, 405 सद्भावना मंडप, 89 आवासीय स्कूल, 527 मार्किट शेड्स, 17397 पेयजल सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में निर्माण कराया गया।

छोटे उद्यमी स्वदेशी के ध्वजवाहक

- **एमएसएमई सेक्टर के लिए 59 मिनट में लोन स्वीकृति-** एमएसएमई सेक्टर के लिए एक करोड़ रुपये तक के लोन की स्वीकृति अब एक घंटे से भी एक मिनट कम में की जाती है।
- **छोटे उद्यमियों के लिए जीसटी छूट सीमा में बढ़ोतरी-** छोटे उद्यमियों को राहत देते हुए जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया गया है।
- **तकनीक उन्नयन हेतु 'हब एंड स्पोक' की स्थापना-** एमएसएमई को तकनीकी सहायता के लिए 'हब एंड स्पोक' की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत देशभर में 20 केंद्रों (हब्स) और 100 टूलरूम्स (स्पोक्स) की स्थापना की जाएगी।
- **साल में एक बार ही रिटर्न भरने की सुविधा-** इसके अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाने वाला रिटर्न अब साल में दो बार की जगह एक बार ही देने की सुविधा प्रदान की गई है।
- **निवारण प्रक्रिया को आसान बनाना-** इसके अंतर्गत एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को अब छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।

अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है। ■

विश्व भर में हो रही भारत की प्रशंसा

विश्व बैंक ने नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन की प्रशंसा की

विश्व बैंक द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन की प्रशंसा की गई क्योंकि इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बाद उपजे आर्थिक संकट के बीच भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए 1 बिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस बीमारी ने देश की अर्थव्यवस्था और जनता को सीधे तौर पर प्रभावित किया है।

15 मई को वर्ल्ड बैंक के इंडिया डायरेक्टर जुनैद अहमद ने कहा, "मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर मिशन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत कोविड-19 के कारण उपजे हालातों में जीवन और आजीविका के बीच कोई अंतर नहीं कर रहा है।"

माइक्रोसॉफ्ट के सह–संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने 23 अप्रैल, 2020 को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की और कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार को थामने के लिए सरकार के प्रयासों की तारीफ की।

डब्ल्यूएचओ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की।

डब्ल्यूएचओ ने भारत का अभिवादन किया

डब्ल्यूएचओ के भारत के प्रतिनिधि हेंक बेकेडम ने 17 मार्च, 2020 को कहा, "भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रतिबद्धता बहुत प्रभावशाली रही है। यही एक कारण है कि भारत अभी भी काफी अच्छा कर रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूं कि हर कोई इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो गया है।"

पेट्रीसिया स्कॉटलैंड ने 'डिजिटल इंडिया' पहल की सराहना की

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कॉमनवेल्थ महासचिव से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सराहना मिली। पैट्रिसिया ने कहा, "भारत ने आईटी (सूचना और प्रौद्योगिकी) में जो किया है उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से भारत ने सस्ती डिजिटल सेवाओं को पेश करके नवाचार और अवसरों के साथ लोगों की आकांक्षाओं को समझने का प्रयास किया है, वह सराहनीय है।"

- अंतरराष्ट्रीय मतदान एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टिंग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वीकृति रेटिंग 1 जनवरी से 14 अप्रैल के बीच 62% से बढ़कर 68% हो गई।
- महामारी के दौरान भारत कोविड-19 से प्रभावित विभिन्न अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए आगे आया। यह अफ्रीका के साथ भारत की पारंपरिक रूप से मजबूत दोस्ती और एकजुटता का नतीजा है, जो पिछले कुछ वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गयी है।

कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए ई–आईटीईसी पाठ्यक्रम की शुरुआत

- विदेश मंत्रालय और एम्स रायपुर ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रोकथाम और प्रबंधन दिशा-निर्देश को लेकर एक कोर्स शुरू किया, जिसे अब अफ्रीका के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रारंभ किया गया हैं। मंत्रालय की इस पहल का व्यापक स्वागत किया गया है। उल्लेखनीय है कि आईटीईसी कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के विभिन्न कार्यक्रम अफ्रीकी देशों के साथ साझा किए गए हैं।
- भारत ने महामारी के दौरान दक्षेस देशों की सहायता की है। चिकित्सा सहायता के अलावा, भारत ने रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को कुवैत और मालदीव भेजा है, जो अन्य देशों में स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित और तकनीकी सहायता देने के लिए वेबिनार आयोजित कर रहे हैं।
- भारत 67 देशों को 10 मिलियन एचसीक्यू टैबलेट प्रदान कर रहा है, जिसमें से 2.8 मिलियन की डिलीवरी 25 मई तक हो चुकी है, इन 21 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जाम्बिया, युगांडा, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, डीआर कांगो, म्यांमार, आर्मेनिया शामिल है।
- श्रीलंका सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक दवाएं भेजने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
- श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धने ने कहा कि उनकी सरकार ने एक विशेष उड़ान के माध्यम से दवाइयां और

संबंधित वस्तुओं को भेजने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और भारत सरकार की सर्वोच्च प्रशंसा और आभार व्यक्त किया है।

- **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच 34 सदस्यीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।**
- कोरोना वायरस प्रभावित ईरान से 58 भारतीयों को निकालने के लिए अमेरिका ने भारतीय वायुसेना की प्रशंसा की।
- अमेरिकी सरकार ने 10 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस प्रभावित ईरान से भारतीयों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए भारतीय वायु सेना की प्रशंसा की।
- वैश्विक कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को 'वंदे भारत मिशन' के तहत भारत सरकार द्वारा वापस लाया जा रहा है।
- भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन 'समुद्र सेतु' भी शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने इसके पहले चरण के दौरान दो जहाजों में लगभग दो हजार भारतीयों को वापस लाने का काम किया है। आईएनएस जलाश्वा और आईएनएस मगर का संचालन भारतीय नागरिकों को विदेशी तटों से वापस लाने के लिए किया जा रहा है।

मिशन सागर: हिंद महासागर में भारत की मदद

कोविड -19 महामारी को लेकर सहायता अनुरोधों के जवाब में भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स भेजा है, इस जहाज पर दो चिकित्सा सहायता टीमें, कोविड से संबंधित आवश्यक दवाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए 'गोलकीपर अवार्ड' से सम्मानित किया गया

- 25 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत में विस्तृत स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलाने के लिए चौथे वार्षिक ग्लोबल गोल्स अवाड्र्स में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 'ग्लोबल गोलकीपर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मोदी सरकार ने इस दिशा में शानदार प्रयास किए हैं।

जलवायु परिवर्तन पर प्रयासों में भारत एक मौलिक भागीदार: यूएन

- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर भारत के प्रयास शानदार है।

  गुटेरेस ने कहा, "भारत एक महत्वपूर्ण घटक है और जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में 'मौलिक भागीदार' है और वह अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को विकसित करने के लिए 'शानदार प्रयास' कर रहा है।"

इस्लामिक राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया

कई इस्लामिक देशों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपने उच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसकी सूची निम्नलिखित है:

डिजिटल इंडिया की सफलता गरीब और विकासशील देशों के लिए आशा की किरण: कॉमनवेल्थ महासचिव

1. किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां - अगस्त 2019
2. ऑर्डर ऑफ जायद, यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार - अगस्त 2019
3. फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर - फरवरी 2018
4. अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, अफगानिस्तान - जून 2016
5. किंग अब्दुलअज़ीज़ सैश अवार्ड, सऊदी अरब - अप्रैल 2016
6. रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, मालदीव- जून 2019

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 20 जुलाई, 2019 को गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने वाली उज्ज्वला योजना की प्रशंसा की।
- उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई, 2016 को मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

आईईए के कार्यकारी निदेशक फतह बिरोल ने कहा कि उज्ज्वला केवल एक ऊर्जा उपलब्धि नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि भी है। पिछले साल, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस योजना की प्रशंसा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी 2019 में भारत के सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हैं: ब्रिटेन स्थित सर्वेक्षण एजेंसी 'यूगोव'

ब्रिटेन स्थित एजेंसी 'यूगोव' द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत में सबसे अधिक प्रशंसा पाने वाले और दुनिया में छठे सबसे अधिक प्रशंसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं।

विश्व बैंक ने भारत की ग्रामीण सड़क योजना का स्वागत किया

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में भारत की ग्रामीण सड़क योजना की सराहना की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसने गतिशीलता में सुधार किया है, आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाई है और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अधिक हुई है। यह भी दावा किया गया है कि ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जुड़े क्षेत्रों में घर पर पैदा होने वाले शिशुओं की संख्या में भारी कमी आई है, इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम-जीएसवाई और अन्य योजनाओं जैसे आवास, रसोई गैस और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदल दिया है। ■

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया 'सुपरमैन'

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, बिश्केक (किर्गिस्तान) : 14 जून 2019 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को मजबूत करने की एससीओ की भावना और उसके विचारों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक आतंकवाद मुक्त समाज की हिमायत करता है।

प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा : भारत और मालदीव के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर : पहला समझौता ज्ञापन (एमओयू) जल विज्ञान संबंधी मामलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया। दूसरा करार स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया। अन्य समझौते समुद्र मार्ग के जरिए यात्री और मालवाहक सेवाएं स्थापित करने, भारत के केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा मालदीव सीमा शुल्क सेवा के बीच सहयोग पर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मालदीव का सर्वोच्च पुरस्कार 'रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन' से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा : दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में 9 जून को पड़ोसी द्वीप देश श्रीलंका पहुंचे। श्री मोदी ने इस यात्रा के लिए पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका को चुना। यह यात्रा 'पड़ोसी प्रथम' की उनकी नीति को दर्शाती है।

एशिया-प्रशांत समूह ने यूएनएसी में दो साल की अस्थाई सदस्यता के लिए किया भारत की उम्मीदवारी का समर्थन : भारत के लिए यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है।

प्रधानमंत्री की भूटान की सफल राजकीय यात्रा, भूटान के साथ 10 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर : भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे शेरिंग के निमंत्रण पर 17-18 अगस्त, 2019 तक भूटान की राजकीय यात्रा की।

प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा व जी-7 शिखर सम्मेलन : प्रधानमंत्री की फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की सफल यात्रा।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 से 26 अगस्त के दौरान फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा की। उन्होंने फ्रांसीसी शहर बिआरित्ज में 25 व 26 अगस्त को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। श्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में 'ऑर्डर ऑफ जायद' और बहरीन में 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द' 'रेनेसां' से सम्मानित किया गया।
- **फ्रांस यात्रा :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में 22 एवं 23 अगस्त को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए और जी-7 फ्रांसीसी अध्यक्षता में बिआरित्ज में 25 व 26 अगस्त, 2019 को जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर फ्रांस की राजकीय यात्रा की।
- **जी-7 शिखर सम्मेलन, बिआरित्ज (फ्रांस) :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के शहर बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। श्री मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की गुंजाइश को 26 अगस्त को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है तथा "हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते।" श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। श्री ट्रंप ने श्री मोदी की इस बात का तुरंत समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं।

बहरीन यात्रा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बहरीन में 24 अगस्त को दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बहरीन में समकक्ष प्रिंस खलीफ बिन सलमान अल खलीफा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम दिए जाने की बात कही। इसके अलावा श्री मोदी ने बहरीन में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया।

हाउडी मोदी, ह्यूस्टन : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर को टेक्सास के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में पचास हजार से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे ट्रम्प भी शामिल हुए।

'ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड 2019' सम्मान : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ग्लोबल गोलकीपर गोल्स अवार्ड 2019 से उन्हें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार लाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जो गांधी जी के एक स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूर्ण करता है।

प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा (ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस मंच) : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस मंच पर प्रमुख व्याख्यान दिया। प्रतिष्ठित लोगों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस अवसर का उपयोग भारत की विकास गाथा की भविष्य की दिशा के बारे में बात करने के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास गाथा चार स्तंभों डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एवं डिसाइवनेस अर्थात् लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और निर्णायकता पर आधारित है।

भारत, बांग्लादेश ने सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये : भारत और बांग्लादेश ने अपने संबंधों को विस्तार देते हुए 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान एलपीजी निर्यात समेत तीन परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया।

भारत-चीन दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, मामल्लपुरम (चेन्नई) : वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के सामरिक, दीर्घकालिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने 11-12 अक्टूबर, 2019 को भारत के मामल्लपुरम (चेन्नई) में अपने दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने एक दोस्ताना माहौल में वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के सामरिक, दीर्घकालिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया।

प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब की एक दिन की आधिकारिक यात्रा की। दोनों देशों ने तेल और गैस, रक्षा एवं नागर विमानन समेत अलग-अलग प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौतों पर 29 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के शाह से रियाद में मुलाकात की : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम (एफआईआई) के दौरान जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह द्वितीय बिन एल-हुसैन से मुलाकात की। इसमें जॉर्डन के शाह की 27 फरवरी 2018 से 1 मार्च, 2018 तक भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र और समझौते भी शामिल थे।

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भारत यात्रा : भारत-जर्मनी के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा समेत 17 क्षेत्रों में समझौता।

जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने एक नवंबर को 17 समझौते और पांच संयुक्त संकल्प-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, शिक्षा, नदियों की सफाई जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी की चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने पांचवें भारत-जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता की।

11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रासिलिया (ब्राजील) : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13-14 नवंबर को ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे 'खुली एवं निवेश के लिए अनुकूल' अर्थव्यवस्था बताते हुए ब्रिक्स देशों की कंपनियों और कारोबारियों से भारत में निवेश करने और वहां मौजूद 'असीम' संभावनाओं तथा 'अनगिनत' अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने मालदीव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने 4 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

भारत में निर्मित तटरक्षक जहाज 'कामयाब' को उपहार के तौर पर मालदीव को देना, रुपे कार्ड लॉन्च करना, एलईडी लाइटों का उपयोग कर माले को रोशन करना, व्यापक सकारात्मक असर वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं और मछली प्रसंस्करण संयंत्रों को लॉन्च करना इनमें शामिल हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर का ऋण देगा भारत : श्रीलंका के नए राष्ट्रपति श्री गोटबाया राजपक्षे ने अपनी पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में 29 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में आतंकवाद से लेकर व्यापार समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, भारत ने श्रीलंका को विकास परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा के अलावा आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए पांच करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी, नेपाली प्रधानमंत्री ने जोगबनी-विराटनगर निगरानी चौकी का उद्घाटन किया : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष श्री के. पी. शर्मा ओली ने 21 जनवरी को सीमा के निकट जोगबनी-विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। गौरतलब है कि जोगबनी-बिराटनगर दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। यह चेकपोस्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है।

कट्टर इस्लामी आतंकवाद से लोगों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं भारत अमेरिकाः डोनाल्ड ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे. ट्रंप ने 24-25 फरवरी को भारत की ऐतिहासिक यात्रा की। वे 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचे। वहां पर लाखों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी दिन वे परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा गए। 25 फरवरी को दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रंप और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। ■

ढांचागत परिवर्तन के नवयुग की शुरुआत

नितिन गडकरी

रचनात्मक सोच, सामाजिक भाव और दृढ़ इच्छाशक्ति कठिन परिस्थिति में भी कार्य को परिणति तक ले जाने में ऊर्जाकारी होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसीलिए हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये, क्योंकि हर दिशा में नये दृष्टिकोण के साथ लक्ष्य का निर्धारण करके कार्य किया गया। सत्ता, संगठन और समाज के बीच समन्वय के कारण जनता में सत्ता के प्रति विश्वास,संगठन के प्रति समर्पण बढ़ा है। सरकार के सभी घटकों ने समाज और राष्ट्र को केन्द्र में रखकर कार्य किया है। सामाजिक समृद्धि से राष्ट्र विकास की अवधारणा के कारण देश नये बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाईवे से एक्सप्रेस-वे, सड़क निर्माण का कार्य 30 किमी प्रतिदिन तक ले जाना और ग्रीन मोबिलिटी के जरिए देश को नये आयाम की तरफ ले जाया गया है।

मोदी सरकार की दूसरी पारी विकास को गति देने वाली है। मुझे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का दोबारा कार्य मिलने से उन कामों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जो पिछले कार्यकाल में आरंभ किए गए थे। हमारी सरकार ने ढांचागत विकास को बेहतर करने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सड़क समय, ईंधन के साथ आवश्यक वस्तुओं की लागत में कमी लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। देश के विकास को गतिशील बनाने के लिए एक्सप्रेस-वे सबसे आवश्यक घटक है। इसलिए हमारा मुख्य फोकस एक्सप्रेस-वे पर है। हम देश में 13 नये एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं। देश को दो एक्सप्रेस-वे दिए जा चुके हैं। महज 500 दिन में 135 किमी लम्बा 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे निर्माण का रिकार्ड है। 14 लेन का 90 किमी लम्बा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे देश का पहला सबसे चौड़ा एक्सप्रेस-वे है। दिल्ली से मुम्बई के बीच 1320 किमी लम्बा एक्सप्रेस-वे बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा देश में 6 आर्थिक कॉरिडोर प्रस्तावित हैं।

इस कालखंड को देश में ढांचागत परिवर्तन के नवयुग की शुरुआत वाला कहा जा सकता है। सड़क निर्माण को नये स्तर पर ले जाने के साथ हम लाजिस्टिक को नया आयाम दे रहे हैं। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे लाजिस्टिक विकास का बेहतर मॉडल बनेगा। इस एक्सप्रेस-वे में बिजली से ट्रक, बस चलाने की योजना भी है। एक्सप्रेस-वे के किनारे ऐसा ढांचा तैयार करने की योजना है, जिससे अनाज, फल और स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं को आसानी से एक राज्य के दूसरे राज्य तथा देश के बाहर भेजा जा सके। पिछले एक साल में साढ़े तीन लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। 2014 से 2019 के बीच साढ़े पांच लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं का काम शुरू हो चुका था। 2014 से पहले पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण सड़क क्षेत्र धन के अभाव से

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई एक लाख 50 हजार किमी पहुंच गई है। हम इसे दो लाख किमी करने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। हम सिर्फ सड़क नहीं बना रहे, बल्कि पिछड़े, वनवासी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं।

जूझ रहा था। छह लाख करोड़ से ज्यादा के काम अटके पड़े थे। सरकार और कम्पनियों के बीच अविश्वास की ऐसी खाई तैयार हो गई थी, जिसे पाटना आसान नहीं था। बड़ी कम्पनियां काम से पीछे हट गई थीं। मंत्रालय के अधिकारियों, बैंकर, कम्पनियों के बीच समन्वय बनाकर समस्याओं को न केवल हल किया गया, बल्कि विश्वास का ऐसा वातावरण तैयार किया कि सड़क निर्माण से पीछे हटने वाली कम्पनियां आगे आईं और कर्ज देने से हाथ खींच लिए बैंकों ने भी सहयोग का कदम बढ़ाया। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई एक लाख 50 हजार किमी पहुंच गई है। हम इसे दो लाख किमी करने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। हम सिर्फ सड़क नहीं बना रहे, बल्कि पिछड़े, वनवासी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। पर्यटन, धार्मिक स्थलों को बेहतर सम्पर्क उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। चारधाम परियोजना, रामवनगमन मार्ग, कैलाश मानसरोवर मार्ग, बौद्ध सर्किट का निर्माण उसी का हिस्सा है। वह दिन दूर नहीं जब हम उत्तराखंड से मानसरोवर जा सकेंगे। जम्मू से श्रीनगर की दूरी कम करने के साथ सभी मौसम में लोग लद्दाख तक जा सकेंगे। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली 10 किमी लम्बी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी (चेनानी नाशरी) सुरंग मार्ग बनने के बाद अब लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला सुरंग मार्ग का काम जल्द शुरू होने वाला है।

हमारी सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक पारित करके कई मसलों में पारदर्शिता लाने का काम किया है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आम जनता को अनावश्यक परेशानी से राहत मिली है तथा मनमाने तरीके से वाहन चलाने वालों में अनुशासन आएगा। देश में वाहन की रफ्तार बढ़े, दुर्घटना में कमी आए, वाहन प्रदूषण की समस्या हल करने की दिशा में भी हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम देश में ई-वाहन को बढ़ावा दे रहे हैं। दो पहिया, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसी तरह ट्रक, बस को जैविक ईंधन में बदलने के लिए भी हमारा मंत्रालय प्रोत्साहित कर रहा है। ग्रीन मोबिलिटी लाभकारी विकल्प है। इसमें ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी के साथ पेट्रोलियम पदार्थ की जगह पर यह ईंधन सस्ता पड़ता है। हमारा उद्देश्य देश पर हर साल 6 लाख करोड़ के पेट्रोलियम पदार्थ के आयात के बोझ को कम करना है। हमने नागपुर में टायलेट के पानी से गैस निकालकर उससे वाहन चलाने का सफल प्रयोग किया है।

नागपुर में एक हजार इलेक्ट्रिक टैक्सी, आटो चल रहे हैं। हम अब विदर्भ को ग्रीन एनर्जी में बदलने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि देश के सभी शहर अपने यहां के टायलेट के दूषित जल से गैस निकालकर उससे वाहन चलाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

हमें हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद दुनिया हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। बिजली, पानी की प्रचुरता वाले हमारे देश में आने के लिए कई कम्पनियां आतुर हैं। उन्हें देश के नेतृत्व, सत्ता व्यवस्था के प्रति विश्वास है। यह विश्वास सरकार के पारदर्शी कामकाज के कारण हासिल हुआ है। देश परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जो स्वर्णिम भारत का नवनिर्माण करेगा। ■

(लेखक केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री हैं)

सामाजिक न्याय और मोदी सरकार 2.0

डॉ. थावरचंद गहलोत

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज से 6 वर्ष पूर्व 2014 में मुझे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री का दायित्व दिया, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानते हुए इसे सेवा के कार्य के रूप में लिया। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को न केवल जीवंत बनाया गया, बल्कि कार्यों के अनेक कीर्तिमान भी स्थापित किये गये हैं। मंत्रालय मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित है 1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।

दोनों ही विभाग शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन जैसे समाज के लाभवंचित और आर्थिकविहीन वर्गों, वृद्धजनों और मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित आदि के सशक्तिकरण का लक्ष्य रखता है ताकि उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन का अधिकार दिया जा सके तथा उनकी उन्नति और विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगी तथा स्वतंत्र जीवन द्वारा उन्हें सहायता साथ ही समान के अन्य लाभवंचित और अधिकारहीन वर्गों के लिए पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया गया। साथ ही, कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है और योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए एक मजबूत कार्यपद्धति अपनाई गई है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया किया जाता है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में 2014-15 में 1800 करोड़ रुपये से 2018-19 की अवधि के दौरान लगभग 3250 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इसमें कुल 60 लाख बच्चों को लाभ मिल रहा है।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगी तथा स्वतंत्र जीवन द्वारा उन्हें सहायता साथ ही समाज के अन्य लाभवंचित और अधिकारहीन वर्गों के लिए पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया गया।

कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की पात्रता को संशोधित कर वर्ष 2017 में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया। साथ में, छात्रवृत्ति की दरों में भी 50% की वृद्धि की गई। वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व विषय को समाप्त कर दिया गया और केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात रखा गया। पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में यह शेयरिंग अनुपात 90:10 है। तद्नुसार, वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य स्कीम पर वार्षिक रूप से व्यय किए गए 300 करोड़ रुपए औसत की तुलना में 2020-21 का बजट अनुमान 700 करोड़ रखा गया है।

एससी छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा स्कीम के अंतर्गत चयनित 220 उत्कृष्ट संस्थाओं के प्रतिभावान पात्र एससी छात्रों को उनके अध्ययन हेतु फीस, रहने और खाने तथा कंप्यूटर/लैपटॉप और अन्य सहायक सामग्रियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। व्यय और लाभार्थियों की संख्या जो 2009-14 में क्रमंशः 78.11 करोड़ रुपए तथा 5716 थी, वह 2014-19 में दुगनी होकर क्रमशः 164.39 करोड़ रुपए तथा 9544 हो गई। वर्ष 2018-19 में पात्रता हेतु वार्षिक पारिवारिक की उच्चतम सीमा को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत रोजगार और उच्चतर शिक्षा, दोनों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु स्कीम के अंतर्गत 2009-14 के दौरान कुल 13.10 करोड़ रुपये जारी किए गए जो 2014-19 की अवधि में बढ़कर 48.33 करोड़ हो गए। इसी अवधि में लाभार्थियों की संख्या 6126 से दुगनी होकर 13473 हो गई।

शिक्षा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान संबंधी केंद्रीय क्षेत्र योजना का मुख्य उद्देश्य, सरकार के विकास संबंधी हस्तक्षेप तक पहुंच बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा रहित अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में व्याप्त कमियों को दूर करना है। सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए प्रदान की जाती है।

डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए यह योजना 2009 में शुरू की गई, जिसे 2014 तक 272 लोगों लाभ मिला था जबकि 2014 से 2020 से

1029 लोगों को लाभ मिला है।

अनुसूचित जातियों का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना (एससीएसपी के लिए एससीए) का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों में आय सृजन योजना, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा अवसंरचना विकास के माध्यम से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की आय में वृद्धि करना है। 2009 से 2014 तक की अवधि के दौरान, वार्षिक रूप से औसत खर्च किए गए 701 करोड़ रुपए की तुलना में 2014-2020 के दौरान वार्षिक रूप से औसत 827.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए है। तदनुसार, 2020-21 के लिए बजट अनुमान में 1200 करोड़ रुपए तक की वृद्धि भी की गई है।

अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती वित्त प्रदान के लिए 200 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से वैचर कैपिटल योजना की शुरुआत दिसम्बर 2015 में की गई थी और इस योजना के तहत फरवरी 2020 तक 107 अनुसूचित जाति उद्यमियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृति की जा चुकी है।

इस प्रकार ओबीसी का आर्थिक विकास के लिए बीसी के लिए 2017-18 में आरंभ हुई योजना और इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के रोजगार सृजन के लिए उन्हें रियायती वित्त प्रदान करने के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों में से उद्यमियों को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, देखभाल और उनके कल्याण तथा स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है।

नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मंत्रालय ने वर्ष 2018 के दौरान भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग के बारे में पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया है। सरकार के पास अब नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं जिनका उपयोग नशीली दवा की मांग में कटौती करने के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2018-2025 की अवधि के लिए नशीली दवा की मांग में कटौती करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के निवारण, उपचार और पुनर्वास के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से नशीली दवा के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों में कटौती करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से आज की तारीख तक 219.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए एनएपीडीडीआर के अंतर्गत 260 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

देश में कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण अभी देश लगभग तीन महीने से पूर्णरूप से बंद है। जिसका नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई हैं, जिस कारण मंत्रालय की नशामुक्ति हेल्पलाइन पर पहले की तुलना में भी कई गुना अधिक कॉल आई हैं और इनके निवारण के लिए मंत्रालय ने देशभर में फैले नशा मुक्ति केंद्रों पर विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउंसलिंग की जा रही है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये हमने विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं की शुरुआत की है तथा कुछ योजनाओं में नीतिगत बदलाव भी लाए गये हैं ताकि इन योजनाओं का सही प्रकार से अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वयन किया जा सके। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु हमारी सरकार बजट प्रावधानों में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है।

भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास हेतु वर्ष 2017-20 में इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) को भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु 3.2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वर्ष 2020-21 के लिए भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए एक नई योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बचने के लिए मंत्रालय में विशेष तौर पर सौ करोड़ रुपये की राशि देश के विभिन्न ज़िलों को आवंटित किया है। जिससे वे भिक्षावृत्त में लिप्त लोगों को भोजन सामग्री या अन्य ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके।

हमारा यह मानना है कि दिव्यांगजन मानव संसाधन का एक अभिन्न अंग है। उनके लिए समावेशी समाज तथा उनके सशक्तिकरण हेतु हमारी सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने PWDs को 'दिव्यांगजन' संबोधित करते हुए उनको एक नई पहचान दी, जो आज उनके गौरवमय जीवन का प्रतीक बन गयी है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये हमने विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं की शुरुआत की है तथा कुछ योजनाओं में नीतिगत बदलाव भी लाए गये हैं ताकि इन योजनाओं का सही प्रकार से अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्यान्वयन किया जा सके। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु हमारी सरकार बजट प्रावधानों में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है। 2013-14 में 560.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जबकि इस वितीय वर्ष में 1204.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2013-14 के तुलना में दो गुणा से भी अधिक है।

आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के कारण कठिन दौर से गुजर रहा, जिसका प्रभाव भारत पर भी गंभीर रूप से पड़ा है और जिसकी सर्वाधिक मार देश के गरीब, वरिष्ठजन, दिव्यांग इत्यादि पर अधिक पड़ा है। पर इस कठिन समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रालय लगनपूर्वक कार्य कर अपनी सभी योजनाओं का लाभ इस जरूरत के समय में मिलें, इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। ■

(लेखक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं।)

जनजातीय कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार

अर्जुन मुंडा

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1999 में देश में अनुसूचित जनजाति समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए एक समन्वित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के उद्देश्य से की गई थी। श्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जस्वी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 2.0 के प्रथम वर्ष में मेरे मंत्रालय द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं-

1. प्रधानमंत्री वन धन योजना:

लघु वन उत्पाद के जनजातीय संग्रहकर्ताओं के बीच आजीविका सृजन के लिए पिछले एक वर्ष में लगभग 1205 वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जिनसे 3.70 लाख लाभार्थियों को लाभ होने की उम्मीद है। 18075 स्वयं सहायता समूह बनाए गए और 166 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

नागालैंड राज्य के टोबू तहसील, मोन जिले में वन धन कार्यक्रम के तहत झाड़ू बनाने के उपक्रम।

2. लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य:

जनजातीय समुदायों को कोविड महामारी द्वारा पैदा हुई कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा एमएफपी के रूप में वर्गीकृत 50 वस्तुओं के एमएसपी को इस वर्ष 1 मई को संशोधित कर बढ़ाया गया है। परिणामस्वरूप, मूल्य संशोधन के पखवाड़े के भीतर 17 राज्यों में 40 करोड़ रुपये के एमएफपी की खरीद की गई है।

3. जनजातीय शिक्षा:

मेरे मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ने देश भर में इस वर्ष 69 विद्यालय संचालित किए जाने और नए 100 विद्यालय स्वीकृत किए जाने के साथ एक अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। आज की तिथि के अनुसार, करीब 73,000 नामांकन के साथ 285 ऐसे स्कूल हैं, जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता बालकों और बालिकाओं के बीच 50:50 का अनुपात है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले जनजातीय छात्रों के लिए, पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 32 लाख लाभार्थियों को 4 अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से 2400 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की है।

कुछ विशेष पहलें जैसे महाराष्ट्र में कायापलट अभियान, जो 502 आश्रम विद्यालयों के 2.50 लाख छात्रों को लाभान्वित करता हैं, मध्य प्रदेश में कन्या शिक्षा परिसर को मजबूत करने और छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रयास आवासीय विद्यालय को पिछले एक वर्ष में मंत्रालय द्वारा 4.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

4. सर्वांगीण विकास और सुशासन के उपाय:

सार्वजनिक भवन, सड़क, स्कूल, लघु सिंचाई सुविधाएं, सौर प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सहित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1600 करोड़ रुपये की निधि राज्यों को वितरित की गई है। फरवरी, 2020 में यूएनडीपी के सहयोग से अनुसूचित जनजाति समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया।

> **लघु वन उत्पाद के जनजातीय संग्रहकर्ताओं के बीच आजीविका सृजन के लिए पिछले एक वर्ष में लगभग 1205 वन धन केंद्र स्थापित किए गए, जिनसे 3.70 लाख लाभार्थियों को लाभ होने की उम्मीद है।**

5. जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना:

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना में अंतरों को कम करने के लिए बहुमुखी प्राथमिक जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल मॉडल पर आधारित एक 'जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना' कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहलें:

मेरे मंत्रालय को केंद्र द्वारा प्रायोजित मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के लिए डीबीटी पोर्टल (dbttribal.gov.in) विकसित करने के लिए प्रथम विशिष्ट स्थान हासिल है। विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के 45 लाख लाभार्थियों का डेटा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) और समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाएं, सत्यापन की सुविधा के लिए 'डिजी लॉकर टूल' के साथ एकीकृत कर दी गई हैं।

7. जनजातीय संस्कृति और अनुसंधान:

जनजातीय संस्कृति और ज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए, सभी शोध पत्रों, पुस्तकों, रिपोर्टों और दस्तावेजों, लोक गीतों, फोटो और वीडियो के लिए एकनिष्ठ संदर्भ (one point reference) सेवा के रूप में, एक अन्वेषण योग्य डिजिटल जनजातीय संचित कोश (http:// repository.tribal.gov.in) की परिकल्पना की जा रही है।

मंत्रालय ने अनेक राज्यों जैसे मिज़ोरम में पावल कुट, नागालैंड में हॉरबिल उत्सव, तेलंगाना में मेदराम जथारा जैसे जनजातीय उत्सवों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है जबकि ट्राइफेड ने दिल्ली सहित देश भर के 17 राज्यों में 'आदि महोत्सव' के नाम से उत्सव आयोजित किए हैं।

8. जनजातीय चिकित्सक और जनजातीय चिकित्सा :

जनजातीय चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पहल के तहत मंत्रालय का लक्ष्य एक केंद्रीकृत ज्ञान केंद्र (Hub) बनाने का है। उसी के भाग के रूप में, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड को एक नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। एम्स-जोधपुर, पतंजलि अनुसंधान संस्थान, प्रवर चिकित्सा विज्ञान संस्थान और माता अमृतानंदमयी संस्थान को, पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा तकनीकों के अभिलेखीकरण और संरक्षण की कार्य परियोजनाएं भी सौंपी गयी हैं।

9. 'गोल' पहल :

मंत्रालय ने फेस बुक इंडिया के साथ साझेदारी में 'गोल - गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स' नामक कार्यक्रम के रूप में एक अनूठी पहल की जिसका उद्देश्य देश भर के लगभग 5000 उन जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षार्थी (मेंटी) के रूप में नामांकित करना है, जो 7 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षकों (मेंटर) द्वारा डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व जैसे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किए जाएंगे जिसके पश्चात् प्रमुख संगठनों के साथ 2 महीने की इंटर्नशिप होगी। आशा की जाती है कि इस पहल से जनजातीय युवाओं में डिजिटल साक्षरता का अंतर कम होगा और वे सशक्त होंगे। ■

(लेखक केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं)

भारत के भविष्य की आधारशिला

प्रकाश जावडेकर

मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान इस देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। यह उनके दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष है जो पूरा हो गया है। यह वर्ष कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा। मोदी सरकार के कामों को मुख्यतः तीन-आयामी गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। पहला, कुछ ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल। दूसरा, कोविड-19 से लड़ना और तीसरा, "आत्मनिर्भर भारत" के माध्यम से भारत के भविष्य के लिए एक आधारशिला रखना।

धारा 370 का निरस्तीकरण, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर अस्तित्व में आना, नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करना, ट्रिपल तलाक कानून और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को सरकार की राष्ट्रीय और ऐतिहासिक राजनीतिक पहलों के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद से कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। अब, यहां पर इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है। हमारी सेना पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान 50 वर्ष से अधिक पुराने बोडो संकट को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौता किया गया और समाज के सभी वर्ग इस समझौते से बेहद खुश हैं। इसी तरह त्रिपुरा, भारत सरकार और मिजोरम के बीच त्रिपक्षीय समझौते से ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को सफलतापूर्वक हल किया गया है। इसके अलावा इस एक वर्ष में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान किया गया जिसको एक प्रमुख सामाजिक पहल की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है; गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) विधेयक, 2020; सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2020 और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण प्रदान करने वाले कानून में संशोधन किया गया।

कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमने सबसे लंबा और बहुत सख्त लॉकडाउन लागू किया, जिसके कारण इस बीमारी से देश को न्यूनतम क्षति को सुनिश्चित किया गया। कई क्षेत्रों में हमारी क्षमता पूर्ण नहीं थी। हमारे पास कोई भी कोविड अस्पताल नहीं था। लेकिन अब हमारे पास 800 से अधिक अस्पताल हैं। हमारे पास परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला थी और अब हमारे पास 300 से अधिक हैं। पीपीई सूट, मास्क और यहां तक कि स्वाब स्टिक को भी आयात किया जा रहा था। इनको लेकर भी अब हम आत्मनिर्भर बन गए है और अब यह सभी 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में ही वेंटिलेटर का उत्पादन भी किया जा रहा है। 165 डिस्टलरी और 962 निर्माताओं को हैंड सैनिटाइटर बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 87 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ का स्वास्थ्य पैकेज और 11,000 करोड़ रुपए राज्य आपदा राहत कोष के लिए जारी किए। कोविड के खिलाफ लड़ाई में 3000 वाहनों के माध्यम से लगभग 45 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों वापिस भेजा गया। विदेशों में फंसे हजारों भारतीय निवासियों को सफलतापूर्वक स्वदेश लाया गया।

> **धारा 370 का निरस्तीकरण, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर अस्तित्व में आना, नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करना, ट्रिपल तलाक कानून और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को सरकार की राष्ट्रीय और ऐतिहासिक राजनीतिक पहलों के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद से कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। अब, यहां पर इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है।**

मोदी जी हमेशा जनसामान्य की चिंता करते हैं। इसलिए सरकार के पहले पैकेज में उन्होंने 80 करोड़ परिवारों को खाद्य सुरक्षा कवर दिया, जिसके तहत इन परिवारों को 25 किलो चावल/गेहूं और 5 किलो दालें मुफ्त (पांच महीने के लिए) दी जा रही हैं। यह योजना पूर्ववर्ती योजना जिसमें अत्यधिक रियायती दरों यानी 2-3 प्रति किलो की दर से प्रति महीने 5 किलो गेहूं/चावल दिए जा रहे हैं, के साथ जारी रहेगी। लगभग 5 करोड़ गैर-राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने दो महीने के लिए 10 किलो मुफ्त चावल/गेहूं और 2 किलो दाल प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इसके अतिरिक्त 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इसके तहत इन महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये (500 x 3) दिये जा रहे है। 8 करोड़ परिवारों को 2000 रुपए के 3 गैस सिलेंडर दिए गए है। लगभग 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की सहायता दी गई है। 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपए दिये जा रहे है। निर्माण श्रमिकों के फंड से लाखों श्रमिकों को सहयोग दिया गया है। यदि कोई गणना करता है, तो हमारे समाज के निचले तबके के 10% परिवारों को 10,000 रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं।

इस विकास क्रम का तीसरा भाग है, 'आत्मनिर्भर' पैकेज के माध्यम से प्रमुख सुधारों को लागू करना। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग हैं। यह एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, जो जीडीपी का 10% है। यह समाज के हर वर्ग को छूता है। ईपीआई के योगदान में नियोक्ता और कर्मचारी

दोनों को छूट मिल रही है। छोटे और मझोले उद्योगों को ऋणों पर 2% ब्याज उपदान दिया गया है। 63 लाख स्व-सहायता समूहों को 20 लाख रुपये तक संपाश्विर्क मुक्त ऋण मिलेगा जो पहले 10 लाख रुपये तक सीमित था।

छोटे और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली गई है, जिससे अधिक कंपनियों को इसका लाभ मिल सकें। लघु एवं मध्यम उद्योगों और एनबीएफसी के लिए 4,45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया हैं। कृषि-अवसंरचना कार्यक्रमों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये, साथ ही मत्स्य विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये और मवेशियों की आबादी में पैर और मुंह की बीमारी के टीकाकरण और उपचार के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

> **छोटे और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली गई है, जिससे अधिक कंपनियों को इसका लाभ मिल सकें। लघु एवं मध्यम उद्योगों और एनबीएफसी के लिए 4,45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया हैं। कृषि-अवसंरचना कार्यक्रमों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये, साथ ही मत्स्य विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये और मवेशियों की आबादी में पैर और मुंह की बीमारी के टीकाकरण और उपचार के लिए 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।**

इस पैकेज में प्रमुख सुधार किए गए हैं। जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, एक ऐतिहासिक पहल है। अभी तक हम 100 प्रतिशत हथियार आयात कर रहे थे, लेकिन रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दे रहे थे। मोदी जी ने देश को इस पाखंड से बाहर निकाला और रक्षा उत्पादन में 74% एफडीआई की अनुमति दी और साथ भारत में निर्मित रक्षा पुर्जों और हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। मनरेगा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो एक अच्छी पहल है। मनरेगा जरूरतमंदों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और वर्तमान प्रवासी श्रमिकों के पलायन को देखते हुए यह कदम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इन श्रमिकों के पलायन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों की अधिक मांग होगी। यूपीए सरकार ने कभी भी मनरेगा पर 37,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च की सीमा को पार नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में मनरेगा पर औसतन रुपए 55,000 करोड़ खर्च किए है। अब हमने इसे लगभग दोगुना कर 1,00,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मोदी सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। वहीं उद्योगों और कर दाताओं के संदर्भ में भी कई सुधारों और रियायतों को लागू किया गया है।

अन्त में, इस पैकेज की प्रमुखता कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार है। किसानों को एपीएमसी से मुक्त कर दिया गया है। वे अपनी पसंद से अब कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। वे अपने कृषि उत्पाद को बेचने के लिए किसी से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के कई किसान विरोधी प्रावधानों से राहत दी गई है। अब किसानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगी, और वह बाजार से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें।

'आत्मनिर्भर' पैकेज भारत का भविष्य तय करेगा। यह दूरदर्शी, ऐतिहासिक और विवेकपूर्ण है। ■

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं)

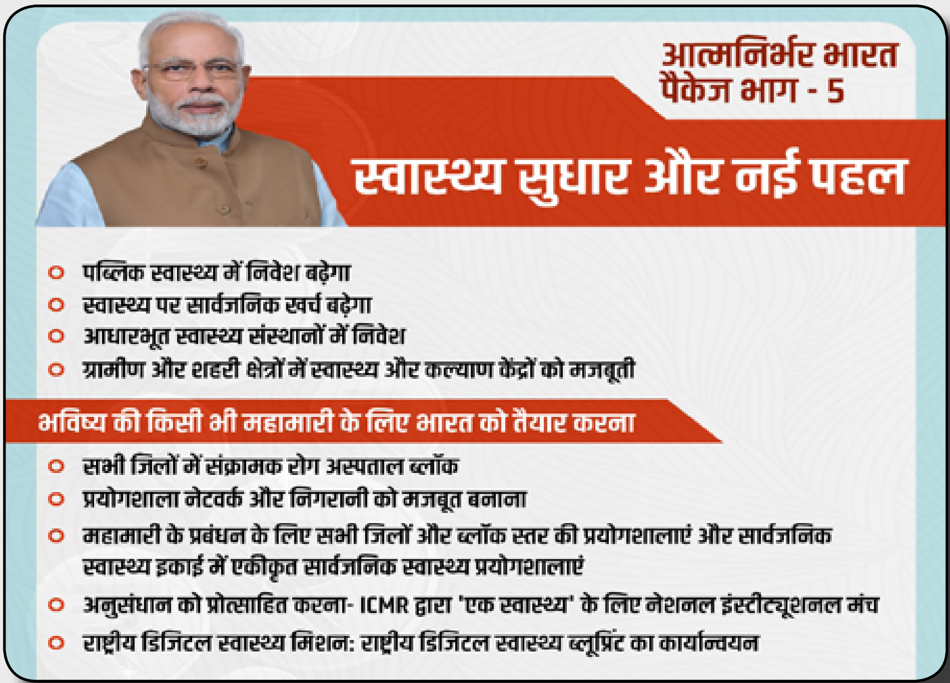

साहसिक नेतृत्व का 'ऊर्जावान' कार्यकाल

धर्मेन्द्र प्रधान

23 मई 2019 को 17वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, जिसमें देश ने अपने यशस्वी जननायक श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अभूतपूर्व व प्रचंड बहुमत से पुनः देश की बागडोर सौंपी। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीटों व गठबंधन को 353 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। देश के राजनीतिक इतिहास में किसी दल व उसके कार्यकर्ताओं के लिए यह असाधारण उपलब्धि है। मोदी सरकार-2.0 को मिला यह जन-समर्थन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार के हर निर्णय में परिलक्षित होती रही है। विदित हो कि पिछले वर्ष मई माह में ही ओडिशा में फैनी चक्रवात ने किस कदर तबाही मचाई थी। सामान्यतः चुनाव परिणाम से ठीक पहले हर दल का राजनीतिक नेतृत्व सरकार बनाने, उसके पूर्वानुमानों के विश्लेषण आदि में व्यस्त रहता है, लेकिन अंतिम चरण की चुनावी व्यस्तताओं को छोड़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के चक्रवात प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाने के कार्य को प्राथमिकता दी। कुछ इसी तरह हाल के दिनों में अम्फान महाचक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सामने आए दोहरे संकट के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों का दौरा कर वहां राहत कार्यों का जायजा लेते हुए क्रमशः 1 हज़ार करोड़ और 500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील व्यक्तित्व का वह पहलू है, जो देश के हर जाति, पंथ, क्षेत्र और व्यक्ति के साथ अपनत्व विकसित करता है। मोदी सरकार ने विगत छह वर्षों में लोक कल्याण से जुड़े ऐसे अनेक निर्णय लिये, जिनसे 'एकात्म मानववाद' का दर्शन 'अन्त्योदय' के लक्ष्य की साधना के रूप में लोक सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में फलीभूत हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देशवासियों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भान जगाना हो, योग को विश्व के कोने-कोने में स्थापित करना हो या समाज के अंतिम व्यक्ति को आवास, ईंधन, जन-धन खाते और इलाज की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास की ऐसी अवधारणा विकसित की, जिसने जन कल्याणकारी राजनीति की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का कार्य किया है।

किसी भी सरकार के मात्र एक वर्ष के कार्यकाल को परखने की पद्धति विश्व के किसी भी लोकतंत्र में शायद नहीं होगी, किन्तु साख पर आधारित राजनीति करने वाली मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के हर दिन का लेखा-जोखा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। अपने दूसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने जनता द्वारा जताए गए अप्रतिम भरोसे को पूरा करने के लिए मात्र एक वर्ष में जिस प्रकार राष्ट्रहित में निर्णय लिए हैं, उससे विश्व में भारत प्रतिष्ठा बढ़ी है। अपने राजनीतिक नफ़े-नुकसान को इतर रख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मोदी सरकार-2.0 ने अनुच्छेद 370 व 35-A को समाप्त कर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की जन आकांक्षाएं पूर्ण किया, तो वहीं, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर बांग्लादेश घुसपैठ रोकने के साथ आतंकवाद के पोषण पाकिस्तान में दयनीय जीवन जी रहे अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख और पारसी समाज के लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान करने का मानवीय निर्णय लिया। इसी तरह तीन तलाक जैसे बर्बर कानून को समाप्त कर सरकार ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ हो रहे उस भेदभाव को समाप्त किया, जिसे कई पीढ़ियों से सहन करने के लिए मुस्लिम समाज की महिलाएं अभिशप्त थीं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने पहले कार्यकाल में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को जहां रफ्तार देने का कार्य किया। वहीं 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' के मकसद से 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की संख्या 8 करोड़ 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। देश के बड़े शहरों के साथ छोटे और कस्बाई इलाकों को भी सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में हमने सीजीडी के 10वें राऊंड की निविदा प्रक्रिया के साथ बड़ी छलांग लगाई है। सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए शहरों में जगह-जगह कुकिंग फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 हज़ार सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था गैस का अनुपात बहुत कम था, लेकिन इस दिशा में हमने तेजी से कदम बढ़ाया है। 10वें चरण की बोली प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् देश की लगभग 70 फीसदी आबादी सिटी गैस नेटवर्क से जुड़ जाएगी। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण बढ़ाने के लिए 4.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रक्रियाधीन है। इससे 2030 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी दोगुनी होगी, जिससे उपभोक्ताओं

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार ने पहले कार्यकाल में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को जहां रफ्तार देने का कार्य किया। वहीं 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' के मकसद से 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों की संख्या 8 करोड़ 50 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है।

को सस्ती व सुलभ ऊर्जा मिलेगी एवं पर्यावरण को लेकर हम अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकेंगे। ख़ास बात यह है कि भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व एक बार पुनः वही पूर्वी भारत करने को तत्पर है, जो कभी ऊर्जा, खनिज व मानव संसाधन के साथ अपनी गौरवशाली संस्कृति से देश की आर्थिक तरक्की को अनुप्रमाणित करता रहा है, किन्तु बीच के कालखंड में सरकारों की उदासीनता के कारण इस क्षेत्र की पहचान पिछड़े व बीमारू भू-भाग के रूप मे होने लगी। मोदी सरकार-2.0 द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन पूर्वोदय 102 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना प्रगति पर है, इससे देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद मिलेगी। देश में 2030 तक 300 इस्पात निर्माण संयंत्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे देश में प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग को मौजूदा 70 किलोग्राम से बढ़ाकर 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य भी पूरा होगा। इससे स्टील सेक्टर के छोटी और मझोली इकाइयों को काफी लाभ होगा और वह नए रोजगार भी सृजित करेंगी।

मोदी सरकार ने विगत छह वर्षों से जिस प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उसका साक्षात्कार देश कोरोना त्रासदी के दौरान भी कर रहा है। विश्व के तमाम कोविड-19 प्रभावित देशों से अर्जित अनुभव के आधार पर जिस प्रकार समय रहते लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसने आज भारत को कोरोना की जंग में विश्व में एक रोल मॉडल देश के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर देश ने लॉकडाउन के दौरान जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया, वह अपने नेतृत्व की क्षमता के प्रति गहरे भरोसे का प्रतीक है। मोदी सरकार-2.0 ने कोरोना संकट से उत्पन्न विभीषिका से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अलावा अन्य मौद्रिक प्रयासों से प्रवासी श्रमिक, खेतिहर मज़दूर के साथ मध्यम वर्ग व देश के आर्थिक विकास को अपने सामर्थ्य से सींचने वाले उद्योग जगत के लिए विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक राहत कार्यक्रम शुरू किया है। यहां प्रधानममंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीन निःशुल्क सिलेंडर व डीबीटी के जरिए उन्हें दी जा रही सरकारी मदद का जिक्र प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने अभावग्रस्तों तक सरकारी राहत को त्वरित गति से पहुंचाने में न सिर्फ मदद की है, बल्कि सरकार के लिए राहत कार्यों को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभरी है। लॉकडाउन-04 से पहले 6 करोड़ 92 लाख हितग्राहियों को रसोईं गैस उज्ज्वला सिलेंडर व हितग्राहियों के बैंक खामों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए 8,432 करोड़ रुपये बतौर सब्सिडी जमा कर विश्व में सबसे बड़े राहत कार्य को संपन्न किया गया है। देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे-जैसे अपना सामाजिक दायरा बढ़ा रही है, उससे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत ऊर्जा की वैश्विक मांग का केंद्र बना रहेगा। अर्थात् विश्व अर्थव्यवस्था में भारत ऊर्जा की मांग और आपूर्ति दोनों का प्रमुख केंन्द्र बनकर उभर रहा है। कोरोना वायरस से उत्पन्न इस भयंकर संकट में भी देश के लिए हर क्षेत्र में नए अवसरों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना दी है, उससे निश्चित ही हमारे शहर ही नहीं गांव भी रोजगार और अवसरों से समृद्धि होंगे। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की जन-सहभागिता, नीतियों की स्वीकार्यता, व मानव केंद्रित उस दृष्टिकोण को जाता है, जो मानव कल्याण के वसुधैव कुटुम्बकम के मंत्र पर आधारित है। एक दौर था जब सरकारों की निष्क्रियता पर आरोप-प्रत्यारोप होते थे, किन्तु मोदी सरकार-2.0 ने उस धारणा को ध्वस्त किया है कि राजनीतिक निर्णय सियासी लाभ व अनुकूल परिस्थितियों को देखकर लिए जाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के प्रति देश के हर नागरिक के मन में आस्था और प्रगाढ़ हो रही है। ■

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं)

समावेशी विकास–सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण मोदी सरकार की नीति

मुख्तार अब्बास नकवी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समावेशी समृद्धि एवं सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की 'राष्ट्रनीति' और शक्तिशाली, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्धि से भरपूर भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हर भारतवासी उसके अभूतपूर्व नेतृत्व और अद्भुत निर्णय क्षमता तथा राष्ट्रहित में किये गए कड़े-बड़े दूरदर्शी फैसलों पर गर्व और गरिमा का एहसास कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील, समावेशी, दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें 'सुशासन एवं समावेशी समृद्धि' का 'प्रामाणिक ब्रांड' बना दिया है।

जहां एक तरफ हर भारतवासी, देश की प्रामाणिक उपलब्धियों और प्रभावशाली नेतृत्व पर गौरवान्वित है वहीं देश की इस शानदार-जानदार उपलब्धियों के सफल सफर से बौखलाया-बदहवास पेशेवर 'मोदी फोबिया क्लब' ने 'इस्लामोफोबिया' कार्ड के जरिये झूठे, मनगढंत तर्कों, तथ्यों से कोसों दूर दुष्प्रचारों के 'पाखंडी प्रयासों' से भारत के शानदार समावेशी संस्कृति, संस्कार और संकल्प पर पलीता लगाने की फिर से साजिशी सूत्र का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया है।

इस 'भारत बैशिंग ब्रिगेड' के 'ज्ञानी अज्ञानियों' को समझना होगा कि जिस देश की संस्कृति-संस्कार और संकल्प 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानी 'सारी पृथ्वी एक कुटुंब (परिवार) के समान है'- साथ ही 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥' यानी सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को दुःख का भागी ना बनना पड़े संकल्प हो। इसी समावेशी सनातन संस्कृति-संस्कार ने जिस विशाल भारत को अनेकता में एकता की मजबूत डोर से जोड़ रखा है, जिसमें मजहब, क्षेत्र, देश से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के सुख-समृद्धि-स्वास्थ्य-सुरक्षा की सीख का समावेश हो। इसी हिंदुस्तानी संस्कार, संस्कृति और संकल्प का परिणाम है कि आजादी के बाद जहां पाकिस्तान ने इस्लामी राष्ट्र का रास्ता चुना, वहीं भारत के लोगों ने 'पंथनिरपेक्ष जनतांत्रिक' राष्ट्र का मार्ग चुना। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 24 प्रतिशत से ज्यादा थे, लेकिन आज 2 प्रतिशत के इर्द-गिर्द बचे हैं। वहीं बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत थे वह बढ़कर 22 प्रतिशत से भी अधिक हो गए हैं। सभी नागरिकों के साथ अल्पसंख्यक भी बराबर की हिस्सेदारी-भागीदारी के साथ फल-फूल रहे हैं। उस देश और उसके नेतृत्व के खिलाफ दुष्प्रचार, 'अज्ञानता और मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा' से ज्यादा कुछ नहीं है।

अफ़सोस की बात है कि कुछ लोगों की 'छद्म सेक्युलर सियासी सनक' ने देश की पंथनिरपेक्षता को मुस्लिम या अल्पसंख्यकों का 'पेटेंट पॉलिटिकल प्रोडक्ट' बनाकर भारत के समावेशी संस्कार का बड़ा नुकसान करने की कोशिश और साथ ही भारतीय मुसलमानों को प्रगति की धारा से दूर करने का समझा-बूझा पाप भी किया है।

आज फिर से ऐसे ही 'साजिशी सियासी सनक से सराबोर' लोग भारत को बदनाम करने और हिंदुस्तान की 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया' के संकल्प पर चोट पहुंचाने की घटिया साजिश में लग गए हैं। यह वो लोग हैं जो श्री नरेंद्र मोदी के परफॉरमेंस, परिश्रम एवं देश की समावेशी प्रगति को हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये हताश आत्माएं 2014 से एक दिन भी चैन से नहीं बैठी, कभी भारत में असहिष्णुता, तो कभी साम्प्रदायिकता, तो कभी भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और भेदभाव के झूठे मनगठंत किस्से कहानियां देश-विदेश में प्रचारित करते रहे।

इस 'मोदी बैशिंग क्लब' की परेशानी ये है कि 2014 के बाद उनके दुष्प्रचार और परोसे गए सारे तर्क, वक्त की कसौटी पर खोटे और फर्जी ही नहीं साबित हुए, बल्कि औंधे मुंह गिर भी गए। इनका कुतर्क था कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही इस्लामी देशों से भारत के रिश्ते बिगड़ जायेंगे, ईसाई प्रभाव वाले देश भारत से अपना मुंह मोड़ लेंगे, भारत सांप्रदायिक दंगों की आग में धू-धू करेगा, अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार चकनाचूर हो जायेंगे।

पर ठीक उसके विपरीत हुआ, इस्लामी देशों के साथ मोदी जी के कार्यकाल में आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा दोस्ताना और करीबी रिश्ते बनें, यूरोपियन एवं अफ्रीकी देश भारत के और नजदीक आये, यही नहीं सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, अफगानिस्तान, रूस, फिलिस्तीन, मालदीव, मॉरीशस आदि देशों ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नवाजा। इसके अलावा श्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'चैंपियंस ऑफ़ दी अर्थ अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'ग्लोबल स्वीकार्यता, लोकप्रियता' किसी के प्रमाण-पत्र की मोहताज नहीं है।

रही बात कि मोदी शासन में भारत के सांप्रदायिक दंगे की आग में धू-धू जलने के लफ्फाजी की, तो हकीक़त यह है पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, दिल्ली में हाल ही में हुए दंगे से पहले शाहीन बाग़ धरने के समय एक मैसेज तेजी से वायरल किया गया था कि 'मोदी कहते हैं.. उनके दौरे हुकूमत में एक भी दंगा-फसाद नहीं हुआ, हमें इस गुरुर

को चकनाचूर करना है'.. और उसके बाद दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत के सभी अंगों को लहूलुहान कर दिया। कुछ लोग अपने कुतर्कों, दुष्प्रचारों को न्यायोचित ठहराने की साजिशी सनक में इतना गिर जायेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता।

शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता, पर यह भी सच है कि उन्हें 'गुमराही गैंग' ने अपने मकसद के लिए गुमराह किया और ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां 'एंट्री गेट' तो था पर 'एग्जिट गेट' नहीं। या यह कह सकते हैं कि इन बेचारी महिलाओं को 'एंट्री गेट' पर धक्का दे कर इस 'साजिशी सिंडिकेट' ने 'एग्जिट गेट' पर ताला लगा दिया।

इस साजिश का ताना-बाना बहुत ही सोची-समझी आपराधिक सोच के साथ बुना गया- 'बोगस बैशिंग ब्रिगेड', श्री नरेंद्र मोदी एवं भारत को बदनाम करने की 'सनक और साजिश' में बेगुनाहों की लाशों के ढेर पर अपनी कामयाबी का ढोल पीटना चाहती थी, दुनिया को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि 'देखो.. जो हमने कहा था वह सच निकला'। जांच एजेंसियां इस खतरनाक खूनी साजिश के तह तक पहुंच रही हैं और इसके परदे के पीछे और सामने के गुनहगारों को कानून ऐसा सबक सिखाएगा कि वो दोबारा ऐसा इंसानियत को लहू-लुहान करने की साजिश का सपना भी देखें, तो उनकी रूह कांप जाये।

इस ब्रिगेड में शामिल बहुत से लोग उसी 'विरासत के वारिस' हैं जिन्होंने कांग्रेस के समय में भिवंडी से भागलपुर, मलियाना से मालेगांव तक हुए 5 हजार से ज्यादा कत्लेआम पर ना कभी सवाल उठाया ना कभी कहीं शिकायत की, क्योंकि यह सब जिस दौरे हुकूमत में हुआ था उसकी नाल उस 'दरबार के दरबारियों' से बंधी है।

मोदी सरकार ने कभी भी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई या धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर विकास की रुपरेखा नहीं बनाई, उनकी प्राथमिकता गरीब-कमजोर तबका और जरूरतमंद रहा। फिर भी जो लोग 'इस्लामोफोबिया' के नाम पर दुनिया में भारत को बदनाम करने का पराक्रम कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि मोदी कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए क्या हुआ है, जो इससे पहले इनकी 'छद्म सेक्युलर सरकारों' ने नहीं किया या जान-बुझकर इतने बड़े समाज को तरक्की की रौशनी से दूर रख कर उसका 'बेदर्दी-बेशर्मी' के साथ 'सियासी शोषण' करते रहे।

पिछले लगभग 5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय है। देश के 6 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई गई तो 39 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव अंधेरे में जिंदगी बिता रहे थे उनके घरों में उजाला हुआ। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान लाभान्वित हुए।

पिछले लगभग 5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 करोड़ गरीबों को घर दिया तो उसमे 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय है। देश के 6 लाख गांवों में बिजली पहुंचाई गई तो 39 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव अंधेरे में जिंदगी बिता रहे थे उनके घरों में उजाला हुआ। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया, तो उसमे भी 33 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान लाभान्वित हुए।

8 करोड़ महिलाओं को 'उज्ज्वला योजना' के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया तो, उसमे 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों को फायदा हुआ। 24 करोड़ लोगों को 'मुद्रा योजना' के तहत छोटे-मझोले व्यवसाय एवं अन्य रोजगारपरक आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं जिनमें 36 प्रतिशत से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। यह लाभ उन्हें इसलिए मिला कि वो गरीब हैं या उन्हें अभी तक गरीबी के दलदल में सोंची-समझी सियासी सोंच के तहत फेंक कर रखा गया था।

इसके अलावा, 'हुनर हाट', 'गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना', सीखो और कमाओ आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराये गए हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को विभिन्न स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। जिस वजह से विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 72 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत रह गया है जो आने वाले दिनों में जीरो प्रतिशत होगा।

देश भर में वक्फ सम्पत्तियों का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर दिया गया है और शत-प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों के जियो मैपिंग का काम जल्द पूरा हो रहा है। मोदी शासन के 5 वर्षों में भारत से हज यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड 1 लाख 30 हजार से 2 लाख की वृद्धि हुई है। आजादी के बाद पहली बार, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कम्युनिटी सेंटर, विभिन्न आर्थिक-सामाजिक-शैक्षिक गतिविधियों के निर्माण के लिए मोदी सरकार शत-प्रतिशत फंडिंग कर रही है। मोदी सरकार द्वारा देश भर में युद्ध स्तर पर शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगारपरक ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है जिसकी सख्त जरूरत थी।

पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत देशभर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आर्थिक-शैक्षिक-सामाजिक एवं रोजगारपरक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

कराया जिनमें 1512 नए स्कूल भवन; 22514 अतिरिक्त क्लास रूम; 630 हॉस्टल; 152 आवासीय विद्यालय; 8820 स्मार्ट क्लास रूम (केंद्रीय विद्यालयों सहित); 32 कॉलेज; 94 आईटीआई; 13 पॉलिटेक्निक; 2 नवोदय विद्यालय; 403 सद्भाव मंडप (बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र); 598 मार्किट शेड; 2842 स्कूलों में टॉयलेट एवं पेयजल सुविधाएं; 135 कॉमन सर्विस सेंटर; 22 वर्किंग वीमेन हॉस्टल; 1717 विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं; 5 अस्पताल, 8 हुनर हब; 10 विभिन्न खेल सुविधाएं; 5956 आंगनवाड़ी केंद्र आदि का निर्माण शामिल हैं।

वैसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को भी समान रूप से मिल रहा है, फिर भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जो बजट कांग्रेस शासन में 3500 करोड़ रुपए था उसे मोदी सरकार ने 5000 करोड़ से ज्यादा कर दिया है यानी 70 प्रतिशत की वृद्धि। यहीं नहीं, 2014 तक केंद्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी जहां 4 प्रतिशत के इर्द-गिर्द थी, आज मोदी सरकार में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर रही है। प्रशासनिक सेवाओं में भी पिछले 60 वर्षों में सर्वाधिक अल्पसंख्यक समाज के लोग चुने गए हैं, यह सरकार की निष्पक्षता और काबिलियत के कद्र की नीति का नतीजा है।

कोरोना के कहर के दौरान समाज के सभी जरूरतमंदों को लॉकडाउन के बीच 32 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 31 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की गई है। इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी हुआ है।

इस आपदा के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 करोड़ 30 लाख जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया है। इसी दौरान 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलिंडर मुहैया कराये गए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8 करोड़ 30 लाख किसानों को प्रथम किश्त के लिए 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की गयी है।

20 करोड़ महिलाओं के जन-धन अकाउंट में 12 हजार करोड़ रुपए डाले गए हैं। निर्माण कार्यों से जुड़े 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पंजीकृत मजदूरों के लिए 31 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इन सभी का लाभ बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों को भी पहुंचा है।

जब कोरोना का कहर दुनिया में शुरू हुआ था, तब पाकिस्तान सहित और कई देश अपने नागरिकों की सुध नहीं ले रहे थे; तभी मोदी सरकार वुहान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब आदि से बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस देश लायी, इनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। वहीं हाल ही में शुरू किये गए 'वन्दे भारत मिशन' के तहत भी मालदीव,

जब कोरोना का कहर दुनिया में शुरू हुआ था, तब पाकिस्तान सहित और कई देश अपने नागरिकों की सुध नहीं ले रहे थे; तभी मोदी सरकार वुहान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब आदि से बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस देश लायी, इनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। वहीं हाल ही में शुरू किये गए 'वन्दे भारत मिशन' के तहत भी मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, क़तर सहित कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है जिनमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं।

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, क़तर सहित कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है जिनमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं।

हमने कभी समाज के सभी वर्गों के साथ बराबरी से अल्पसंख्यकों के सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक प्रगति के लिए किये गए काम का ढोल नहीं पीटा, ना इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश की। 'समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण' मोदी सरकार के लिए 'राष्ट्रनीति' है, 'राजनीति' नहीं। इसी विश्वास का नतीजा है कि कोरोना की चुनौतियों को परास्त करने के लिए समाज के सभी वर्ग एक जुट होकर लड़ रहे हैं, मंदिर, गुरुद्वारों, चर्चों की तरह मस्जिदें, दरगाहें एवं सभी धार्मिक-सामाजिक जगहों पर हर तरह के भीड़-भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रम रोक दिए हैं। सभी लोग ईमानदारी के साथ लॉकडाउन, कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के तहत सभी दिशा निर्देशों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर अपील को सम्मान के साथ स्वीकार कर पालन करते रहें।

यही नहीं तमाम दुष्प्रचारों-अफवाहों को दरकिनार कर विभिन्न धार्मिक-सामाजिक संगठन जिनमे दरगाहें, मस्जिदें, इमामबाड़ें, अंजुमनें एवं अल्पसंख्यक सामाजिक-शैक्षिक संस्थान आदि शामिल हैं, लोगों को राहत के लिए आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। लेकिन इस संकट के समय भी 'साजिशों के सूत्रधार' बाज नहीं आ रहे हैं, 'साइबर ठगों' से तालमेल कर सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलाने, दुष्प्रचार करने, कुछ विदेशी संस्थाओं को भारत के खिलाफ चिट्ठियां लिखने में व्यस्त हैं, लेकिन मेरे देश का संस्कार और संकल्प इतना मजबूत है कि इन तमाम 'साजिशी सूरमाओं की शैतानी चालों' को नाकाम करता हुआ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास- सबका विश्वास' के संकल्प के साथ, एकजुटता से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, देश के विश्वास चक्र को विषम चक्र में बदलने के लिए ऐसे 'साजिशी सिंडिकेट' को भारत को बदनाम करने की सोंच से गढ़ा गया 'इस्लामोफोबिया' कार्ड और 'हॉरर हंगामा' बुरी तरह ध्वस्त होगा। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत'- मेरे हिंदुस्तान की आत्मा है, इस पर चोट 135 करोड़ हिन्दुस्तानियों की रूह पर हमला है, हमारा एकजुटता के साथ भारत की सफलता का हमसफ़र बन कर चलना ही 'राष्ट्रधर्म' है। ■

(लेखक केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं)

वैचारिक उत्कर्ष का वर्ष

प्रभात झा

30 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर रही है। अपने पांच वर्षों के पहले कार्यकाल में सरकार ने जहां समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया, वहीं इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए मजबूत नींव रखने में भी सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा। विश्व में भारत के प्रति सोच में परिवर्तन आया। 'सबका साथ सबका विकास' से उत्पन्न जन-विश्वास के फलस्वरूप 23 मई 2019 को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को ऐतिहासिक विजय मिली। अपार जनसमर्थन के साथ 30 मई 2019 को नरेन्द्र मोदी ने पुनः देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। दूसरे कार्यकाल के पहले साल के आरंभिक महीनों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जहां एक ओर विचारधारा को समर्पित किया है, वहीं विगत महीनों में पूरे राष्ट्र को एकसूत्र में बांधते हुए वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जो साहसिक कदम उठाया है, उसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उपलब्धियों और चुनौतियों से भरा यह वर्ष भारत के लिए युगांतकारी रहा है।

स्वतंत्रता के बाद तुष्टिकरण और मनमानी की नीति ने राष्ट्र के समक्ष अनेक समस्याओं को ला खड़ा किया। इसमें एक प्रमुख समस्या जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए संविधान में धारा 370 और 35ए का प्रावधान था। धारा 370 के कारण धरती पर स्वर्ग कहा जानेवाला कश्मीर भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती देनेवाला और आतंकवाद का केंद्र बनता चला गया। राष्ट्र और विकास की मुख्यधारा से दूर होता गया। जिनके हाथों में देश का नेतृत्व था, राष्ट्रीयता के प्रति उनकी उदासीनता की भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित जम्मू-कश्मीर में 41849 लोगों ने शहादत दी। लेकिन जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, अपने दूसरे कार्यकाल के 70 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने कर दिखाया। संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान से धारा 370 और 35ए को हटानेवाले विधेयक को पारित कराकर सरकार ने साबित किया कि उसके लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकात्मता सर्वोपरि है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख लोकतंत्र और विकास की नई राह पर चल पड़ा है।

विविधता भारतीय राष्ट्र की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत को विश्व में विशिष्ट बनाता है। इस एकात्मता को मजबूत करना प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। जहां तक नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रश्न है, मई 2014 से लेकर मई 2019 के पहले कार्यकाल और मई 2019 से मई 2020 तक के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में, राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने की दिशा में ऐसे-ऐसे कदम उठाये गए हैं कि पिछली सरकारों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। 'एक राष्ट्र - एक कर', 'एक राष्ट्र - एक मोबिलिटी कार्ड', 'एक राष्ट्र - एक फ़ास्ट टैग', 'एक देश - एक संविधान' और आज वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में 'एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड।' देश में राष्ट्रीयता व भारतीयता की भावना आज अभूतपूर्व रूप से बलवती हुई है। क्षेत्रीयता की संकीर्णता से देश को बाहर लाने और पूरे राष्ट्र को एकसूत्र में बांधने का काम किया है मोदी सरकार ने।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जहां पहले कार्यकाल में 'सबका साथ-सबका विकास' मूलमंत्र के साथ कार्य किया, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' मूलमंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है। वेतन संहिता लाकर महिला कामगारों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया गया है, वहीं 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019' को मंजूरी दी गई ताकि छोटे व्यापारियों को 60 साल की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जा सके। सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाया गया। सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने और जल संबंधी मुद्दों के व्यापक समाधान के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल के दस सप्ताह के अंदर मुस्लिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया। 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया। एक अगस्त 2019 से देश में तत्काल तीन तलाक देना कानूनी रूप से अपराध हो गया। देश की 8 करोड़ से अधिक मुस्लिम महिलाओं को बहुप्रतीक्षित न्याय मिला। साथ ही, एक ओर जहां बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया, वहीं सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का अनुमोदन किया गया।

सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानकदेव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। गुरु नानकदेव जी के 550वें प्रकाश पर्व को देश और दुनिया में पूरे मान-सम्मान के साथ मनाने का अवसर मिलना, देश के लिए सौभाग्य की बात है। यह सुखद रहा कि 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के दिव्य वातावरण में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामजन्म भूमि विषय पर ऐतिहासिक फैसला दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से सदियों की हिंदू-मुस्लिम कटुता का अंत हुआ और रामंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

वर्ष 1989 में पालमपुर के अपने अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर को लेकर प्रस्ताव पारित किया था और इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी रही। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसके लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा भी निकाली थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीराम जन्मस्थल पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और

इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मस्थल पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य कर रहा है। 31 साल बाद ही सही, भारतीय जनता पार्टी ने देश से जो वादा किया था पूरा हो रहा है। श्रीराम जन्मभूमि स्थान पर खुदाई और निर्माण कार्य आरंभ हो गया है और यथाशीघ्र मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन दे दी गई है।

50 साल से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू-रियांग जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू-रियांग जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है।

विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, "पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।" हमारे राष्ट्र निर्माता की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व था। मानवता की भी यही पुकार थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष के भीतर नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, मुस्लिम देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देकर शोषण से मुक्ति दिलाई और मानवता की रक्षा की।

भारत सहित पूरा विश्व आज कोरोना वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों से संकटग्रस्त स्थिति में है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत चुनौती की इस इस घड़ी को अवसर में बदलने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के साथ आगे बढ़ रहा है। 'आत्मनिर्भरता' भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की मूल अवधारणा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि भारत की आर्थिक सफलता संस्कृतिप्रणीत अर्थनीति में है जिसका मूलाधार आत्मनिर्भरता है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 'एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन, आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम् है।' उन्होंने भारतवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। इसके लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा भी की है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के संकल्पों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज घोषणा भी की गई है, जो देश की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है। जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा 'यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है, भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत की आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं।' सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी 4 वर्ष के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है। संकट में फंसे सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों को 20 हजार करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है। संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति ठीक करने के लिए 90 हजार करोड़ रुपये दिया गया है। छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन (मार्च-अप्रैल) के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये की है। 31 मई 2020 तक किसानों के कर्ज पर ब्याज की छूट दी गई है। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के लिए 4200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों का मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी गई है। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए 10 हजार रुपये तक के ऋण की व्यवस्था की गई है।

यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है।

वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश की 130 करोड़ जनता का एकजुट होकर विश्व के साथ खड़ा होना और विश्व को 'वसुधैव कुटुंबकम्' का संदेश देना है। महामारी से लड़ने में, संकट के दौरान अपने निकट के मनुष्य को नियंत्रित करने में, जो नेतृत्व श्री नरेन्द्र मोदी ने दिखाया है, इससे पहले महात्मा गांधी में देखा गया था। जनता कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन-1 की तैयारी, दीप प्रज्ज्वलन की राष्ट्रीय एकात्म शक्ति से लॉकडाउन-2 के लिए देश का मनः स्थिति तैयार करना, और फिर नियंत्रित रूप से लॉकडाउन-3 एवं लॉकडाउन-3 को लागू करना। विश्व हतप्रभ है। लेकिन यह कार्य वही कर सकता है जिसमें ईश्वरीय शक्ति हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में वह ईश्वरीय शक्ति है। इस दौरान गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन को सम्बोधित कर और जी-20 देशों के वर्चुअल सम्मेलन का नेतृत्व कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। चुनौती को अवसर में बदलने के उनके अदम्य साहस और अद्भुत शक्ति को विश्व ने सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के हाथों में कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता सौंपी है। भविष्य भारतीय नेतृत्व के हाथों में है, आज यह पूरे विश्व का संदेश है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हैं)

अहम है भारतीयों का जीवन और सुधार सरकार ने समय गंवाए बिना यह दिखा दिया

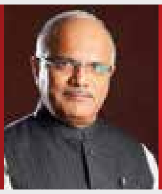

डॉ. विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे

मोदी सरकार 2.0 के एक वर्ष पूरे होने के इस मुकाम पर जब देश एक वैश्विक महामारी से जंग में जुटा है पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों पर मंथन करना भी बहुत प्रासंगिक होगा। पिछला एक वर्ष सरकार के लिए चुनौतियों भरा रहा है क्योंकि इसने राजनीतिक जनादेश का उपयोग कर कुछ अनसुलझी गुत्थियों को सुझलाने का अभूतपूर्व प्रयास किया है।

धारा 370 समाप्त करने का निर्णय निस्संदेह युगांतकारी घटनाओं में एक था, जिसके बाद जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। राज्य के पुनर्गठन में लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को मान्यता दी गई है और साथ ही, केंद्र शासित प्रदेशों को निवेश के लिए आकर्षक बनाने का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया गया है जिससे अंततः पूरे क्षेत्र में तेजी से रोजगार सृजन होगा। इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर राज्य के युवाओं के सपनों को स्थानीय नेताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं ने रौंद रखा था। इसके परिणामस्वरूप एक के बाद एक सरकारें एक अरसे से इस मसले का हल निकालने में नाकाम रहीं।

एक अन्य मसला नागरिक संशोधन कानून (सीएए) का है जिसमें विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत के सभी राजनेताओं ने जो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में बसे अल्पसंख्यकों से वादे किए उन्हें पूरा करने का लक्ष्य है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और पंडित नेहरू दोनों ने नव निर्मित पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। परंतु वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में बसे पाकिस्तान के कई शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी गई। उनका दर्द कम करने और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए मौजूदा सरकार ने सीएए की पहल की, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान करना है। दरअसल यह प्रतिबद्धता महज मानवतावादी है जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी दुहराई थी। हालांकि अंततः प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे पूरा किया।

मोदी सरकार ने एक ओर पिछली एक के बाद एक कई सरकारों की अनदेखी में लंबे समय से अधर में लटके मसलों का हल किया है तो दूसरी ओर अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूरे होने के साथ इस वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का डट कर सामना कर रही है। भारत के इतिहास में अक्सर सूखा, भुखमरी और महामारी का प्रकोप देखा गया है और पिछली सरकारें विभिन्न तरीकों से उनसे निपटती रही हैं। हमारे देश को लेकर सामान्य धारणा यह रही है कि उन्नत देशों – अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में जि़न्दगी सस्ती है। दरअसल पूरे देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक सीमा भी है। लेकिन इस स्थिति में भी मौजूदा सरकार ने मामले को सही से संभाला वरना हम अनगिनत जानें गंवा देते।

वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार यह हकीकत दुनिया के सामने रखना है कि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में जिन्दगी कहीं अधिक कीमती है। महामारी की भयावहता को भांपते ही माननीय प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की घोषणा कर अभूतपूर्व कार्य किया जिसके बाद लॉकडाउन किया गया। लोगों की जान बचाने के लिए 1.3 अरब लोगों के देश को लॉकडाउन करना असाधारण कदम था और वह भी यह सुनिश्चित करते हुए कि लोगों को भोजन, दवा आदि ज़रूरी चीजों की आपूर्ति बनी रहे। केंद्र सरकार ने विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और प्रबंधन के साथ सफलतापूर्वक यह कार्य किया।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इसे भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के दीर्घकालिक निवेश के अवसर के रूप में लिया है। इसका आने वाले वर्षों में अच्छे सामाजिक–आर्थिक परिणाम मिलेंगे। खासकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा। महामारी से जंग में प्रौद्योगिकी को हथियार बनाने पर जोर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि हम अधिक से अधिक जानें बचाएं। हालांकि लॉकडाउन में बहुत से लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। पर सबके दीर्घकालीन हित में सरकार ने 20 ट्रिलियन के विशाल स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की है। साथ ही, कई सुधार किए हैं जिनकी कुछ महीने पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे।

सरकार ने न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के हमारे बहुत से सहयोगी राष्ट्रों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति कर लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया है। मोदी सरकार ने जिस तरह कोविड–19 महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाला है उसकी दुनिया कायल है, हालांकि मुमकिन है इस जंग में कुछ चूक हुई हो। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सरकार के समय से कदम उठाने से अनगिनत लोगों की जानें बची हैं।

इस महामारी से हमारा संघर्ष जारी है। पर इस सिलसिले में हमें यह स्वीकार करना होगा कि सरकार ने पिछले एक वर्ष में 303 के प्रचंड जनादेश का सदुपयोग करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय लेने का साहस किया है जिससे देश की दिशा और दशा ज़रूर बदलेगी।

कोविड–19 के रूप में मुसीबत का जो पहाड़ हमारे सामने आया शायद ही कोई सरकार इससे पार पाने में इस तरह कामयाब होती। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे व्यवस्थाजन्य सुधार का अवसर बना दिया है। इसके साथ ही लंबे अरसे से अधर में लटके भारतीय प्रशासन के कुछ मसलों का हल निकालने का अथक प्रयास सफल हो सकता है। व्यवस्थाजन्य बदलाव के साथ हाल में किए गए सुधारों से 2022 तक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया और तेज होगी। प्रायः 303 से प्राप्त सबसे बड़ी शक्ति किसी संकट को सुअवसर में बदलने का सरकार का दृढ़ संकल्प है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं।)

मोदी सरकार की दमदार पहल

श्याम जाजू

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त हो रहा है। 19/20 के इस साल में जो-जो घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं, सबको विस्मित करनेवाली हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझते हुए पूरा देश नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है।

वैसे यह पहला साल अनेक उपलब्धियों के साथ ही बहुचर्चित रहा है। कई बातें ऐसी हुईं, किसी ने सोचा भी नहीं था। आजादी के बाद से ही कश्मीर निरंतर आतंकवाद, धार्मिक उन्माद व राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के कारण अशांत प्रदेशों में से एक रहा है। धारा 370 के बारे में देशभर में चर्चाएं तो होती रहीं, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी के चलते हुआ पर समस्या का निदान होकर इतनी तत्परता से उसका समाधान हो जाएगा व देश एकात्म होने में एक नया आयाम जुड़ जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। देश के गृहमंत्री अमित शाहजी के नेतृत्व में पहल कर जिस पूरे होमवर्क के साथ इस सरकार ने राज्यसभा में अल्पमत होते हुए भी दोनों सदनों में बिल पारित कर जो इतिहास बनाया है, पूरा देश उसका साक्षी है।

असम समस्या, घुसखोरों का उत्तरपूर्वी प्रदेशों में प्रादुर्भाव, अशांत ब्रह्मपुत्रा, राष्ट्रीय एकात्मता को आह्वान देनेवाले समस्या को ध्यान में लेते हुए सीएए नागरिकता संशोधन विधेयक को भी पारित कराकर मोदीजी की सरकार ने देशभक्ति व राष्ट्र की सुरक्षा विषयों पर दो टूक भूमिका लेकर, सजग प्रहरी के रूप में हम काम करेंगे, यह संदेश पूरे देश में दिया है।

ट्रिपल तलाक कानून का विषय भी सालों से लंबित था। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में तो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करनेवाली उस वक्त की सरकार ने न्यायालय का भी अपमान किया और लाखों मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान व सम्मान को तिलांजलि दी। यह भी ऐतिहासिक बिल सदन में पारित कर मुस्लिम बहनें घर-घर में कोई पत्नी के रूप में, बहन की भूमिका में या बहू के दायित्व में थी, उनकी असुरक्षा का भाव खत्म कर उनका भी सम्मान करने का काम इसी साल में हुआ है।

सालों से देश में हर चुनाव में उपस्थिति दर्ज करानेवाले पूरे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ राममंदिर का निर्णय भी इसी वर्ष में आया। देश में कहीं भी कोई उग्र प्रतिक्रिया या दंगा फसाद न होकर अत्यंत सुगमता से मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, इससे भी पूरे देश में संतोष व समाधान का माहौल निर्माण हुआ है।

सरकार के पहले साल में सभी निर्णयों में एक बात का सातत्य है, देश में गरीब आदमी को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में कामयाब होने की दिशा में सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। स्किल इंडिया के माध्यम से देश में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर जनशक्ति का सही दिशा में उपयोग होने के लिए सरकार ने सशक्त कदम उठाए हैं।

देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर प्रगति की ओर निरंतर चले, इसके लिए सरकार का रवैया बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी विषय को ध्यान में लेकर देश के किसानों को ऋणमुक्त बनाकर, किसानी व खेती व्यवसाय अपने बलबूते पर खड़े होने की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाये हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। सभी किसानों के खाता में मदद हेतु साल के 6000 रुपए हम बैंक-खाता में क्रेडिट करेंगे, यह वादा भाजपा ने चुनाव में किया था। उसकी भी परिपूर्ति कर सरकार ने कृषि विषय में दमदार कदम रखा है।

कोरोना के संक्रमण काल में भी सरकार ने जो-जो कदम उठाये हैं, इससे सरकार संकट की घड़ी में राहत तो दे रही है पर इसके साथ-साथ मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रही है। इससे देश आत्मनिर्भरता की ओर जाने में भी कामयाब रहेगा, ऐसे निर्णय इसी सरकार ने किये हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज तक केवल बजट का 2 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता था। समय की पुकार व देश की आवश्यकता को ध्यान में लेते हुए सरकार ने जो पहलें की हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है।

इसी का परिणाम है कि इतनी आबादी होते हुए भी भारत की क्षति कोरोना से कम हुई है। दूसरे संपन्न देशों की तुलना में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने दम-खम के निर्णय लेकर जो साहस का परिचय दिया है, उससे भी इस संकट में हम सामना कर पा रहे हैं और विश्व में हमारी एक अलग छवि उभरकर आई है।

सरकार के पहले साल में सभी निर्णयों में एक बात का सातत्य है, देश में गरीब आदमी को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में कामयाब होने की दिशा में सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। स्किल इंडिया के माध्यम से देश में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर जनशक्ति का सही दिशा में उपयोग होने के लिए सरकार ने सशक्त कदम उठाए हैं।

मनरेगा के माध्यम से भूखमरी कम कर गांवों में रोजगार देने हेतु उसका दायरा बढ़ाने के साथ-साथ वेतन में भी बढ़ोतरी करने का काम सरकार ने किया है। प्रवासी मजदूरों को वो जहां हैं वहीं राशन उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन' प्रोग्राम को क्रियान्वित कर गांव में भी उसको राशन मिलने की सुविधा उपलब्ध कराई है।

पिछले कार्यकाल में पुराने कानून हटाकर उसमें समयानुकूल परिवर्तन कर प्रगति की राह में रोड़ा बनकर खड़े रहनेवाली व्यवस्था को हटाकर नए कानून बनाने का काम सरकार ने किया था। इस साल के निर्णयों में उस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत में ऑनलाइन व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सपना पूरा कर दिया।

इस साल में उठाए गए कदमों से जहां एक ओर संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी हो गई, वहीं इसके लागत में भी कमी आई और

शेष भाग पृष्ठ 59 पर...

अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं

दुष्यन्त कुमार गौतम

मोदी सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। आज भारत देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 अर्थात् कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, परन्तु की इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोगों को राहत देने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 के संकट काल में भी मजबूत बनी हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 अरब डॉलर बढ़कर 487.04 अरब डालर पर पहुंचा। आज इस संकटकाल के दौरान में अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ देशवासियों के लिए यह बेहद सम्मान और गौरव का विषय है कि मोदी सरकार में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का सर्वसम्मति से कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आज मोदीजी के नेतृत्व में सही समय पर सही फैसला लेकर इस महामारी को लेकर भारत बेहतर स्थिति में है और भारत का रिकवरी रेट शीर्ष पर है।

कोविड-19 संकट को अवसर के रूप में बदलने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज की घोषणा कर देश के हर क्षेत्र को आर्थिक मजबूती देने का अद्भुत काम किया है, जिसमें गरीब अर्थात् ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग को भी बहुत लाभ योजनाओं के माध्यम से देने का कार्य किया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल से मई मध्य तक 6.8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए हैं जिसमें ज्यादातर व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं और यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लगभग 9500 गांव कवर एवं अतिरिक्त 3584 गांवों तक योजना का विस्तार।

सीवरों और सैप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए लक्षित समूह हेतु स्वच्छता से संबंधित 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी।

पीसीआर एवं पीओए अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को राहत देने और अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए 536 करोड़ रुपए का प्रावधान।

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटा देने से वहां पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग (ज्यादातर सफाईकर्मी) को सामान्य अधिकार प्राप्त नहीं थे, आज वह उनको प्राप्त हो गए हैं। वर्तमान में उनके निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि बन रहे हैं और वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

कोविड-19 संकट को अवसर के रूप में बदलने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज की घोषणा कर देश के हर क्षेत्र को आर्थिक मजबूती देने का अद्भुत काम किया है, जिसमें गरीब अर्थात् ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग को भी बहुत लाभ योजनाओं के माध्यम से देने का कार्य किया है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अनुसार जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्थात् जो रेहड़ी-पटरी वाले व्यापारी हैं जिनमें लगभग अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति भी संबंध रखते हैं उनके लिए 5000 करोड़ रुपए की विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करेगी।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अनुसार गरीबों, प्रवासी श्रमिकों, जो कि इनमें बहुत से व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से है उनको सशक्त बनाने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना है और जो व्यक्ति गैर कार्ड धारक है उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटा देने से वहां पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग (ज्यादातर सफाईकर्मी) को सामान्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, जोकि धारा 370 रहते हुए अनुसूचित जाति वर्ग को वह अधिकार पहले कभी प्राप्त ही नहीं हुए, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहा था। जम्मू-कश्मीर का अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति चाहे वह कितना ही पढ़ा-लिखा हो, चाहे वह डॉक्टर बन जाए, चाहे वह इंजीनियर बन जाए लेकिन जम्मू-कश्मीर में उनको सफाईकर्मी ही लगाया जाता था उनको आरक्षण का लाभ तो क्या उनको सामान्य अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर काफी अत्याचार शोषण किया जाता था और आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने धारा 370 हटाकर अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण के लाभ के साथ सामान्य अधिकार भी प्राप्त हुए हैं।

आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा सीएए के कानून से भी अनुसूचित जाति वर्ग को बहुत ही लाभ हुआ है जैसे पाकिस्तान में रह रहे हिन्दू सफाईकर्मी (अनुसूचित जाति वर्ग) जो कि वहां पर वह अत्याचार, शोषण आदि से पीड़ित थे, बल्कि वहां पर उनकी मां, बहनें, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उन सबके लिए भी सीएए के कानून से हिन्दुस्तान में उनको भी लाभ प्राप्त हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति वर्ग पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के फार्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 'वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल' आउटरीच को बढ़ा देती है। असंगठित माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस एमएफईज (MFEs) इकाइयों को एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य मानकों प्राप्त करने, ब्रांड बनाने और मार्केटिंग के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। क्लस्टर बेस्ट अप्रोच जैसे उत्तर प्रदेश में आम, कर्नाटक में टमाटर, आंध्रप्रदेश में मिर्च, महाराष्ट्र में संतरा आदि।

शेष भाग पृष्ठ 59 पर...

अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प

बैजयंत 'जय' पंडा

23 मई, 2019 की प्रचंड जीत को एक साल बीत चुका है। यह जीत सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी की ही जीत नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'रिफॉर्म-बेस्ड' (सुधार पर आधारित) नीतियों की जीत है। मैंने अपने लम्बे राजनीतिक सफर में भाजपा और श्री मोदी जी की नीतियों और विकास कार्यों का अच्छे से विश्लेषण किया है और मुझे ये विश्वास है कि इस सरकार का विकास-केंद्रित शासन हमारे देश को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

भारतीय जनता पिछले बहुत सालों से किसी ऐसे नेता की प्रतीक्षा कर रही थी जो सियासत पर नहीं, बल्कि उनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करे। और अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही, मोदी सरकार ने 'रिफॉर्म' की नीतियों पर ज़ोर दिया। दूसरे कार्यकाल का विवरण अगर एक शब्द में हो तो इसे 'उपलब्धियों का एक साल' कहा जा सकता है। जब 'ट्रिपल तलाक़' जैसी अनुचित और गैर ज़रूरी प्रथा को भारतीय संसद में दण्डनीय अपराध घोषित किया गया, तब मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से किए वादे को पूरा किया। इस प्रथा को समाप्त करना, मोदी सरकार की उस इच्छा-शक्ति की ओर संकेत करता है जो अब इसकी पहचान बन चुकी है। इसी कदम ने देश में यू.सी.सी. (UCC) की ज़रूरत और चर्चा को भी आगे बढ़ाया।

इन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा था अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय। आश्चर्य की बात है कि भारतीय संविधान का वह एकमात्र अनुच्छेद जो 'temporary' या अस्थायी अनुच्छेद के रूप में डाला गया था, उसे हटाने में 70 साल लग गए क्योंकि कोई सरकार इतना ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए सक्षम ही नहीं थी। और इन सालों में जम्मू-कश्मीर में विकास नहीं बल्कि केवल आतंकवाद और भ्रष्टाचार ही पनप पाया। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को ना सिर्फ विकास की राह से दूर रखा, इसके प्रावधानों की वजह से यह

भारतीय जनता पिछले बहुत सालों से किसी ऐसे नेता की प्रतीक्षा कर रही थी जो सियासत पर नहीं, बल्कि उनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करे।

क्षेत्र मानवाधिकार, न्याय और उन्नति से भी वंचित रहा।

इस ऐतिहासिक निर्णय में देश उनके साथ था और इसका पता उन हज़ारों भारतीयों के चेहरों से लगा जो इस निर्णय का उत्सव मनाने सड़कों पर उतरे थे। हमारे लद्दाखी भाई-बहनों को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि अब वह भी उन्नति की दिशा में बढ़ रहे हैं। हाल ही में, जब अधिवास नियमों को बदला गया, तब पहली बार प्रदेश के उन अनगिनत शरणार्थियों और एस.सी. (SC) समुदायों को उम्मीद की किरण नज़र आयी, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपना खून-पसीना बहाया, लेकिन उन्हें बुनियादी अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए।

जब मोदी सरकार ने अपने घोषणा-पत्र का एक और वादा पूरा करते हुए 3 पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सी.ए.ए. के अंतर्गत फास्ट-ट्रैक नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की, तब इस सरकार की उपलब्धियों में एक और कड़ी जुड़ गयी। यह राष्ट्र के लिए एक लंबे समय से लंबित वादा था जिसे सरकार ने पूरा किया। हालांकि कुछ वर्गों ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर, आधे-अधूरे 'सिद्धांतों' और भय-भ्रामक चित्रण के द्वारा देश को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह नाकाम रहे।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार ने भारतीयों के भव्य सपने को पूरा करने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया। यह इस बात की झलक देती है कि यह सरकार अपने किये हर वादे को पूरा करती है।

एक से बढ़कर एक कामयाबी के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक महामारी के रूप में आई, जिसे अब हम धीरे-धीरे हरा रहे हैं। देखते ही देखते, यह अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़ी आर्थिक क्षमता वाले देश भी इस महामारी से लड़ने में काफी हद तक असफल रहे और हज़ारों लोग जान गंवा बैठे। इस चुनौती का सामना करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता की रणनीति ही थी जो देश के लाखों नागरिकों को बचाने में सफल रही।

आपदा का सामना करने के लिए मोदी सरकार ने जनवरी से समयबद्ध और पूर्वव्यापी उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था।

सरकार ने चीन में उत्पन्न होने वाले कोरोना वायरस के स्रोत से आने वाली उड़ानों को रोका और फिर जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के द्वारा ये सुनिश्चित किया कि ये वायरस तेजी से ना फैले। यह निर्णय एक बड़ी तबाही से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण था। परिणाम स्पष्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगभग 216 जिले कोरोना मुक्त हैं, और 60,490 रोगी, रिकवरी दर को 41.61% तक ले गए हैं। 80% मामले पांच शहरों तक सीमित हैं। कई विशेषज्ञों और सरकार ने लॉकडाउन प्रभाव का एक सांख्यिकीय विश्लेषण किया और यह पाया कि लोकडाउन की वजह से लगभग 37,000-78,000 लोगों का जीवन बचाया गया। मामले जो 14-29 लाख तक जा सकते थे, वह अब कुछ हज़ार ही बढ़ेंगे। इसका श्रेय एक कर्मठ प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को जाता है।

महामारी की वजह से आयी आर्थिक गिरावट को दूर करने के लिए हाल ही में सरकार ने बीस लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया जो जीडीपी का लगभग 10% है, जबकि अधिकांश विपक्षी नेताओं ने भी जीडीपी के सिर्फ 5%-6% की मांग की थी। आत्मनिर्भरता पर प्रधानमंत्री का जोर और लोकल के लिए वोकल होना ही अब भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का नया मंत्र है।

वित्त मंत्री जी ने कुल पांच चरणों में आत्मनिर्भर अभियान की नींव रखी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नयी ऊंचाई तक ले जायेगा। 1991 के उदारीकरण सुधारों के बाद, भारत ने ऐसे कोई रिफॉर्म नहीं देखे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने इस आर्थिक पैकेज की बहुत प्रशंसा की, जिसमें हर तबके को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गयी थी।

इस पैकेज के द्वारा ग्रामीण हों या शहरी, हर निचले हिस्से के व्यक्ति को तत्काल नकद राशि पहुंचाई गयी; एमएसएमई और बड़े उद्योगों को राहत पैकेज मिले; और देश के लाखों मज़दूरों और किसानों को मदद पहुंचाई गयी। इसमें हेल्थकेयर वर्कर्स इंश्योरेंस, हेल्थकेयर सप्लाई और पीपीई किट, टेस्टिंग किट आदि के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पैकेज के आलोचक भी यह जानते हैं कि अगर किसी के पास भारत को महामारी और आर्थिक मंदी से बचाने का राजनीतिक संकल्प था, तो यह केवल श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सक्षम सरकार के पास था।

आने वाले वर्षों में एक बड़ा बदलाव दुनिया का इंतजार कर रहा है और इस महामारी ने निस्संदेह ही आर्थिक गतिविधि को प्रभावित किया है, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि यह सरकार तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं कर लेंगे और नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया में बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई है, खासकर इस महामारी के दौरान जब हमने दूसरे देशों की मदद में भी हाथ बढ़ाया। यह 6 साल, भारत के भविष्य को एक नयी दिशा दिखा गए हैं। 'न्यू इंडिया' की सफलता हमें ज़रूर प्राप्त होगी, यह हम 130 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हैं)

पृष्ठ 56 का शेष भाग...

सुगमता भी हो गयी। कोई बिचौलिये रहे नहीं, व्यवस्था पारदर्शी व कार्यक्षम बनने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी बार के बजट के बारे में बोलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की करने की बात कही है। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का प्रावधान सरकार ने किया है। पांच वर्ष का परफॉर्मेंस और यह पहले साल की शुरुआत देखते हुए कई नए कीर्तिमान हमने गढ़े हैं। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ दुनिया की बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी भारत में चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में बन रहा है, उसके साथ-साथ सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है।

2014 में भारत विश्व बैंक कारोबारी सुगमता श्रेणी में 142वें स्थान पर था, 2019 में 63वें स्थान पर पहुंचा है। भारत ने 10 मानकों में से 7 मानकों में प्रगति दर्ज की है। लघु उद्योग (MSME) बढ़ाकर स्वरोजगार निर्मिति करते हुए नया रोजगार निर्माण करने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं।

दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णायक व प्रगति का मार्ग प्रशस्त करनेवाला रहा है। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश का अभिमान व अस्मिता बढ़ाने का काम भी इस कार्यकाल में हुआ है। विश्व में नई इमेज अपने कर्तृत्व व नेतृत्व से मोदी जी ने बनायी है। आज कोरोना के संकटग्रस्त अवस्था में भी चीन में काम करनेवाले अमेरिकन व बाकी उद्योगपति भी धीरे-धीरे अपना कारोबार समेटकर भारत की ओर सक्षम व समर्थ पर्याय के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकन संगठन एडवोकेसी ग्रुप द्वारा यही व्यक्त किया गया है कि कई कंपनियों ने अपना रुख भारत की ओर कर दिया है। सैमसंग ने अपना कारोबार चीन में समेट लिया है और भारत में अपने प्लांट का विस्तार किया है। सोनी ने चीन में अपना प्लांट बंद करने की घोषणा कर दी है। एप्पल ने बेंगलुरू में अपनी उत्पादन इकाई शुरू कर दी है। यह सब बातें यही बता रही है कि मोदी सरकार का पहला साल यह निश्चित रूप से नया कीर्तिमान स्थापित कर देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करनेवाला साबित हुआ है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

पृष्ठ 57 का शेष भाग...

हर्बल खेती को बढ़ावा- इन सबमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को रोजगार के साथ-साथ अपने स्वावलम्बी आत्मनिर्भर उद्योगों में पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

अनुसूचित जाति वर्ग के एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोमोट करने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक के लिए ऋण की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है।

स्टैंडअप इंडिया स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की महिला व्यवसायी के लिए मोदी सरकार ने बैंक से एक करोड़ रुपए की ऋण देने की व्यवस्था करके अनुसूचित जाति वर्ग की महिला व्यवसायी को भी स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया है।

आयुष्मान योजना- मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अनुसूचित जाति वर्ग को पूरा-पूरा लाभ मिला है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

आत्मनिर्भरता : 21वीं सदी के भारत की राह

मुरलीधर राव

मानव जाति ने अतीत में भूकंप, महामारी और युद्ध जैसी कई आपदाओं और संकटों का सामना किया है। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 महामारी ने लगभग पूरे विश्व को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। इसने पूरी मानव जाति को बहुत बुरी तरह विचलित कर दिया है। इतिहास में हैजा, प्लेग जैसी कई महामारियों ने मनुष्यों को बहुत सताया है, लेकिन इनमें से कोई भी कोविड-19 जितनी व्यापक नहीं रही। आज वैश्विक एकीकरण और राष्ट्रों के बीच बढ़ती आवाजाही ने कोविड को अब तक की सबसे बड़ी महामारी बना दिया है। इस समय लगभग 188 देशों में इस महामारी के 55 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके परिणामस्वरूप करीब 3.5 लाख लोग मौत के शिकार हो चुके हैं।

कोविड-19 के चलते जहां एक ओर बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है, वहीं इससे वैश्विक स्तर पर एक ऐसी उथल-पुथल भी मच गई है, जो अपने आप में अनहोनी है। आपूर्ति और मांग दोनों दृष्टि से दुनिया में पहले कभी भी इस हद तक आर्थिक एकीकरण नहीं हुआ था। इसी कारण व्यवधान भी पहले से कहीं अधिक तीव्र और व्यापक है।

इस समय दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कोविड-19 का सफलतापूर्वक मुकाबला करना ताकि कम से कम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। दूसरी चुनौती है अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखना और जल्द से जल्द इसे सामान्य स्थिति में लाना। नीति निर्माताओं और दुनिया के नेताओं को इन दोनों चुनौतियों से एक साथ सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को लेकर विभिन्न देशों के उपायों में एक तरह की समानता देखी जा सकती है। लेकिन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए किसी एक देश में अपनाए गए उपायों को दूसरे देश में लागू करना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय।

कोविड महामारी के मामले में भारत भी एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति से गुजर रहा है। एक ओर जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल जैसी स्थिति है वहीं दूसरी ओर आर्थिक तंत्र में भी भारी व्यवधान आ चुका है। हालांकि एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड संकट के दौरान देश को उसी तरह संभाला है जैसा वे पहले भी कई बार संकट की स्थिति में कर चुके हैं। कोविड की रोकथाम करने और उससे निपटने की उनकी पद्धति और कार्य योजना बेमिसाल है। जिस तरह अधिक से अधिक लोग कोविड-19 की गिरफ्त से निकल कर स्वस्थ हो रहे हैं और मौत का आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, वह प्रधानमंत्री की रणनीतिक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। यह राशि भारत की जीडीपी की लगभग 10 प्रतिशत है। इस पैकेज को 21 वीं सदी के भारत के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

इस मामले में नरेन्द्र मोदी जी ने दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लाने की भी पहल की ताकि महामारी से निपटने की एक समेकित रणनीति बनाई जा सके। इसी तरह उन्होंने विश्व के नेताओं को विश्वास में लेकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जिसके चलते मानव जाति के हित में विश्व स्तर पर एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जा सका।

कोविड संकट के दौरान सबसे कमजोर वर्ग की मुसीबतों का समाधान करने के लिए सरकार ने तुरंत कदम उठाया। महामारी के शुरुआती चरण में ही 1.7 लाख करोड़ रुपये के गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई, जिससे 39 करोड़ लोगों को सहायता प्राप्त हो सकी। प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के माध्यम से यह सहायता और कारगर साबित हुई। इसी के साथ मार्च और अप्रैल में आरबीआई ने आपातकालीन उपायों के तहत 8 लाख करोड़ रुपये जारी किए। इससे अर्थव्यवस्था में नगदी की मात्रा बढ़ी और लोगों को थोड़ी राहत मिली।

नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार इस महामारी का सामना किया, वह अद्वितीय और अनुकरणीय है। उन्होंने लोगों को इस चुनौती का एहसास करवाते हुए इसे एक अवसर में बदल दिया। उनका मानना है कि चुनौती का जवाब हमें इस तरह देना चाहिए कि खतरा छोटा साबित हो जाए। उनकी सरकार भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करना चाहती है जिसकी 21 वीं सदी के विश्व में लोग अपेक्षा करते हैं। इसलिए, उन्होंने 138 करोड़ भारतीयों से अपील की कि वे 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए कोविड-19 को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें।

इस संदर्भ में बड़ी दूरदृष्टि के साथ उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। यह राशि भारत की जीडीपी की लगभग 10 प्रतिशत है। इस पैकेज को 21 वीं सदी के भारत के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दो या तीन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने या राहत के कुछ उपाय करने की बजाए उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के इस बड़ी आकांक्षा को पूरा करने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने पैकेज के पीछे इकोनॉमी, इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी और डिमांड (अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक, जनसमुदाय और मांग) को आधार बताया। उन्होंने भविष्य की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिसमें छोटी-मोटी बढ़ोतरी की नहीं, बल्कि लंबी छलांग की बात कही गई है। पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी की उपलब्धता और कानूनों पर फोकस किया गया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे को आधुनिक भारत की पहचान बनाने पर जोर दिया है।

कोविड के बाद की दुनिया के नए संदर्भ और 21 वीं सदी की भारत की आकांक्षाओं को साकार करते हुए, उन्होंने वोकल फॉर लोकल (स्थानीय उत्पादों की बात हो) का नारा दिया। आत्मनिर्भरता भारत की आर्थिक नीति का मूल तत्व है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भरता का हमारा मॉडल अपने को फिर से परिभाषित करे। आत्मनिर्भरता का मतलब आत्म केंद्रित होना नहीं है। यह वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धांत से प्रेरित है। आत्मनिर्भरता के

इस दृष्टिकोण को राष्ट्र और समाज दोनों के एजेंडे में शामिल करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है।

2014 में सत्ता में आने के बाद नरेन्द्र मोदी जी ने 21 वीं सदी में भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कारगर पहल की। भ्रष्टाचार और नीतिगत अनिर्णय में डूबी व्यवस्था को उन्होंने देखते ही देखते एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन में तब्दील कर दिया। कुछ महीनों के भीतर ही सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत की। इस दौरान विश्व रिकार्ड बनाते हुए बैंक खाते खोले गए, जो वित्तीय समावेशन का बेजोड़ उदाहरण बनकर हमारे सामने है। 38.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों और 1.35 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ, जनधन योजना उन तमाम उपायों में से एक थी जिसे एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए लागू किया गया। इसके चलते पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं सुगम हो पाई हैं, जिसके माध्यम से न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रत्येक वर्ष किसानों के बैंक खातों में सीधे 6000 रुपए स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इसी के साथ कोविड राहत के तौर पर 8.19 करोड़ लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपये की किस्त भी जारी की गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह योजना आज भारत के प्रगति पथ की मजबूत नींव साबित हो रही है।

विभिन्न बीमा योजनाओं के माध्यम से बीमा वंचित लोगों का बीमा करना एक और ऐसा पहलू है जिससे मजबूत नींव की परिकल्पना साकार हो रही है। इस दृष्टि से पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना उल्लेखनीय हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक करोड़ से अधिक रोगियों का उपचार किया गया है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन तमाम लोगों को पेंशन की सुरक्षा दी गई है जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से कम है। पीएम किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों को भी इसी तरह पेंशन सुनिश्चित करती है। अभी तक लगभग 20 लाख किसान इसके तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत 1.12 लाख घरों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम चल रहा है।

नरेन्द्र मोदी जी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दिया है। अब तक रखी गई मजबूत नींव के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता की यह पहल भारत को फिर से गौरवशाली बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। पीएम ने याद दिलाया कि कैसे भारत कभी दुनिया में 'सोने की चिड़िया' के रूप में प्रसिद्ध था। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने लगातार 1700 वर्षों से अधिक समय तक विश्व का आर्थिक नेतृत्व किया है। 1 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक विश्व जीडीपी में हमारा हिस्सा न्यूनतम 24.4 प्रतिशत और अधिकतम 32.9 प्रतिशत था। इस पैमाने पर चीन की जीडीपी हिस्सेदारी सबसे अधिक 26.1 प्रतिशत और सबसे कम 22.3 प्रतिशत रही है। मोदी जी के सपने का मूल बिंदु यही है। इसी को सामने रखते हुए उन्होंने 2014 से ही एक नींव तैयार करने का काम किया, ताकि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को साकार किया जा सके।

भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने लगातार 1700 वर्षों से अधिक समय तक विश्व का आर्थिक नेतृत्व किया है। 1 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक विश्व जीडीपी में हमारा हिस्सा न्यूनतम 24.4 प्रतिशत और अधिकतम 32.9 प्रतिशत था। इस पैमाने पर चीन की जीडीपी हिस्सेदारी सबसे अधिक 26.1 प्रतिशत और सबसे कम 22.3 प्रतिशत रही है।

एक आत्मनिर्भर भारत का मतलब राष्ट्र के सुरक्षा पहलुओं को व्यापक बनाना भी है। सुरक्षा अब केवल सैन्य सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषय भी शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना की परिकल्पना में इसका ध्यान रखा गया है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ भारत का दुनिया में दूध का शीर्ष उत्पादक बनकर उभरना अब एक सच्चाई है। खाद्य सुरक्षा की कुछ कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने के लिए तिलहन, दलहन और नीली क्रांति पर जोर दिया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की अदायगी, 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष और ऐसे ही कई और उपायों के द्वारा खाद्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने का काम किया गया है।

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) भारत की विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के बाद लोगों के रोजगार का यह दूसरा सबसे बड़ा माध्यम है। भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को मजबूत करने और राष्ट्र की संभावनाओं को ठोस आधार देने के लिए MSME की परिभाषा में संशोधन, 3 लाख रुपए तक के गिरवी मुक्त तुरंत ऋण का भुगतान, 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी आवक, 200 करोड़ रुपए तक की निविदाओं में अकेले भागीदारी और ऐसे ही कई और उपाय किए गए हैं।

कोविड के पहले और कोविड के बाद के स्वास्थ्य ढांचे में अंतर को आगे चलकर साफ महसूस किया जा सकेगा। स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, आयुष आदि के कारण स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत बेहतर हो गया है। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि यहां जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हो, मृत्यु दर कम हो, महामारियों से निपटने में हमारी कुशलता बढ़े और भारत दुनिया का स्वास्थ्य गंतव्य बने। आज स्वास्थ्य पेशेवरों की एक बड़ी फौज, नवाचार की विशेष योग्यता और दवाइयों के उत्पादन की भारी क्षमता के कारण भारत दुनिया भर में कोविड की लड़ाई लड़ने वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है।

1965 के युद्ध के दौरान देश में खाद्यान्न संकट था। इसी कारण लाल बहादुर शास्त्री ने रोज एक समय का भोजन छोड़ने का आह्वान किया था। इससे भारत को वापस अपने पैर पर खड़ा होने में मदद मिली थी। 2020 में, जब हमने कोविड की लड़ाई शुरू की, तब भारत में पीपीई या एन-95 मास्क का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन 60 दिनों के भीतर हमने तस्वीर बदल दी। आज प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई किट का निर्माण करते हुए हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पीपीई निर्माता बन गए हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इस राष्ट्र के सामने चुनौती होती है और मार्गदर्शन करने में सक्षम नेता होता है, तो यह देश अधिक दृढ़ता और शक्ति के साथ अपने को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने और संविधान सभा में लंबी बहस के बाद भारत ने बराबरी के सिद्धांत पर एक समतावादी समाज बनाने का फैसला किया था। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के अधूरे सपने को पूरा करेगी, जिन्होंने एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

मोदी सरकार की नीतियों में गरीब कल्याण पर जोर

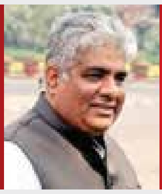

भूपेंद्र यादव

आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा कर रही है, तब देश कोविड-19 के रूप में विकट आपदा से लड़ रहा है। इस महामारी के समक्ष दुनिया के विकसित और साधन संपन्न देशों ने भी हथियार डाल दिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की वजह से भारत इस महामारी के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करके पूरी मजबूती से इसके खिलाफ लड़ रहा है।

गौर करें तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के शासन की नीतियों के केंद्र में गरीब कल्याण की दृष्टि और समतामूलक समाज की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे थे। दूसरे कार्यकाल में भी वह निरंतरता जारी रही। गत दो महीनों में कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौती के बीच सरकार उसी दृष्टि से कार्य करती नजर आ रही है। मोदी सरकार इस संकट से निपटने के साथ-साथ देश के गरीबों, पिछड़ों, श्रमिकों को संबल देने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।

2014 में जब मोदी सरकार पहली बार केंद्र की सत्ता में आई, तो उसके समक्ष आर्थिक विषमता की समस्या जटिल थी। गरीब-अमीर के बीच की खाई आज की तुलना में ज्यादा बड़ी थी। गरीबों का जीवन स्तर मानकों के अनुरूप ऊपर नहीं उठ रहा था। इसका प्रमुख कारण आर्थिक विषमता का प्रबल होना रहा। एक तरह से कहना उचित होगा कि आर्थिक विषमता देश के सर्वांगीण विकास में एक बड़ी बाधा की तरह थी। चूंकि दशकों से चलती आ रही आर्थिक विषमता ने सामाजिक विषमता को भी मजबूत किया। इसको ठीक करना 2014 में आई नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। मोदी सरकार ने सबसे पहले इसे दूर करने के लिए नीतिगत प्रयास शुरू किये। सरकार की दृष्टि में अन्त्योदय के संकल्प स्पष्ट थे। गरीब कल्याण की भावना मुखर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा, 'हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है।' इस प्रकार दीन दयाल उपाध्याय की अन्त्योदय की अवधारणा पर आधारित समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने वाली नीतियों के निर्माण की शुरुआत सरकार द्वारा की गयी।

देश आजाद होने के साढ़े छः दशक से भी

28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरुआत की, जिसके तहत घर-घर जाकर समाज के गरीब तबकों के लोगों के खाते खोले गए। इसके जरिये देश के गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में सम्मिलित कर इसका हिस्सा बनाने का एक बड़ा काम सरकार ने किया। इस योजना के तहत देश में 35 करोड़ से अधिक खाते खोले गये।

अधिक का समय बीत जाने के बावजूद तक देश की एक बड़ी आबादी बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा तक नहीं बन पाई थी। यह आबादी देश के गरीब, पिछड़ा, वंचित तबके की आबादी थी। उन्हें दशकों तक मुख्यधारा के अर्थतंत्र से वंचित रखा गया था। 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' की शुरुआत की, जिसके तहत घर-घर जाकर समाज के गरीब तबकों के लोगों के खाते खोले गए। इसके जरिये देश के गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में सम्मिलित कर इसका हिस्सा बनाने का एक बड़ा काम सरकार ने किया। इस योजना के तहत देश में 35 करोड़ से अधिक खाते खोले गये। हालांकि तब विपक्ष ने इस योजना के दूरगामी लाभों को न समझते हुए इसका उपहास उड़ाया, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि देश के गरीबों को सशक्त करने तथा शासन के स्तर पर पारदर्शिता लाने में यह योजना अत्यंत कारगर सिद्ध हुई है।

तमाम सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों, किसानों आदि को दी जाने वाली राशि बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के अब सीधे इन खातों के जरिये उनके पास पहुंच जाती है। इस कोविड संकट के दौर में भी जब लॉक डाउन के कारण देश के मजदूरों, किसानों के लिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, तब सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाने का काम इसी व्यवस्था के तहत तुरंत हो गया। एक आंकड़े के मुताबिक़ 24 मार्च से 17 अप्रैल के बीच 16 करोड़ लोगों के खातें में 36659 करोड़ की राशि भेजी गयी है। अगर 2014 में जनधन योजना के जरिये सरकार ने इन लोगों के बैंक खाते नहीं खुलवाए होते तो आज इस संकट काल में इतने बड़े पैमाने पर और इतनी तेजी तथा पारदर्शिता के साथ गरीब और वंचित तबके को इतनी बड़ी सहायता राशि का वितरण कभी संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान जैसी योजनाओं के द्वारा सरकार ने समाज के कमजोर तबकों के हितों को सुरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त बनाने का भी प्रयास किया है।

सामाजिक न्याय के नाम पर देश में खूब राजनीति हुई है, लेकिन इसे सही अर्थों में लागू करने की नीयत इस पर राजनीति करने वालों में नहीं थी। सामाजिक न्याय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसे 'जातिवाद' का आकार देकर राजनीतिक लाभ लिया, जबकि भाजपा के लिए सामाजिक न्याय का अर्थ बिना किसी का हक़ प्रभावित किये 'सबका साथ,

सबका विकास' करना रहा है। मोदी सरकार ने नीतिगत स्तर पर यह सुनिश्चित किया कि समाज में सबको समान अवसर उपलब्ध हो सके। अनुसूचित जाति-जनजाति के हितों के साथ-साथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, सरकारी नौकरियों में क्लास 3 और 4 में साक्षात्कार समाप्त करने तथा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने जैसे क़दमों से सामाजिक न्याय की वास्तविक अवधारणा मूर्त आकार देने का काम किया है। समाज के अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़ों के लिए संविधानसम्मत व्यवस्था से मिले आरक्षण के साथ भाजपा सरकार पूरी तत्परता से खड़ी रही। वहीं समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य तबके के युवाओं को दस प्रतिशत आरक्षण किसी के अधिकार को कम करके देने का साहसिक निर्णय सरकार ने लिया। समाज के किसी भी वर्ग व व्यक्ति के साथ कोई अन्याय न हो, इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबद्ध कार्य किया है।

इसके अलावा महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 मई, 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की गयी। इस योजना के तहत अब तक देश के 715 जिलों की आठ करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि आदि योजनाओं के माध्यम से न केवल स्त्री के प्रति सामाजिक सोच में परिष्कार लाने का काम किया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी अवसर प्रदान किए। दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं।

महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 मई, 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की गयी। इस योजना के तहत अब तक देश के 715 जिलों की आठ करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी समाज में वर्ग संघर्ष नहीं, सर्व समन्वय के लिए काम करती है। वर्ग संघर्ष का रास्ता वाम दलों का है। भाजपा की वैचारिकता का आधार एकात्म मानव दर्शन भी हमें यही सिखाता है कि समाज में कोई व्यक्ति छोटा-बड़ा नहीं है, सब समान हैं। यह विचार दृष्टि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों और योजनाओं में स्पष्टता से उभर कर आती है। चाहें सरकार के पहले पांच साल का कार्यकाल हो या इस एक साल के कार्यकाल हो अथवा मौजूदा कोविड आपदा के दौर में सरकार का कामकाज हो, सबमें सरकार का उद्देश्य इतना ही रहा है कि देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर प्रगति की राह में पिछड़ रहे लोगों तथा समुदायों को आगे बढ़ने का अवसर देते हुए एक सुखी, समृद्ध और समतामूलक भावना से युक्त देश और समाज का निर्माण किया जा सके। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

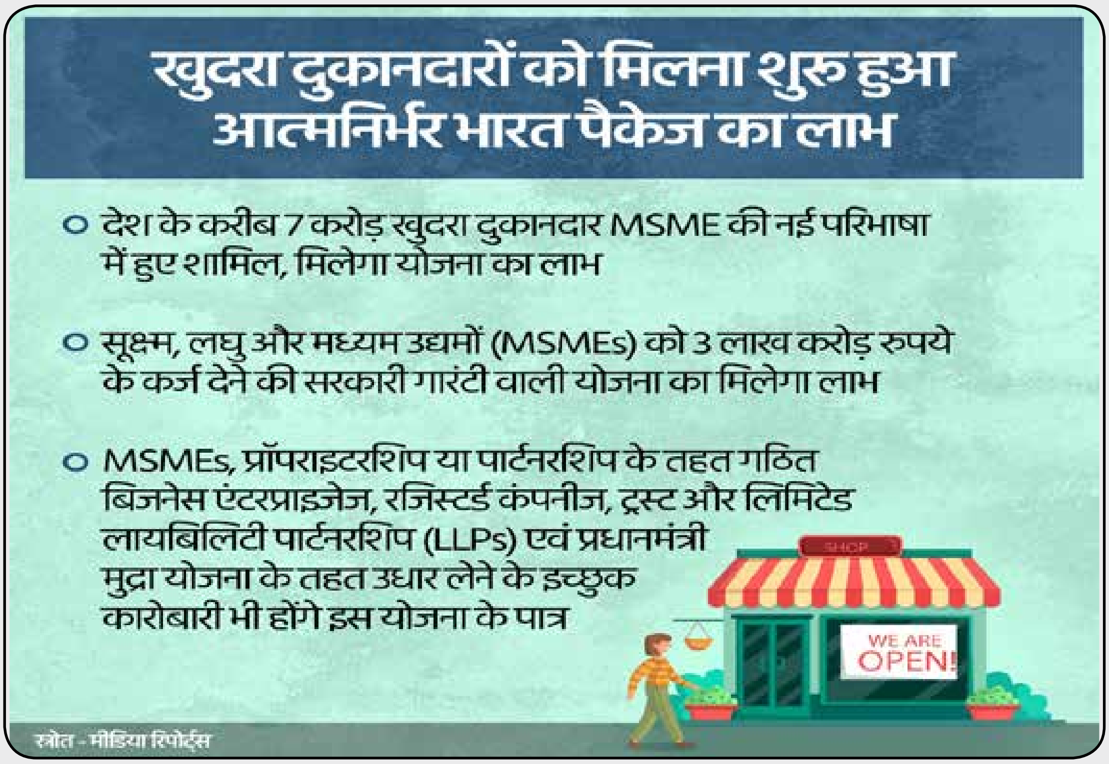

मोदी सरकार के पैकेज का गणित और प्रभाव

स्वामिनाथन गुरुमूर्ति

मोदी सरकार के राहत पैकेज को तीन भागों में बांटा जा सकता है - प्रत्यक्ष सरकारी खर्च, बैंक ऋण, और रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कर्ज। मोदी के विरोधियों ने कहा कि पैकेज का बैंक क्रेडिट वाला हिस्सा बहुत बड़ा है और सरकार का हिस्सा बेहद कम है। लेकिन उनकी आलोचना भारतीय वित्तीय मॉडल की उनकी खराब समझ और सार्वजनिक बैंकों एवं सरकार के बीच राजकोषीय संबंधों पर आधारित है। सात राष्ट्रों के समूह जी-7 के साथ मोदी पैकेज की तुलना करना भी तर्कहीन है क्योंकि भारतीय बैंकिंग मॉडल जी-7 से काफी भिन्न है। जब तक इस विशाल अंतर को नहीं समझा जाता, मोदी पैकेज के गणित के पीछे के तर्क को समझा नहीं जा सकता।

जी–7 में बैंक ऋण नहीं, केवल नोटों की छपाई पर जोर

अमेरिका, जो वैश्विक वित्तीय नियमों का निर्धारण करता है, उसके पास केवल एक सार्वजनिक स्वामित्व वाला बैंक है। अमेरिकी बैंक की कुल संपत्ति 20.4 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले बैंक की हिस्सेदारी 0.03 प्रतिशत से कम है। इंग्लैंड में 10 ट्रिलियन डॉलर की कुल बैंक संपत्ति, जिसमें केवल एक राज्य के स्वामित्व वाला बैंक और उसकी हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत है। फ्रांस में कुल बैंक संपत्ति 8.3 ट्रिलियन डॉलर की है और इसमें सार्वजनिक बैंक का हिस्सा सिर्फ 2.6 प्रतिशत है। जर्मनी में एक अद्वितीय वित्तीय मॉडल है, जहां बैंक की कुल संपत्ति 9.16 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। जापान की बैंक संपत्ति कुल 17.42 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से सार्वजनिक बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 8 प्रतिशत है। पूरे यूरोपीय संघ के बैंकों की संपत्ति 47.6 ट्रिलियन डॉलर है। और जी-7 की कुल बैंकों की संपत्ति 86.4 ट्रिलियन डॉलर है। जी-7 देशों का संयुक्त शेयर बाजार पूंजीकरण करीब 60 ट्रिलियन डॉलर है। बैंक फंड और स्टॉक मार्केट एक्सेस के बावजूद जी-7 राष्ट्र बैंकों या शेयर बाजारों से कोई उधार नहीं लेते हैं; इसके बजाय वे कोविड पैकेज के लिए नोटों की छपाई का सहारा ले रहे हैं। जी-7 राष्ट्र अपने पैकेज के लिए बैंकों या शेयर मार्किट से ऋण नहीं लेते हैं, बल्कि नोटों की छपाई पर जोर देते हैं और यही बात मोदी पैकेज को भिन्न बनाती है।

मोदी पैकेज का तार्किक उद्देश्य और समान रूप से स्पष्ट इरादा है। इसका स्पष्ट इरादा बजट के प्रत्यक्ष राजकोषीय खर्च के माध्यम से वंचित और परेशान लोगों को मदद प्रदान करना है। उनका कोविड-19 राहत लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिसमें पहले गरीबों, फिर मध्य समूह और अंत में बाकी के सहयोग की वकालत करता है।

कोविड –19 बैंक क्रेडिट समान रूप से सरकारी जोखिम है

भारत की परिस्थितियां इसके एकदम विपरीत है। भारत में, लगभग आधी बचत बैंक में जमा है और इसका 70 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक बैंकों में है। और वित्तीय बचत का केवल 2.5 प्रतिशत स्टॉक से मिलता है, जो भारत में निवेश करने वाली विदेशी वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वित्तीय प्रणाली का मुख्य चालक बैंक है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारतीय व्यापार को भी वित्तपोषित करना होता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उधार, भारतीय व्यापारियों को बैंकों से अतिरिक्त पैसा उधार लेने के लिए मजबूर करता है, इसके परिणामस्वरूप वह विदेशी वाणिज्यिक इकाइयों से उधार लेते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम है। चालू वर्ष के लिए, बैंकों पर राज्य और केंद्र सरकार की ऋण मांग उनके द्वारा जमा की गई धनराशि से 60 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दोनों सरकारें बैंकों से अधिक उधार ले सकें। इसीलिए मोदी सरकार को कोविड-19 संबंधित खर्चों के लिए अपनी उधार की सीमा को सीमित करना होगा।

एक कम ज्ञात तथ्य अब अधिक प्रासंगिक है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्रेडिट जोखिम को भारत सरकार की अपनी संप्रभु रेटिंग में आकस्मिक देयता मानती हैं। मूडीज की एक रिपोर्ट ने 2016 में कहा कि गैर जरूरी खराब ऋण सरकार की बैलेंस शीट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह पैकेज वस्तुतः सरकारी गारंटी क्रेडिट और सरकार द्वारा अस्वीकार्य क्रेडिट के बीच रेखा को मिटा देता है। मोदी पैकेज का पूरा बैंक क्रेडिट हिस्सा या अस्वीकार्य क्रेडिट को लेकर सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार के प्रत्यक्ष व्यय और बैंक ऋण मोदी पैकेज का 62 प्रतिशत हिस्सा है और बाकी 38 प्रतिशत आरबीआई का हिस्सा है।

मोदी पैकेज: इरादा और उद्देश्य

मोदी पैकेज का तार्किक उद्देश्य और समान रूप से स्पष्ट इरादा है। इसका स्पष्ट इरादा बजट के प्रत्यक्ष राजकोषीय खर्च के माध्यम से वंचित और परेशान लोगों को मदद प्रदान करना है। उनका कोविड-19 राहत लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिसमें पहले गरीबों, फिर मध्य समूह और अंत में बाकी के सहयोग की वकालत करता है। इसका उद्देश्य राहत उपायों के साथ अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना है। यह

परस्पर उद्देश्य इस पैकेज से स्पष्ट होते हैं।

मोदी ने 26 मार्च को वादा किया था कि अगले तीन महीनों में 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज देने का काम किया जाएगा। अप्रैल में ही, 36 राज्यों ने लाभार्थियों को वितरण के लिए 67.65 लाख टन अनाज लिया था। उन्होंने अगले तीन महीनों के लिए 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बुक किए गए 509 लाख अनुरोधों में से 482 लाख सिलेंडर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। 38 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के माध्यम से दी जा चुकी है, मोदी सरकार ने किसानों के लिए 16,394 करोड़ रुपये, महिलाओं को 10,295 करोड़ रुपये, वृद्ध, विधवा और विकलांगों को 1,405 करोड़ रुपये और पंजीकृत 3.5 करोड़ प्रवासी निर्माण श्रमिकों को 3,492 करोड़ रुपये दिए हैं।

26 मार्च की घोषणा में एमएसएमई में प्रति माह 15,000 रुपये से कम आय वालों (100 से कम कर्मचारियों के साथ) को तीन महीने के लिए अपने वेतन का 25 प्रतिशत देने की पेशकश की गई; संगठित कर्मचारियों को तीन महीने के लिए उनके वेतन के 75 प्रतिशत के बराबर एक गैर-वापसी योग्य अग्रिम; और मनरेगा के गरीबों को दैनिक वेतन भुगतान में 20 रुपये की वृद्धि। पीएमजेडीवाई और आधार लिंकेज के माध्यम से बनाई गई व्यवस्था के कारण सरकार ने तंत्र में रिसाव को कम किया है और सभी को बिना परेशानी के सीधे राहत दी है, जिसने लाभार्थी को किसी भी एटीएम या अन्य अधिकृत व्यक्ति से बायोमेट्रिक्स के उपयोग के माध्यम से नकदी प्राप्त करने में सक्षम बनाया। कल्पना कीजिए कि यदि 38 करोड़ बैंक खातों को आधार जैसी प्रणाली से जोड़ा नहीं गया होता, तो भारत इस कोरोना काल में काफी त्रस्त होता।

26 मार्च के बाद मोदी ने अपने अगले कोविड-19 पैकेज के लिए राष्ट्र को संभलने का मौका दिया। और इस दौरान वह पैकेज को छोड़कर हर चीज के बारे में बात कर रहे थे। 12 मई को जनता की उत्सुकता बढ़ने के बाद, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की - इसका अधिकांश जोर अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुधारों के साथ राहत देने के लिए, जो उत्साह प्रधानमंत्री मोदी ने उत्पन्न किया था उसे अगले पांच दिनों तक जीवित रखा। इन पांच दिनों में वित्त मंत्री ने सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की।

इसमें 3 लाख करोड़ रुपए गरंटी मुक्त ऋण, 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी और 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज और 75,000 करोड़ रुपए एनबीएफसी को राहत, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं और मुद्रा लोन के लिए 6,500 करोड़ रुपए का ऋण - सभी एमएसएमई के लिए कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये दिए गए। प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन, मछुआरों के लिए प्रावधान, पशुपालन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, 49,000 करोड़ रुपये की राशि और मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये, सभी गरीबों के लिए, 89,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कृषक वर्ग के लिए, कृषि ऋण और कृषि इन्फ्रा के रूप में 330 लाख और सोर्स डिफरेंस पर 50,000 करोड़ रुपये की कर कटौती, सरकार द्वारा 9,550 करोड़ रुपये का पीएफ भुगतान और 70,000 करोड़ रुपये का हाउसिंग लोन - मध्यम वर्ग के लिए 1,29,550 करोड़ रुपये। यहां तक कि उनके विरोधियों ने भी बयान जारी कहा कि सरकार ने अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं किया है, मोदी ने वास्तव में अपने लक्षित वर्ग को राहत दी है.।

जिन महिला लाभार्थियों के खाते में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई गई थी, उनमें से लाभार्थियों ने आधी राशि को निकाल लिया है, यह दर्शाता है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभाव नहीं हुआ है। एक और अच्छी खबर यह है कि पीएमजेडीवाई खातों में लॉकडाउन के दौरान जमा में वृद्धि देखी गई है।

एमएसएमई को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनको मिलने वाले कर्ज गारंटी के साथ है या नहीं। सरकार के लिए असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वादा किया गया ऋण वितरित किया जाए। मोदी अपने पैकेज की अवधारणा और संचार में रणनीतिक रहे हैं। येचुरी कहते हैं कि यह सभी अमीरों के लिए है, ऐसा कब था जब अमीरों के लिए प्रावधान नहीं किए जाते थे। जैसा कि चिदंबरम कहते हैं कि यह एक खाली कागज है, मोदी ने वास्तव में सभी को अधिक से अधिक राहत देने का काम किया है।

प्रोत्साहन पैकेज पर कुछ अंतिम शब्द

अब, कुछ अच्छी खबर। जिन महिला लाभार्थियों के खाते में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई गई थी, उनमें से लाभार्थियों ने आधी राशि को निकाल लिया है, यह दर्शाता है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभाव नहीं हुआ है। एक और अच्छी खबर यह है कि पीएमजेडीवाई खातों में लॉकडाउन के दौरान जमा में वृद्धि देखी गई है। 1 से 7 अप्रैल के बीच 8,000 करोड़ रुपये जमा हुए। और 15 मई तक, यह 8,000 करोड़ रुपये और बढ़ गया - 45 दिनों के लॉकडाउन में कुल 16,000 करोड़ रुपये इन खातों में जमा करवाए गए। इसकी तुलना में, पूरे 2019 के दौरान, पीएमजेडीवाई बचत केवल 26,000 करोड़ रुपये बढ़ी थी। एक तरह से यह बुरी खबर है - लेकिन यह बुरा नहीं है - कि वे बचत कर रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे हैं और इस हद तक कोई मांग नहीं है।

अंत में, क्या यह मोदी पैकेज अब अंतिम होगा? ऐसा लगता नहीं है। कोविड-19 की चुनौती लगातार जारी है। कोई नहीं जानता कि इससे और कितना नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि मोदी जी ने अपने अंतिम विकल्पों को खुला रखा है जैसा कि जी-7 कर रहे है। आरबीआई गवर्नर की ओर से एक संकेत आया है कि उन्होंने घाटे के विमुद्रीकरण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, अर्थात् सरकार आरबीआई से उधार ले रही है। यह वास्तव में सही रणनीति है। ■

(लेखक प्रख्यात स्तंभकार एवं चिंतक हैं)

'लोकल के लिए वोकल' का संकल्प

अनुराग ठाकुर

किसी भी देश की खुशहाली का पहला पैमाना सरकार व जनता के बीच कैसा सम्बन्ध है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सरकार व जनता के बीच का रिश्ता राजा-प्रजा के बजाय आदेशक व सेवक का होना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे देश के पास प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं जिसने पिछले 6 वर्षों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता के साथ 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की बिना रुके बिना थके सेवा की है।

30 मई 2019, पांच वर्षों तक सेवा, साधना और सर्वकल्याण के प्रति समर्पित रहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्वयं के बजाय समूह का भाव होने पर ही जन कसौटी पर खरा उतरा जा सकता है। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने राजसत्ता की परिभाषा ही बदल दी है। पारदर्शी नीति और जनहितकारी कार्यों से देश के जनमानस में राजनीतिक विश्वास का वातावरण निर्मित हो सका। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम में पहले से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत उसी का नतीजा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ही चुनौतियों से हुई है। परन्तु ईमानदार सोच और राष्ट्रहित की भावना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने चुनौती को अवसर के रूप में लिया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर के बीच वैश्विक महामारी कोविड-19 से जहां दुनिया के कई देशों की आर्थिक गाड़ी डगमगा गई है, वहीं देश के गरीब, किसान, छोटे उद्यमियों के लिए 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने के साथ मोदीजी ने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का अचूक मंत्र दिया है।

सत्ता की दूसरी पारी के आरंभ में ही ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए, जिससे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार का यह कार्यकाल कैसा रहने वाला है। जिस तरह क्रिकेट में ओपनिंग के दौरान लक्ष्य निर्धारण कर रन रेट ज्यादा रखा जाता है, उसी तर्ज पर केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने टीम मोदी के ओपनिंग वैट्समैन के रूप में पिच पर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। देश के लिए नासूर बना धारा-370 और 35 (ए) का ऐसा शर्तिया इलाज किया गया, जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशप्त तीन तलाक पर सख्त कानून बनाकर उन्हें गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र कराया। मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में भारत के नवनिर्माण का लक्ष्य रखा था। इसके लिए देश में विदेशी पूंजी निवेश, ढांचागत निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का खाका तैयार किया गया है। लेकिन अभी पहली तिमाही पूरी नहीं हुई थी कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दस्तक दे दी। इस संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन भारत का नेतृत्व मोदी जी जैसे सक्षम व्यक्ति के हाथ में होने के कारण हम अन्य देशों की तुलना में इस महामारी के लपेटे में कम रहे। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा आबादी होने के बाद भी मोदीजी के दूरदर्शी निर्णय के कारण भारत में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम है। कोरोना हमारे लिए चुनौती के साथ अवसर पैदा किया है। हम पीपीई और मास्क निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। देश में जहां पीपीई और मास्क का निर्माण बिलकुल नहीं होता था, वहीं अब भारत प्रतिदिन 5 लाख पीपीई किट तथा 5 लाख मास्क-95 का निर्माण कर रहा है।

दुनिया के 15 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा आबादी होने के बाद भी मोदीजी के दूरदर्शी निर्णय के कारण भारत में संक्रमण और मृत्यु दर बहुत कम है। कोरोना हमारे लिए चुनौती के साथ अवसर पैदा किया है। हम पीपीई और मास्क निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं।

संकट की इस घड़ी में केन्द्र सरकार ने सारी योजनाओं को किनारे रख मानव सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिसमें लॉकडाउन लगाकर कोरोना के संक्रमण के विस्तार को रोकने का कदम उठाया गया, वहीं देश के गरीबों के लिए दाल-रोटी की चिंता की गई। केन्द्र सरकार ने अनाज प्रबंधन अपने हाथ में लेते हुए सभी 80 करोड़ लोगों को 5 महीने के लिए कुल 25 किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और 5 किलो दाल देने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण उस वर्ग के सामने भी समस्या पैदा हो गई थी, जो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो माह तक चावल, गेहूं और दाल देने का काम शुरू कर दिया। केन्द्र सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के भोजन के साथ उनकी घर वापसी की भी चिंता की गई और इसके लिए रेलवे द्वारा श्रमिक एक्सप्रेस चलाकर लाखों श्रमिकों उनके घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों के किराए का 85 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार दे रही है। साथ ही, श्रमिकों को सफर के दौरान भोजन-पानी की प्रबंध भी केन्द्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देश के नवनिर्माण में श्रमिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार की तरफ से हर स्तर पर उनकी चिंता की जा रही है। श्रमिकों की घर वापसी के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत एक लाख

एक हजार करोड़ का बजट तय किया गया है। मनरेगा के तहत मिलने वाले श्रम में भी सरकार ने बढ़ोतरी कर 182 रुपये प्रतिदिन की जगह पर 202 रुपये की मजदूरी तय कर दी है। यह सब सरकार की तरफ से इसलिए किया गया, ताकि श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट पैदा न हो। कोरोना संकट के इस दौर में केन्द्र सरकार ने गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक जून से राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी 'वन नेशन-वन राशन' कार्ड लागू किया जा रहा है। इसमें अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी को कवर किया जाएगा। इस योजना में एक राशन कार्ड पर राशनकार्डधारी देश के किसी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। इससे देश के 80 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारी लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, केन्द्र सरकार की तरफ से लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए 20 करोड़ जनधन खाता में 21 हजार करोड़ की धनराशि जमा कराई गई है। उज्ज्वला योजना के तहत गांव की 7 करोड़ गरीब महिलाओं को दिए गए गैस कनेक्शन में 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेण्डर के साथ 9 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी की राशि उनके खातों में जमा कराई गई है।

किसान देश का अन्नदाता है। किसान को वैश्विक और प्राकृतिक दोनों तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ा है। केन्द्र सरकार द्वारा किसान को चिंता से उबारने के लिए 9 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल माह में 18 हजार करोड़ रुपये की धनराशि जमा कराई गई है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि किसानों को दी गई है। कर्ज लेने वाला किसान आर्थिक परेशानी महसूस नहीं करे, इसके लिए सरकार की तरफ से कर्ज की किस्त चुकाने के लिए 6 माह की छूट भी दी गई है। साथ ही, कम ब्याज दर पर ऋण के लिए 86 हजार करोड़ रुपये किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दी। सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन के रखरखाव के लिए कई तरह के उपाय शुरू किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज चैन, वेयरहाऊस, फ्रूड प्रोसेसिंग केन्द्र और अन्य भंडारण गृह के लिए एक लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है। सरकार की तरफ से किसानों को जैविक और हर्बल खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल की खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर भी उत्पाद बेच सकें उसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों को बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव होगा। इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी।

कोरोना संकट के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से कर्मचारी और लघु, सूक्ष्म, मध्यम व्यापारियों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। कर्मचारी भविष्यनिधि जमा करने के प्रावधान पर नियोक्ता और कर्मचारियों को राहत देते हुए 6 माह तक दोनों के हिस्से की 12-12 प्रतिशत की ईपीएफ की राशि सरकार भरेगी। कर्मचारियों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर कर्मचारी को 75 प्रतिशत धनराशि निकालने की छूट दी गई है। केन्द्र सरकार की 100 प्रतिशत गारंटी पर अब लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों को मजबूती देने के उद्देश्य से 3 लाख करोड़ रुपये का पैकेज मात्र 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया है जिससे व्यापारियों को 20 प्रतिशत अधिक कार्यशील पूंजी बिना कोई गारंटी एवं कॉलेटरल के मिलेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में करीब 28 फीसदी और कुल निर्यात में करीब 40 फीसदी का योगदान है। देश में यह सेक्टर कृषि के बाद सबसे ज्यादा करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा लोन डिफाल्ट वाली एमएसएमई को राहत देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के सबोर्डिनेट कर्ज का ऐलान किया गया है। इससे करीब 2 लाख कारोबारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एमएसएमई में Equity Infusion के लिए 50,000 करोड़ रुपये का एक फंड्स का फंड भी बनाया जाएगा। ज्यादा निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन करेगी। अब सूक्ष्म उद्योग की टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक, लघु उद्योग की टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये तक एवं मध्यम उद्योग की टर्नओवर सीमा को 100 करोड़ रुपये तक कर दिया है। इसके अलावा एमएसएमई की मदद के लिए 200 करोड़ रुपये तक ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे। इससे स्थानीय कारोबारी कम्पनियों को मौका मिल सकेगा।

अब सूक्ष्म उद्योग की टर्नओवर सीमा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक, लघु उद्योग की टर्नओवर सीमा को 50 करोड़ रुपये तक एवं मध्यम उद्योग की टर्नओवर सीमा को 100 करोड़ रुपये तक कर दिया है। इसके अलावा एमएसएमई की मदद के लिए 200 करोड़ रुपये तक ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे। इससे स्थानीय कारोबारी कम्पनियों को मौका मिल सकेगा।

इस वैश्विक मंदी के दौर में जब दुनिया के तमाम देश आर्थिक संकट से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत ने 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज एवं सुधार लाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश को विश्वास है कि हर कठिन चुनौती का सामना करके उससे बाहर निकलने की सामर्थ्य रखने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे रचनात्मक दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी सोच वाले नेतृत्व के हाथ में देश न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि समृद्धि की दिशा में भी दुनिया से आगे निकलेगा। क्योंकि पिछले पांच साल में मोदीजी ने भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि का निर्माण किया है, उससे दुनिया के कई देश अब भारत की तरफ आशाभरी नजरों से देखने लगे हैं। मोदीजी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल के लिए वोकल एवं लोकल से ग्लोबल का स्लोगन देकर अपना देश, अपनी माटी के प्रति देशवासियों को नया मूलमंत्र दिया है। ■

(लेखक केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हैं।)

एमएसएमई: भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन

प्रताप चन्द्र षड़ंगी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत वाले एमएसएमई से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में मदद मिलती है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आती है और राष्ट्रीय आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। एमएसएमई प्राथमिक रूप से सहायक इकाइयां हैं और बड़े उद्योगों की पूरक हैं। देश के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योगों सहित एमएसएमई सेक्टर के विकास और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्थापना की गई है।

विकास और कार्यनिष्पादन

पिछले वर्षों के दौरान, एमएसएमई सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक जीवंत और गतिशील सेक्टर के रूप में उभरा है जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान लगभग 30% का रहा है। यह सेक्टर देश में रोज़गार, विनिर्माण आउटपुट और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई सेक्टर में अनुमानतः 11.10 करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त है जो कि कृषि के बाद आने वाला का अग्रणी क्षेत्र है। अनुमान है कि लघु सेक्टर में स्थायी परिसंपत्तियों में एक लाख रुपए निवेश करने पर चार व्यक्तियों के लिए रोज़गार सृजित होते हैं। केवल यही क्षेत्र ऐसा है जो स्वरोज़गार और मजदूरी-रोज़गार दोनों के लिए ही अधिकतम अवसरों का सृजन करता है। मूल्य की दृष्टि से, देश के विनिर्माण आउटपुट के लगभग 33 प्रतिशत और कुल निर्यात के 48 प्रतिशत का योगदान इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। एमएसई सेक्टर से निर्यात संवर्धन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अपने उत्पादों के निर्यात में एमएसएमई की मदद करने के उद्देश्य से एमएसएमई निर्यातकों को वरीयता दी गई है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी कर सकें: पैकेजिंग, सेक्टर विशेष के मार्केटिंग इनपुटों और अन्य निर्यात संबंधी अपेक्षाओं के क्षेत्र में एमएसएमई निर्यातकों को प्रशिक्षण और एक्सपोज़र प्राप्त हो।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के अंतर्निहित फायदों को मान्यता दी है और स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे बहुत से नवप्रवर्तनकारी नीतिगत इंटरवेशनों के माध्यम से नए एमएसएमई की स्थापना और उद्यमिता क्रांति का प्रसार किया है।

एमएसएमई सेक्टर न केवल आर्थिक विकास में बढ़-चढ़ कर योगदान करता है बल्कि ये कम लागत पर गैर-कृषि आजीविका सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक संतुलन, हरित विकास और सबसे बेहतर ढंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास का कायम रखने के माध्यम से अनगिनत पद्धतियों द्वारा समेकित (inclusive) और टिकाऊ समाज (ससटेनिबल सोसाइटी) का निर्माण करता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के अंतर्निहित फायदों को मान्यता दी है और स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे बहुत से नवप्रवर्तनकारी नीतिगत इंटरवेशनों के माध्यम से नए एमएसएमई की स्थापना और उद्यमिता क्रांति का प्रसार किया है। नए उद्योगों को व्यवसाय जमाने के लिए प्रोत्साहन देने और मौजूदा उद्योगों को पनपने के और मौके दे कर एमएसएमई इकोसिस्टम की स्थापना किए जाने के लिए सजग रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, आज हमारे देश में छह करोड़ से अधिक एमएसएमई मौजूद हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है- महिला उद्यमियों से सहज संवाद (इज़ी इंटरफेस) कायम होना। आज देश में कुल 1.24 करोड़ इकाइयां महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली है।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

यह महसूस किया गया है कि एमएसएमई के पास सृजित औद्योगिक आधार के मद्देनज़र और एमएसएमई पर निरंतर बनाई प्रेरक नीतियों के मद्देनजर विकास की अपार संभावनाएं हैं। अनुभव से पाया गया है कि एमएसएमई की विभिन्न बाधाओं का समाधान किए बिना इस क्षेत्र का विकास रुक सकता है और गतिहीन भी हो सकता है। इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एमएसएमई की क्षमताओं में वृद्धि हेतु वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और एमएसएमई को विपणन सहायता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

सरकार हमेशा से ही एमएसएमई के विकास के प्रति संवेदनशील रही है और इसलिए सरकार ने वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और विपणन के क्षेत्र में एमएसएमई की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। हालांकि एमएसएमई के लिए प्रेरक बिजनिस इकोसिस्टम के सृजन हेतु व्यापक स्तरीय उपाय

कर लिये गये हैं और वर्ष 2020-21 में बजटीय आबंटन में वृद्धि की गई है, वहीं एमएसएमई मंत्रालय ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने और एमएसएमई क्षेत्र में उथल-पुथल से बचने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली हैं।

एमएसएमई पर कोविड–19 का प्रभाव

कोविड-19 और इसके परिणामी लॉकडाउन की वजह से देश भर के लाखों लघु उद्योगों पर तगड़ी मार पड़ी है। अपने आकार, प्रचालन पैमाने, सीमित वित्त और प्रबंधन संसाधनों की वजह से, विशेष रूप से एमएसई सहित एमएसएमई इस महामारी से आई बाधाओं से जूझ नहीं पा रहे हैं। देश में हुए लॉकडाउन की वजह से इस क्षेत्र के घटते निर्यात, उत्पादन बंदी, मजदूरों की अनुपलब्धता, उपभोग की अनिश्चितता और बाज़ार में पूंजी तरलता के समाप्त होने के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रभावित क्षेत्र में पहले से ही लाखों लोग बेरोज़गार हैं और बहुत से उद्योग हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं।

कोविड-19 के प्रभाव के कारण एमएसएमई की कठिनाइयों पर उचित रूप से विचार करने के बाद, सरकार ने एमएसएमई को नवजीवन प्रदान करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज ज़ारी किया है और इस प्रक्रिया से हमारी अर्थव्यवस्था फिर उठ खड़ी होगी, जो कि इस क्षेत्र में व्याप्त अप्रत्याशित झटकों का सामना कर रही है।

एमएसएमई के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

वित्त की उपलब्धता एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वर्तमान परिस्थिति में बुरी तरह प्रभावित है, इसमें विशेष रूप से कार्यशील पूंजीगत ज़रूरतों को पूरा किया जाना शामिल है। एमएसएमई पर अत्यधिक मार पड़ी है और इन्हें सृजित प्रचालन दायित्वों की पूर्ति, कच्चे माल की खरीद और उद्योग फिर से शुरू करने के लिए अतिरिक्त वित्त की जरूरत है। इसलिए सरकार ने एमएसएमई के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमएसएमई समेत बिजनिस के लिए 3 लाख रु. तक का कोलेट्रल-फ्री आटोमैटिक ऋण।तनावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. तक का अनुषंगी ऋण (सबऑरडिनेट डेबिट)।
- निधियों के कोष (फंड ऑफ फंडस) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी इनफ्यूजन।
- एमएसएमई की नवीन टर्नओवर आधारित परिभाषा।
- 200 करोड़ रु. तक के वैश्विक टैंडरों की मनाही।
- एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के स्थान पर ई-मार्केट लिंकेज।
- सरकार और सीपीएसई से एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाली निधियां 45 दिन में ज़ारी की जाएंगी।

इन उपायों में यह सम्भावनाएं हैं जिससे एमएसएमई महामारी के दुष्प्रभावों के बावजूद फिर से उठ खड़ी होंगी। इस प्रोत्साहन से बहुत सी इकाइयों में कार्य फिर से शुरू हो जाएगा और ये क्रमिक रूप से बिजनेस कार्य पर लौट आएंगी। अनुषंगी ऋण निधि और निधियों के कोष में यह संभावना मौजूद है कि ये एमएसएमई की लंबी अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। एमएसएमई के इतिहास में ये ऐसे अप्रत्याशित निर्णय हैं जिनसे इन्हें और अधिक विलक्षण बनाते हुए और वित्त के भरोसेमंद स्रोत के लिए एकीकृत करते हुए इनकी प्रोफाइल में बढ़ोतरी की गई है।

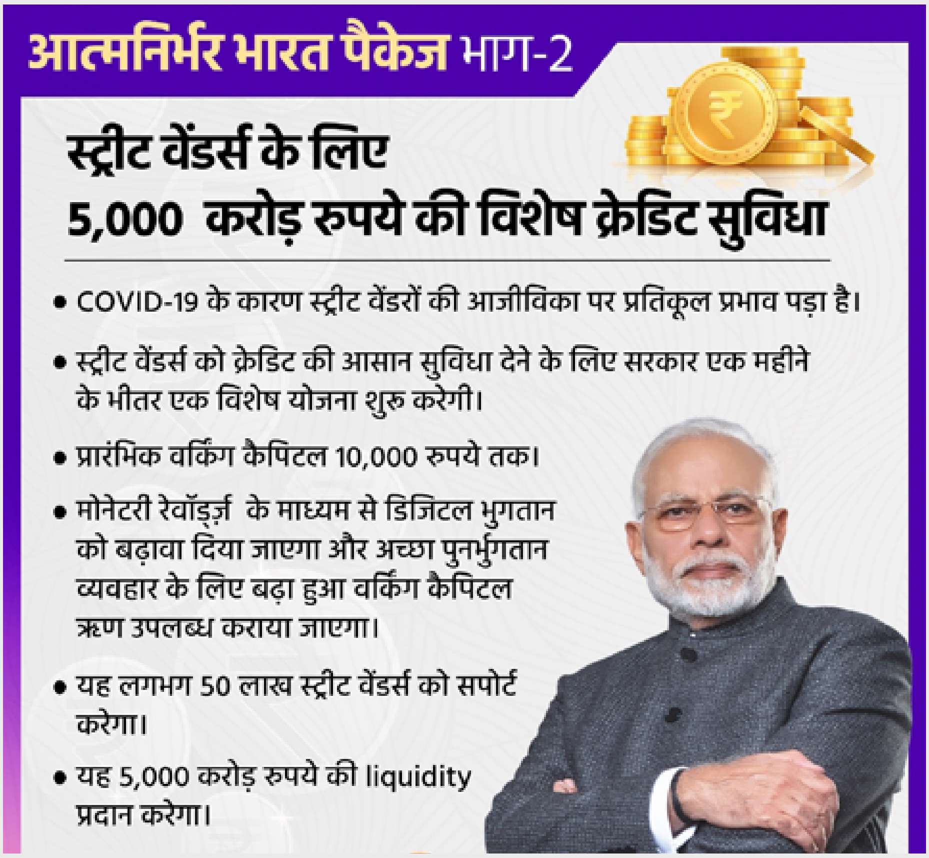

निष्कर्ष:

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई ने बड़ा विकास किया है और उन नीतिगत फ्रेमवर्क के योगदान और उपयुक्त पहलों के साथ उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन भी किया है जिन्हें एमएसएमई के विकास एवं प्रगति के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अपनाया गया है। पोस्ट कोविड-19 की स्थिति में सरकार पहले से और अधिक प्रतिबद्ध बनी रहेगी ताकि एमएसएमई का विकास करने और बेहतर होने के लिए अधिक सुरक्षित और बेहतर इको-सिस्टम दिया जा सके। माननीय प्रधान मंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को साकार करने का दायित्व मुख्य रूप से हमारे एमएसएमई के कंधों पर ही है। ■

(लेखक केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं)

नारीशक्ति के दम पर बढ़ता नया भारत

विजया रहाटकर

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं पत्रकारिता; ये चार स्तंभ हैं लोकतंत्र के। कोई भी यह बताएगा। लेकिन जो आबादी का आधा हिस्सा है और जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, उस महिला सक्षमीकरण के चार स्तंभ कोई बता पाएगा?

शायद नहीं! अगर हमें ये चार स्तंभ ही पता नहीं, तो हम उस दिशा में कैसे प्रयास कर पाएंगे? शायद पिछले 60-70 सालों मे ऐसा ही हुआ। सरकारें आयीं, चली गयीं, लेकिन महिलाओं को केंद्र में रखकर ना नीतियां बनायी, ना कार्यान्वयन किया गया। सक्षमीकरण एवं उत्थान की बातें सिर्फ महिला दिन को अखबारों की पन्नों में, राजनेताओं के भाषणों में एवं सरकार के 'विजन डॉक्युमेंट' में रह गयीं। क्यों कि महिला कभी भी 'वोट बैंक' नहीं थी।

'चलता है...' इस ऐटिट्यूट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार धक्का दिया सन 2014 में सरकार बनने के बाद। मोदी जी की पहली बड़ी पहल थी- जन धन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ..! दोनों की प्राथमिकता थी सिर्फ महिलाएं। आज गरीब महिलाओं के लगभग 20 करोड़ बैंक खाते हैं और हरियाणा जैसे प्रदेश जो लिंगानुपात में पीछे थे, लिंगानुपात 840 से बढ़कर 935 तक पहुंचा है। मोदी जी सिर्फ यहां नहीं रुके और धीरे धीरे महिलाकेंद्री योजनाओं का कारवां बढ़ता गया। महिला सक्षमीकरण के चार स्तंभ सुनिश्चित किए गए। सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सक्षमीकरण एवं आर्थिक सक्षमीकरण ये वो चार स्तंभ। इन्हें सामने रखकर अनेक कदम उठाए गए। उन्होंने न सिर्फ योजनाएं बनाईं, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूरा जोर दिया। बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा-दीक्षा, पोषण, कौशल एवं सार्वभौमिक विकास हेतु क्रमबद्ध तरीके से विविध योजनाओं को जमीन पर उतारा गया।

सबसे अहम थे सुरक्षा के प्रावधान। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के रेप पर फांसी का प्रावधान किया गया। कानून में बदलाव करके ज्युडिशियल प्रोसेस सात-आठ महीनों में खत्म करने की समय सीमा निश्चित की गयी। इसकी वजह से अनेक राज्यों में दो-तीन महीनों में ही दुष्कर्मी के दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। एंटी ट्रैफिकिंग विधेयक लाया गया, निर्भया फंड का कारगर तरीके से उपयोग शुरू किया, हिंसा की शिकार हुई महिलाओं के लिए 300 से ज्यादा 'वन स्टॉप सेंटर्स' खोले गए, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 700 से ज्यादा स्वाधार गृह बनाए गए।

> **मोदी जी की पहली बड़ी पहल थी- जन धन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ..! दोनों की प्राथमिकता थी सिर्फ महिलाएं। आज गरीब महिलाओं के लगभग 20 करोड़ बैंक खाते हैं और हरियाणा जैसे प्रदेश जो लिंगानुपात में पीछे थे, लिंगानुपात 840 से बढ़कर 935 तक पहुंचा है।**

मातृत्व की रक्षा भविष्य की सुरक्षा होती है, ये सबको पता है। लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। मोदी जी अपवाद रहें। सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया। हजारों स्वास्थ्य केंद्रों में ढाई करोड़ से ज्यादा गर्भावस्था जांच की गई, 8 लाख से ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता लगाया गया। प्रधानमंत्री मातृवंदना के तहत हर प्रेगनेंट महिला को 6000 रुपयों की वित्तीय मदद दी। मिशन इंद्रधनुष में माता और छोटे बच्चों का टीकाकरण शुरू किया। उसका दायरा बढ़ाया, विस्तार कर के 5 नए टीके (मीजल्स, रूबेला, नेयुमोकोकल रोटावायरस, इनएक्टिव्हेटेड पोलियो और जापनीज इन्सेफाइलिटीस) बढ़ाए गये। इसका लाभ करोड़ों माता और बच्चों को हो रहा है। नौ हजार करोड़ का राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया। उसका लाभ लाखों माताओं को मिल रहा है। आगे जाकर और एक अहम कदम मोदी जी ने उठाया। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तों का कर दिया। प्रसूति उपरांत माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ये 26 हफ्ते कितने आवश्यक होते हैं, ये कोई भी कामकाजी महिला बताएगी। इन सभी कदमों से माता मृत्यु दर में लगभग 30 प्रतिशत की कमी पाई गई। 2011-13 में माता मृत्यु दर 167 थी, जो 2016-18 के दौरान लगभग 110-120 तक घटी।

महिलाओं के सामाजिक सक्षमीकरण के लिए मोदी जी ने जितने कदम उठाए, शायद अभी तक किसी ने नहीं उठाये होंगे। उज्ज्वला योजना इस सामाजिक सक्षमीकरण की बड़ी मिसाल है। गरीब दलित, आदिवासी महिलाओं को मुफ्त रसोई सिलिंडर देने की इस योजना ने अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। घुट-घुट कर जीने के बजाय स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका 'उज्ज्वला' ने साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा महिलाओं, बच्चों को दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में न सिर्फ प्राथमिकता दी, बल्कि मकान की मालिक या फिर सहस्वामिनी बनाया। सिर्फ इस एक कदम ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया, आत्मनिर्भर किया। स्वच्छ भारत में मिशन मोड पर बनाए दस करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने करोड़ों महिलाओं को शर्मिंदगी मुक्त किया। यही स्कूलों में हुआ, जब पांच लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ बालिकाओं को अब शर्मिंदगी का भय नहीं सताता।

तीन तलाक कानून तो मोदी जी के लिए crowning glory है। सदियों पुरानी इस कुप्रथा से करोड़ों मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाना आसान बात नहीं थी। मुल्ला मौलवी के साथ-साथ उन्हें प्रोटेक्शन देनेवाली छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का विरोध को देखते हुए मोदी जी ने दिखाई राजनैतिक इच्छाशक्ति का कोई तोड़ नहीं। इस दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए मुस्लिम बहनें हमेशा मोदी जी की ऋणी रहेगी। ऐसा ही एक निर्णय लिया, जो मुस्लिम महिलाओं को और सशक्त होने का एहसास दिलायेगा। आजादी के बाद पहिली बार हज नीति बनाकर मेहरम (पुरुष अभिभावक) बिन हज यात्रा को जाने की अनुमति महिलाओं को दी गई। शिक्षा

का महत्व ध्यान में रखते हुए तीन करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बालिकाओं को शिष्यवृत्ति दी जा रही है।

अगर आर्थिक सक्षमीकरण नहीं हो, तो शायद सामाजिक सक्षमीकरण का ज्यादा उपयोग नहीं होता है। इसलिए मोदी जी की महिला नीतियों मे आर्थिक सक्षमीकरण के पर ज्यादा बल दिया है। जैसाकि पहले जिक्र किया, जन धन योजना ने 20 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं के बैंक खाते खुले। अब इन खातों मे एक लाख करोड़ से ज्यादा धन संचय इन गरीब महिलाओं ने किया है। मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा फायदा तो महिलाओं ने लिया है। 25 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए, उसमें 17-18 करोड़ महिलाएं हैं। इस एक ही योजना ने आर्थिक सक्षमीकरण की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया। सुकन्या समृद्धि योजना हो, स्टैंडअप इंडिया हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देनी हो, महिला 'ई-हाट' हो, 'एमएसएमई' में बिजनेस वुमेन्स को बढ़ावा हो... मोदी जी ने उन्हें आर्थिक ताकत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

जब विश्व महिला विकास की (सिर्फ) बातें कर रहा है, तब मोदी जी आगे बढ़कर महिला नेतृत्व में विकास (Women Led Development) की बातें कर रहे हैं। उसे धरातल पर लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाल में कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई। अगर आप ध्यान से उसे देखेंगे तो आराम से पता लगेगा, मोदी जी ने महिलाओं पर ही भरोसा रखा है! जन धन की 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने पांच सौ रुपए, आठ करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला लाभार्थियों को तीन रसोई सिलिंडर मुफ्त, स्वयं सहायता समूहों को सस्ता और दोगुना लोन।

नारीशक्ति को सशक्त और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदारी देने के लिए मोदी जी ने पिछले छह सालों मे जितनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उतनी विगत 60 सालों में किसी ने नहीं दिखाई। मोदी जी ने यह करके दिखाया, क्यों कि 'मोदीनॉमिक्स' का मूलाधार ही नारीशक्ति है।

ये दर्शाता है कि मोदी जी बना रहे नया भारत। यह नारीशक्ति के दम पर बढ़ता भारत है। चाहे खेल-कूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान... हमारी नारीशक्ति किसी से पीछे नहीं हैं। कोरोना फायटर्स में भी महिलाएं सबसे आगे हैं। वे हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और अपनी उपलब्धियों से भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। नारीशक्ति को सशक्त और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदारी देने के लिए मोदी जी ने पिछले छह सालों मे जितनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उतनी विगत 60 सालों में किसी ने नहीं दिखाई। मोदी जी ने यह करके दिखाया, क्यों कि 'मोदीनॉमिक्स' का मूलाधार ही नारीशक्ति है। मोदी सरकार-2 के एक साल पूरे होने पर टीम मोदी को लाख-लाख बधाइयां। मन में पूरा विश्वास है कि आगे भी महिलाओं को और सबल बनाने के दिशा में बेहतर कदम पड़ते रहेंगे। ■

(लेखिका भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

आत्मनिर्भर भारत : चुनौतियां एवं अवसर

संकट में ही छुपे अवसर!

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा करने जा रही है। 2019 का जनादेश ऐतिहासिक था। 35 साल बाद किसी सरकार को इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अभूतपूर्व जनादेश निश्चित ही आत्मविश्वास देता है और कई चुनौतियां भी लेकर आता है।

हमारे पिछले पांच वर्षों के शासन काल में आशा की किरण दिखी थी। जो एक पारदर्शी और समान अवसर वाली पारिस्थितिकी तंत्र वाले संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को इंगित करती है। धन की केन्द्रीयकृत प्रवृत्ति, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सामाजिक वितरण तंत्र में रिसाव और कर संग्रह में अनियमितता अब इतिहास का हिस्सा बन चुके है। मोदी जी कभी केवल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने नहीं आए; उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन किए। चुनौतियां को हमेशा एक अवसर मानकर उन्होंने हर समस्याओं का दृढ़ता से सामना किया।

दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी कम विकट नहीं रहा है। सरकार का ध्यान जीवन यापन में सुगमता, अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करना और सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धता पर अधिक केन्द्रित रहा।

क्षमताओं का निर्माण: सरकार हमेशा से क्षमताओं के निर्माण के लिए तकनिकों का उपयोग करती रही है। मोदी जी समस्या की पहचान करते है, तकनीकी समाधान बनाते हैं; हितधारकों को पूरे तंत्र के साथ जोड़ते हैं और कार्य मूल्यांकन के लिए व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

कोविड-19 संकट ने राज्य की जनलाभकारी क्षमता के पहलू पर सबका ध्यान केंद्रित किया है। सुशासन, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से राज्य की इस क्षमता में बड़े पैमाने पर सुधार लाया जा रहा है। आधार कार्ड पर आधारित भारत की डिजिटल पहल ने अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम की है। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं का पूरा पोषण हो रहा है।

वैचारिक प्रतिबद्धता: इस वर्ष में विचारधारा को अन्य चीजों पर वरीयता प्राप्त हुई है। श्री अमित शाह जी ने ठीक ही कहा कि हम केवल शासन के लिए दूसरे कार्यकाल में नहीं चुने गए हैं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए चुने गए हैं। ऐसी कुछ ऐतिहासिक समस्याओं से भारत त्रस्त था। अनुच्छेद 370 को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अस्थायी प्रकिया के रूप में स्थान दिया था, वह हमें स्थायी रूप से दिन-रात परेशान करता रहता था। हम जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा होने का गुणगान तो करते थे, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। पहले के नेतृत्व में न तो साहस था और न ही ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने का उत्साह था। मोदी सरकार ने इसे एक झटके में हटा दिया। लोग आश्चर्यचकित थे कि हम इतने वर्षों से क्या इन्तजार कर रहे थे? नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाना, रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा या राष्ट्रीय जनसांख्यिकी रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर काम इस बात को इंगित कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है।

> **अनुच्छेद 370 को हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने एक अस्थायी प्रकिया के रूप में स्थान दिया था, वह हमें स्थायी रूप से दिन-रात परेशान करता रहता था। हम जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा होने का गुणगान तो करते थे, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। पहले के नेतृत्व में न तो साहस था और न ही ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने का उत्साह था।**

दूसरा बजट: यह बजट पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए एक रोडमैप तैयार करने में मील का पत्थर है। इस बजट में आर्थिक विकास के तहत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे तकनीकि परिधान केंद्रों, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने केंद्र, राज्य और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से वित्तपोषण के लिए 6500 परियोजनाओं की पहचान करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ रुपये के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना के तंत्र को स्वरूप दिया। सरकार ने विदेशी संप्रभु ऋण कोष से निवेश प्राप्त करने के लिए रुपये और बांड बाजारों को खोला है, जिससे विनिमय में उतार-चढ़ाव के खिलाफ मजबूती प्राप्त की जा सकें।

यह बजट व्यापक धन सृजन, व्यावसायिक नीतियों और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर केंद्रित है। संसाधन की आवश्यकता पूर्ति के लिए इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इसमें करदाता के अधिकार चार्टर की घोषणा कर प्रशासन के भीतर जवाबदेही लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है। करदाता के अधिकार का प्रावधान दुनिया भर में केवल तीन अन्य देशों में मौजूद है।

आरसीईपी (RCEP), एफटीए (FTA) और आयात शुल्क: कॉर्पोरेट करों में 25 प्रतिशत कमी, कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापक बदलाव, घरेलू इकाईयों के सरक्षा के लिए आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार, आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार

समझौता (एफटीए) पर पुनः विचार और आठ खंडों में आयात शुल्क बढ़ाना; सरकार के सभी कदम उद्योगों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा के हमले से बचाने की दिशा में थे।

कोरोना चुनौतियां: कोविड-19 एक नई घटना है, जो अनिश्चितता से भरपूर है। वैश्विक मंदी की गंभीर चुनौती के बावजूद सरकार के सभी हस्तक्षेप सराहनीय हैं। आर्थिक अनिश्चितता, नौकरियों की अनियमितता और वित्तीय समस्याओं के कारण अर्थव्यवस्था में मांग कम हो रही है, इसलिए, सरकार का ध्यान मांग को बढाने पर है।

आत्मनिर्भर भारत: गैर-वैश्वीकरण की प्रवृत्ति, जो वैश्विक वित्तीय संकट (2008) के बाद शुरू हुई और 2016 के अमेरिकी चुनावों के बाद जिसे बढ़त मिली, उस प्रवृत्ति में और तेजी आ सकती है। भारत महत्वपूर्ण उत्पादों और क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्पादन के सभी कारकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, हम आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत आर्थिक सुधार, घरेलू उद्योगों को अभूतपूर्व तरीके से प्रतिस्पर्धी एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेंगे। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुछ चुनौतियां हैं; जैसे ब्याज दर कम करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी, श्रम सुधार, अनुपालन में आसानी, अनुबंध प्रवर्तन और एफडीआई नीति। इन क्षेत्रों में विस्तृत सुधार निम्नानुसार हैं;

निजी पूंजी निर्माण: इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्याज पर जोखिम प्रीमियम कम हुआ है और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो दर में लगातार कमी ने प्रमुख उधार दर को नीचे ला दिया है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति: वर्तमान में लॉजिस्टिक क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 14-15 प्रतिशत है, जहां विकसित देशों में यह लगभग 9-10 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए परिवहन लागत लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने 2022 तक इसे नीचे लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है।

श्रम कानून सुधार: श्रम सुधारों की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने मौजूदा कई श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने का फैसला किया है। श्रम सुधारों के अनुपालन में ढील देने और मजदूर कल्याण को आसान बनाने, निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुविधा तैयार करने और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी पहल शामिल है।

> **श्रम सुधारों की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने मौजूदा कई श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने का फैसला किया है। श्रम सुधारों के अनुपालन में ढील देने और मजदूर कल्याण को आसान बनाने, निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुविधा तैयार करने और निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसी पहल शामिल है।**

अनुपालन तंत्र: आसान अनुपालन के लिए तकनीकी नवाचार की आवश्यकता होती है। सरकार ने आयकर अधिनियम के लिए वर्चुअल ई—आकलन की घोषणा की है। रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी और सेबी आदि के अधिकांश अनुपालन ऑनलाईन हो गए हैं। अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। सरकार विनिर्माण नीति लाई है जिसमें चार उद्यमों तंबाकू, रक्षा, शराब और खतरनाक रसायन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अनुमति और लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म करके केवल उद्यमी मेमोरेंडम (EM) भरने की व्यवस्था कर दी गई है।

एफडीआई नीति: केंद्र सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है, जिनमें से कुछ में ही सेक्टोरल कैप हैं। चालू खाते को परिवर्तनशील बनाया गया है; घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुगम बानाने के लिए फेमा और प्रत्यावर्तन नियमों के तहत प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

नए उभरते क्षेत्र: केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थापना की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत के लिए भविष्य में बड़ी गुंजाइश है। सरकार ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी जैसे सभी पांच स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत ध्यान केंद्रित किया है, जो भविष्य के लिए अनेक अवसर पैदा करेगा।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने भविष्य के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है और हम पूरे उत्साह के साथ इस पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के हित और प्रखर राष्ट्रवाद के साथ हमारी सरकार सभी नीतियों को लागू कर रही है और यह आश्वासन दे रही है कि सबका भविष्य सुरक्षित हाथों में हैं। ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता (आर्थिक मामले) हैं।

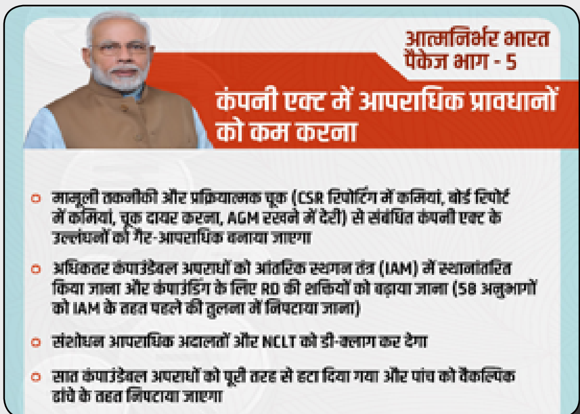

मोदी 2.0- विदेश नीति की पहल

डॉ. विजय चौथाईवाले

मई 2019 में लोकसभा चुनावों में अपनी विशाल जीत के बाद विदेश नीति पर प्रधानमंत्री मोदीजी का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहा। इसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, बहुपक्षीय मंचों पर भारत के हितों को आगे रखना और बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंद देशों को दवा या कोई अन्य सहायता प्रदान करना शामिल था।

2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क नेताओं को आमंत्रित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदीजी ने अपने दूसरे शपथ समारोह के लिए बिम्सटेक नेताओं को आमंत्रित किया। बिम्सटेक में शामिल देश बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों का समूह है और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा भी है। इसके अतिरिक्त, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाये जेनेबकोव (तत्कालीन एससीओ) और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ को भी इस अवसर के लिए आमंत्रित किया गया था।

दूसरे कार्यकाल में उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए श्रीलंका का चयन किया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने सेंट एंथोनी तीर्थ का दौरा किया और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने ईस्टर पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। इसके बाद भूटान, फ्रांस, बहरीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के कई द्विपक्षीय दौरे हुए। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने पारस्परिक हितों के विभिन्न विषयों के साथ-साथ वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बात की। उदाहरण के लिए फ्रांस में, उन्होंने कहा, "आजकल हम 21 वीं सदी में हम 'इन्फ्रा' की बात करते हैं। यह 'इन' प्लस 'फ्रा' 'भारत' और 'फ्रांस' का गठबंधन है।" उन्होंने अपने भाषणों के दौरान जलवायु परिवर्तन और सौर गठबंधन पर भी चर्चा की। भूटान में उन्होंने 720 मेगावाट के मंगदेछु पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया और रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया।

प्रधानमंत्री मोदी बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनें। बहरीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बहरीन के सर्वोच्च सम्मान,'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनैसेन्स' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण को समर्पित श्रीनाथजी मंदिर का दौरा किया और वहां से रुपे कार्ड के माध्यम से 'प्रसाद' भी खरीदा था।

सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक हाई-प्रोफाइल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी शामिल हुए, जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक पहल 'रेगिस्तान में दावोस' के रूप में पहचाना जाता है।

रूस यात्रा के दौरान व्लादिवोस्तोक में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत व्लादिमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रपति ने किया गया। दोनों नेताओं ने 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस दोनों किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में बाहरी प्रभाव के खिलाफ हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन में खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, अफगान शांति प्रक्रिया और तेल एवं गैस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की संभावनाओं सहित पारस्परिक हित के कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शामिल किया गया। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, औद्योगिक सहयोग, निवेश, कनेक्टिविटी कॉरिडोर और ऊर्जा के क्षेत्र में 25 समझौतों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' देने की घोषणा की।

उपरोक्त द्विपक्षीय यात्राओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सम्मेलनों में भी भाग लिया है। सबसे पहले, वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक गए। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक सुरक्षा स्थिति, बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग, विभिन्न मुल्कों के नागरिकों के बीच आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी जी—20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के ओसाका गए। उन्होंने यहां महिला सशक्तिकरण, डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मुद्दे, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति और आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करते हुए शिखर सम्मेलन का समृद्ध एजेंडा बनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता भी की।

मुख्य जी-20 बैठक और कई द्विपक्षीय बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी दो त्रि-पक्षीय बैठकों में शामिल हुए, जिसमें एक रूस और चीन के साथ तथा दूसरी अमेरिका और जापान के साथ थी।

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के विशेष निमंत्रण पर 45वें जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए, जैसाकि हम जानते हैं कि भारत समूह का सदस्य नहीं है। इस निमंत्रण को इन दो नेताओं के बीच 'प्रगाढ़ व्यक्तिगत संबंधों' के रूप में देखा जाता है और यह आमंत्रण भारत को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में मान्यता भी देता है। जी—7 शिखर सम्मेलन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहों (एनएसजी) के लिए भारत की सदस्यता से लेकर वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों की वकालत करता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का भारत का कदम भी यहां चर्चा का विषय था। पाकिस्तान इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर भारत को ही अपना समर्थन दिया है और दोहराया है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मुद्दा है। एक अन्य घटना में संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता को लेकर कहा कि वह इस मामले में मदद करने को तैयार है।

प्रधानमंत्री की इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा सात-दिवसीय अमेरिका यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई छोटे और बड़े समूहों को संबोधित किया, कई द्विपक्षीय बैठकें कीं, साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया।

ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक अमेरिका के सोलह ऊर्जा प्रमुख कंपनियों के शीर्ष सीईओ और उनके प्रतिनिधियों के साथ हुई। यह चर्चा भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने और आपसी निवेश के अवसरों के विस्तार पर केंद्रित थी। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन संयुक्त राष्ट्र

महासभा (यूएनजीए) में था। यहां जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, तो दर्शकों में एक अनूठा अतिथि भी मौजूद रहा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गांधी की शिक्षाओं का आह्वान किया और जलवायु परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन की अपील की। उन्होंने 2 अक्टूबर को भारत में एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी पहल के साथ ही पर्यावरण के मुद्दों पर भारत की अन्य पहलों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर एक उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विश्व कल्याण लोगों के कल्याण के साथ शुरू होता है, और स्वास्थ्य इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इस वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप, भारत स्वास्थ्य पर बहुत जोर दे रहा है।" इसके बाद आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ पर अन्य नेताओं से उनकी बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम- 'लीडरशिप मैटर्सः रेलेन्स ऑफ गांधी इन टेंपरेरी टाइम्स'- महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन द्वारा आयोजित में अपनी बात रखी। उन्होंने गांधी की शिक्षाओं, सामाजिक सुधारों और दृष्टि की सराहना की और कहा कि वे समकालीन समय में प्रासंगिक थे। एक दोस्ताना पहल के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को गांधी सोलर पार्क भी उपहार में दिया, जिसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत की छत पर सौर पैनलों के साथ स्थापित किया गया है।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को बिल्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए "ग्लोबल गेटकीपर्स अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार न्यूयॉर्क में प्रशांत द्वीप देशों के नेताओं से एक बहुपक्षीय सम्मेलन में मुलाकात की। उन्होंने अपनी विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए एट ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिजनेस फोरम में सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने सीईओ सम्मेलन में 40 से अधिक नेताओं और अमेरिकी सीईओ के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

अंतिम दिन संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु, आतंकवाद से लड़ने, वैश्विक शांति बनाए रखने और हाशिए खड़े लोगों के संदर्भ में अपनी सरकार के प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने मंच से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के अपने संदेश को दोहराया और भारत की संस्कृति के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री ने 3,000 साल पुरानी तमिल कविता को उद्धृत करते हुए कहा कि समावेशिता भारत की ताकत और परंपरा है। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का भी आह्वान किया।

पिछले एक साल में भारत ने घरेलू मोर्चे पर कई परिवर्तनकारी पहल की हैं जैसेकि अनुच्छेद 370, सीएए और वैश्विक मीडिया के कुछ हिस्सों ने कदमों के खिलाफ एक ठोस अभियान भी चलाया। इसलिए भारत के लिए इन उपायों के औचित्य और महत्व की व्याख्या करना अनिवार्य था।

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम निश्चित रूप से "हाउडी मोदी" था जिसमें 50000 से अधिक उत्साही प्रवासी भारतीय ने भाग लिया और जिनको प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प ने संबोधित किया।

बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान शिखर सम्मेलन और आरसीईपी बैठक में भाग लेने के लिए बैंकॉक गए। इस दौरान भारत ने आरसीईपी संधि से बाहर निकलने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी गए।

कोविड-19 महामारी दुनिया के इतिहास में सबसे गंभीर संकटों में से एक है। लेकिन यह स्वाभाविक है कि भारत मानवता के प्रति दया और प्रेम के साथ अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। अपने नागरिकों की रक्षा करने के साथ ही भारत ने दुनिया के 133 से अधिक देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है (446 मिलियन एचसीक्यू टैबलेट और 1.54 बिलियन पेरासिटामोल टैबलेट)।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के नेताओं के साथ वीडियो सम्मेलन की मेजबानी की। इस बैठक में सार्क (भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान) के सभी सदस्य में शामिल हुए।

भारत ने एक कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा, जो सार्क के सभी सदस्यों से स्वैच्छिक योगदान पर आधारित था और इसमें 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया।

भारत ने सभी सदस्य देशों के लिए परीक्षण किट और अन्य उपकरणों के साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम को भेजने का प्रस्ताव रखा है।

जी -20 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बाद के वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद के लिए एक नए दृष्टिकोण को पेश किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के चालीस से अधिक नेताओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने साठ से अधिक देशों के अपने समकक्षों से बात की।

पिछले एक साल में भारत ने घरेलू मोर्चे पर कई परिवर्तनकारी पहल की हैं जैसेकि अनुच्छेद 370, सीएए और वैश्विक मीडिया के कुछ हिस्सों ने कदमों के खिलाफ एक ठोस अभियान भी चलाया। इसलिए भारत के लिए इन उपायों के औचित्य और महत्व की व्याख्या करना अनिवार्य था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया है और हमारे वैश्विक मित्रों को आश्वस्त किया है कि ये उपाय भेदभावपूर्ण नहीं हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को भी सशक्त बनाते हैं और पाकिस्तान जैसे देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाते हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर, भारत इन मुद्दों पर वैश्विक शक्तियों अपने पक्ष में लाने में काफी हद तक सफल रहा है। बाद में कोविड-19 संकट के दौरान भारत ने फिर से सूचनाओं के सक्रिय आदान-प्रदान, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और यहां तक कि खाद्यान्न आदि आपूर्ति के साथ अपने नेतृत्व को दिखाया है। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राएं बंद हो गई हैं, लेकिन फिर भी यह परिस्थिति उनको वैश्विक नेता और कोविड-19 महामारी के खिलाफ अग्रणी भागीदार होने से रोकती नहीं हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में प्रशंसा हुई, जिसने भारत के गौरव को नए मुकाम पर पहुंचाया है। ■

(लेखक भाजपा विदेश विभाग के प्रमुख हैं)

युवा हो रहे सशक्त

संजीव कुमार सिन्हा

युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। कहा जाता है - युवाशक्ति-राष्ट्रशक्ति। युवा ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण होता है। युवा परिवर्तन का संवाहक होता है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, संपूर्ण क्रांति हो, श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन हो या कुछ वर्ष पूर्व संपन्न अन्ना आंदोलन, युवाओं ने इन सबमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। परिवर्तन साकार किया। युवा अन्याय-भ्रष्टाचार बरदाश्त नहीं करता। कांग्रेसनीत संप्रग शासन में जब भ्रष्टाचार बेलगाम हुआ तो युवा आक्रोश चरम पर पहुंचा। 2014 में युवाओं ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन का शंखनाद किया। केंद्र में भाजपानीत राजग सरकार बनी।

श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को लेकर प्राथमिकता से कार्य किया। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते ही उनके नेतृत्ववाली राजग सरकार ने युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए अनेक योजनाओं का श्रीगणेश किया। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा आयोग गठित करने का फैसला किया गया। युवाओं को रोजगार दिलाने और कारोबार शुरू करने में सहयोग के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग बनाया गया। पहली बार केंद्र सरकार में कौशल विकास के लिए अलग से नया विभाग बनाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। पीएमकेवीवाई का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। मोदी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं प्रारंभ कर युवाओं के हित को संवर्धित करने का उद्यम किया जा रहा है। इस दृष्टि से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा, फिट इंडिया, खेलो इंडिया आदि योजनाएं उल्लेखनीय हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 तक 73 लाख 47 हजार युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन युवाओं में से 16 लाख 61 हजार युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा दीर्घकाल के लिए 137 अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी की जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में कौशल विकास के पांच सौ केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया है। मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है कि युवा सम्मान के साथ अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। मुद्रा योजना के तहत 25 दिसंबर, 2019 तक अपना कारोबार शुरू करने के लिए 21.4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना गारंटी का ऋण दिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के तहत करीब 35.28 लाख युवाओं ने देशभर में 1.80 लाख युवा क्लब के जरिये पंजीकरण कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत करीब 3.91 मिलियन युवाओं ने 42661 एनएसएस इकाइयों में पंजीकरण कराया। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। युवा केंद्रित 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत देश के कोने-कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया जा रहा है। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेन्टिव के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत, किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर, जो ईपीएस और ईपीएफ का 12 प्रतिशत, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाना होता है, वो पहले तीन वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है। देश की युवा शक्ति को एनसीसी के प्रति जागरूक करने और इसमें सहभागिता बढ़ाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने की दिशा में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक अभूतपूर्व निर्णय करते हुए सैन्य बलों की तरह एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती की लिखित परीक्षा में उनके सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस/अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना' नामक एक युवा अनुकूल योजना का शुभारंभ किया गया। युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्त्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एनसीडीसी द्वारा यह योजना तैयार की गई है।

मोदी सरकार की नीतियां युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। एक ओर जहां एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसी संस्थाओं की स्थापना में बढ़ोतरी हो रही है वहीं युवा अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। उल्लेखनीय है कि देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 80 करोड़ युवा हैं। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं की राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रतिसाद में, युवाओं का जबरदस्त समर्थन उन्हें प्राप्त होता रहता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर कोलकाता के बेलूर मठ में कहा कि पिछले 5 वर्षों का अनुभव बताता है कि देश के युवाओं के साथ जुड़ने का अभियान सफल होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले तक एक निराशा थी कि भारत स्वच्छ हो सकता है या नहीं और क्या भारत में डिजिटल भुगतान का प्रसार इतना बढ़ सकता है, लेकिन देश के युवाओं ने कमान संभाली और बदलाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और लगन 21 वीं सदी में भारत में बड़े बदलाव का आधार बनी है। उन्होंने कहा कि युवा चुनौतियों का सामना करते हैं और उनका समाधान निकालते हैं और चुनौतियों को चुनौती देते हैं। युवाओं के इसी जज्बे के बूते सरकार देश के समक्ष खड़ी दशकों पुरानी चुनौतियों से निबटने का प्रयास कर रही है। ■

(लेखक कमल संदेश के सह संपादक हैं)

स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम..

राम प्रसाद त्रिपाठी

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये सरकार और शोधकर्ताओ ने कार्य प्रारंभ किये, ऐसी बात नहीं हैं। बजट 2020 में, भारत सरकार ने विशेष रूप से भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए खर्च जीडीपी के 1.6 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी जिसमें R&D लिये खर्च बढ़ाया गया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये सरकार का यह बहुत ही सकारात्मक प्रयास था। अन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये भी देश में समय-समय पर प्रयास हुए हैं। साल 1965 के दरम्यान जब भारत-पाकिस्तान युद्ध चल रहा था तब प्रधानमंत्री शास्त्री जी को अमेरिका से धमकी दी गई थी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया था "बंद कर दीजिए गेहूं देना"। उसके बाद कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये जो प्रयास हुआ वो हमारे सामने हैं। यूँ कह लें जब-जब भारत पर विपदा आई है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है ।

कोविड-19 महामारी के खिलाफ जब जंग की शुरुआत हुई तो उससे मुकाबला के लिये भारत के पास साधन की बहुत कमी थी। तीन महीने पहले देश में एक मात्र कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर था। पीपीई, N-95 मास्क जैसे अति आवश्यक चीजों का उत्पादन ना के बराबर था, पूर्ण रूप से इन आवश्यक चीजों को हमें विदेश से आयात करने पड़ते थे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमसे यह सवाल पूछ रहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत कैसे मुकाबला करेगा? उन्हें यह आशंका थी कि भारत बुरी तरह से कोविड के मोर्चे पर विफल होगा। अपितु भारत ने आरंभ से ही इस संकट से निपटने के लिए जैसे जुटा और कोविड-19 के तैयारियों और उपायों के संदर्भ में जो ठोस प्रयास किया वो सराहनीय था। भारत के हरेक क्षेत्र के उद्यमियों और इन्नोवेटर ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती का अति शीघ्रता से जवाब दिया है। चाहे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन और दवाओं के वैश्विक विकास में भारतीय संस्थाओं और कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान करने का विषय हो या 120 से ज्यादा देश को hydroxychloroquine दवाओं को उपलब्ध करवाना हो, भारत ने हर मोर्चे पर अपना झंडा बुलंद किया है। तीन महीनों में, पीपीई किट, N-95 मास्क की ना के बराबर उत्पादन से बढ़कर प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा का उत्पादन होना और कुछ ही दिनों में भारत का दुनिया की दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक बन जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिये वैज्ञानिक एजेंसियां, शोधकर्ताओं, निजी और सार्वजनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटरों, उद्यमियों और शोधकर्ता स्व-प्रेरित होकर यह चमत्कार कर दिखाया। उम्मीद के अनुरूप देश के बड़े बड़े शोध संस्थान सराहनीय कार्य किये। परंतु छोटे-छोटे संस्थान, उदाहरण के रूप में, ओडिशा स्थित ब्रह्मपुर आईटीआई, जिसका कोरोना शोध से कोई सीधा संपर्क नही है, वो COVID-19 के उपचार में शामिल फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ के लिए कम लागत वाला Aerosol Boxes, Face Shields, सैनिटाइजर, मास्क और इलाज में उपयोगी चिकित्सा उपकरण बनाये, यह बहुत ही संतोषप्रद है।

चाहे कोरोना के खिलाफ वैक्सीन और दवाओं के वैश्विक विकास में भारतीय संस्थाओं और कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान करने का विषय हो या 120 से ज्यादा देश को hydroxychloroquine दवाओं को उपलब्ध करवाना हो, भारत ने हर मोर्चे पर अपना झंडा बुलंद किया है।

क्या हुए नए इनोवेशन

कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जितने के लिये दुनियाभर में सबसे पहले भारत आरोग्य-सेतु ऐप लंच किया था। जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अच्छा मदद किया। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट "ELISA" को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। आईआईटी-दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत वाली कोविड -19 परीक्षण किट का विकास किया गया है। एक आईआईटी-बॉम्बे स्टार्टअप ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से दिल की धड़कन को सुन सकता है और उन्हें रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ, इस महामारी से लड़ने के जोखिम को डिजिटल स्टेथोस्कोप कम करता है। माइक्रोवेव स्टेरलाइजर "ATULYA", इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन मशीन, रैपिड डायग्नोस्टिक किट, किफायती वेंटिलेटर- IIT कानपुर के साथ NOCCA रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया हैं। किफायती वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता भी किया गया है। वर्तमान में कम से कम 6 भारतीय कंपनियां नए कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन (टीके) विकसित करने पर काम कर रही हैं।

भारतीय सेना और DRDO द्वारा "COVSACK" कियोस्क, अल्ट्रावॉयलेट लाइट-आधारित सेनिटेशन बॉक्स, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्सन टॉवर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (LASTEC) द्वारा अल्ट्रा वायलेट (UV) डिसइंफेक्सन टॉवर विकसित किया गया है। संपर्क रहित प्रक्षालक, रिमोट से नियंत्रित ट्रॉली और भारतीय नेवी द्वारा खास तरह का पीपीई किट विकसित किया गया हैं।

कई स्टार्टअप भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिये हैं। जैसे पोर्टेबल बुखार पहचान प्रणाली, पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण करके। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिये जो आर्थिक मदद का पैकेज तैयार किया है उससे उद्यमशील मानसिकता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। यूं कहे कि भारत के द्वारा तमाम इनोवेशन हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है और सुनहरा भविष्य की ओर मार्गदर्शित करता है कि हम जरूर अपने ध्येय को पाने में कामयाब होंगे। ■

(लेखक कमल संदेश के एसोसिएट एडिटर हैं)

मोदी सरकार ग्राम स्वराज की ओर

विकास आनंद

महात्मा गांधी के भारत का मतलब ग्राम स्वराज था। वे कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के सत्ता की बागडोर पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस के हाथ में आई। लेकिन पंडित नेहरू की भारत के बारे में जो दृष्टि थी, वह गांव केन्द्रित नहीं थी और न ही उनके विकास को लेकर जो विचार थे उसमें गांव इकाई था। उनकी जो विकास की धरणा थी, वह ऊपर से नीचे की ओर (Top to Bottom) था। यही दृष्टिकोण आगे भी कांग्रेस के नेतृत्व ने जारी रखा। आज हमारे देश में जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है, उसी विकास के दृष्टिकोण का परिणाम है।

जब देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आई, तब विकास के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भाजपा के विकास का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर (Bottom to Top) की ओर है। इसमें विकास की इकाई गांव और किसान हैं। नरेन्द्र मोदी के विकास के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर गांव और प्रगतिशील राष्ट्र की कल्पना है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक गरीब के वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रथम कार्यकाल में जनधन योजना की शुरुआत की। यह वित्तीय समावेशन विश्व का सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य गांव, किसान, गरीब, महिला बुजुर्ग, वंचित को हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। इस योजना के तहत खुलने वाला बैंक खाता जीरो रूपये से खुलता है। इस योजना के कारण समाज का कमजोर तबका अपने को सशक्त महसूस कर रहा है।

बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल नीति और डायरेक्ट फण्ड ट्रान्सफर जैसे उपायों को कार्यान्वित किया। इसके कार्यान्वयन से गरीब और किसान का हिस्से का अनुदान, लाभ का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के हाथ में जाने से बच गया। इस प्रयास की पूरे संसार में सराहना की गयी। इससे गरीबी को कम करने में काफी सहायता मिली और वर्तमान में चल रही महामारी में भी काफी असरदार रहा।

प्रधानमंत्री ने अपने द्वितीय कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की। बंदी के दौरान यह योजना किसानों को राहत पहुंचाने में काफी फायदेमंद साबित हो रही है। 28 मई 2020 तक 9.67 करोड़ किसान बंदी (lockdown) के दौरान लाभान्वित हुए। मार्च-अप्रैल के दौरान 19 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत निर्गत किया गया। यह राशि डायरेक्ट किसानों के खाते में ट्रान्सफर करके उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। इस योजना के तहत 6000 रुपए तीन किस्तों में प्रत्येक किसान को दिया जाता है। यह योजना अनुपूरक है। छोटे-मझोले किसानों के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ताकि खेती सुचारू रूप से चलती रहे। फसल का पैदावार बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पीछे सरकार की मंशा थी कि हमारे किसान सूदखोर के जाल में न फंसे।

कृषि क्षेत्र मोदी सरकार की हमेशा ही प्राथमिकता रही है। सरकारी योजनाओं के तहत किसानों के बीज, उर्वरक, समय पर फसल की खरीदारी पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का हमेशा ध्यान रहता है कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले। भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा को लगातार बढ़ाये जाने पर कार्य हो रहा है।

जब देश में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आई, तब विकास के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भाजपा के विकास का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर (Bottom to Top) की ओर है। इसमें विकास की इकाई गांव और किसान हैं। नरेन्द्र मोदी के विकास का दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर गांव और प्रगतिशील राष्ट्र की कल्पना है।

प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में कृषि निर्यात नीति 2018 लेकर आए थे। यह नीति 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के ध्येय को लेकर लाया गया है। मोदी जी की नई कृषि आयात नीति कृषि उत्पादों के निर्यात को दूना करने और भारत के किसानों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने का भी है।

किसानों को मजबूत बनाने के लिए कृषि निर्यात को दोगुना सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे प्रमुख उपायों पर काम कर रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, कृषि निर्यात में राज्य सरकार की अधिक भागीदारी, मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देना, विपणन और ब्रांड इंडिया का प्रचार करना आदि है। सरकार ने उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति तैयार की है।

2016 में सरकार ने ई-एनएम नामक ऑनलाइन 'राष्ट्रीय कृषि विपणन मंच' लॉन्च किया। मंच कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को सुविधा प्रदान करता है।

ई-एनएएम बेहतर कृषि उत्पादों की कीमत खोजने में मदद कर रहा है। ई-एनएएम बाजार लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि फसलों को तुरंत तौला जाता है और उसी दिन स्टॉक को उठा लिया जाता है और भुगतान की ऑनलाइन ही मंजूरी दे दी जाती है। यह मंच सभी प्रकार की बाधा को दूर करता है चाहे वह नौकरशाही हो या बिचौलियों का अवांछित हस्तक्षेप। नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को आत्मनिर्भर गांव बनाने के उद्देश्य से इस मंच का शुभारंभ किया था।

खराब फसल विकास के मामले में किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार की उपरोक्त प्रमुख पहलों के अलावा, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना है। देशभर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए, इसने प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का शुभारंभ किया। किसानों के लिए क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में पैसा दिया।

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश के हर गांव के विद्युतीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में हर गांव को बिजली का कनेक्शन प्रदान किया है। इस महान उपलब्धि के लिए, वैश्विक ऊर्जा प्रहरी 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)' ने 2018 में प्रत्येक गांव को बिजली प्रदान करने की बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के मामले में भारत को एक 'स्टार प्रदर्शक' कहा। संस्था ने हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की।

आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा विश्व की जीडीपी को कम करने के बावजूद भारत को कई विकसित राष्ट्रों की तुलना में उच्च विकास दर वाले देश में रखा है। सरकार ने संकट के इस दौर में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि इस क्षेत्र में लगी कुल आबादी का 57% पीड़ित न हो। स्पष्ट रूपरेखा और दृढ़ संकल्प के साथ सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। ■

(लेखक कमल संदेश के एसोसिएट एडिटर हैं)

कोरोना संकट के समय जन सेवा के लिए समर्पित भाजपा

21वीं सदी, भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व, आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राणशक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग, हर भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा।

– श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास

पी.पी.– 66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली – 110003
फोन: 23381428 – 011, फैक्स: 23387887 – 011
ईमेल: mail.kamalsandesh@gmail.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

सहयोग राशि: ₹ 100